चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 31 जुलाई– 06 अगस्त 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

पूरे सरकारी तंत्र को चुनौती दे रहा मोईन कुरैशी का मनी-लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट

सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह के बाद अब रंजीत सिन्हा पर चार्जशीट की तैयारी

साढ़े पांच सौ घंटे की टेलीफोन टैपिंग में सफेदपोशों की भरमार, इनमें कई भाजपाई भी

सपा नेता, पूर्व डीजीपी, फिल्मकार, ईडी के अफसर व कई अन्य छानबीन के दायरे में

फिल्म 'जानिसार' में मोईन कुरैशी ने पैसा लगाया तब हिरोइन बनी उसकी बेटी परनिया

प्रभात रंजन दीन

काला धन सफेद (मनी लॉन्ड्रिंग) करने के धंधे के सरगना मोईन कुरैशी को मदद पहुंचाने के मामले में सीबीआई अपने एक और पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है. अरबों रुपए का काला धन सफेद करने के मामले में फंसे मीट व्यापारी मोईन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के गहरे सम्बन्ध रहे हैं. इसी मामले में सीबीआई के एक और पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जांच के दायरे में सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक व यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जावीद अहमद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, प्रसिद्ध फिल्मकार मुजफ्फर अली और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के ही एक आला अधिकारी राजेश्वर सिंह भी हैं. इनके मोईन कुरैशी से जुड़े होने की पृष्ठभूमि सामने आई है. मोईन से जुड़े कांग्रेसी नेताओं की तो लंबी फेहरिस्त है. इन सबकी जांच हो रही है. पिछले दिनों ईडी के लखनऊ दफ्तर में हुई छापेमारी और सहायक निदेशक एनबी सिंह की गिरफ्तारी तो बस एक शुरुआत मानी जा रही है. इस छापेमारी के जरिए सीबीआई को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में घुसने और जरूरी दस्तावेज खंगालने का मौका मिल गया. सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि मीट व्यापारी मोईन कुरैशी की गतिविधियों के बारे में रामपुर के एसएसपी से मिली कई आधिकारिक सूचनाओं को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दबाए रखा और उसकी जांच नहीं होने दी. ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बंधित कई शिकायतें लंबित हैं, जिनकी जांच नहीं कराई गई. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक प्रमुख फोन कंपनी की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसे ईडी के आला अधिकारी ने काफी अर्से तक दबाए रखा.

मोईन कुरैशी का मामला ऐसा है कि इसकी जितनी परतें खोलते जाएं, उतनी कहानियां सामने आती जाएंगी. सीबीआई के अधिकारी ही कहते हैं कि कुरैशी के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के गोरखधंधे के तार इतने फैले हैं कि वे दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, कर्नाटक, सीबीआई, ईडी से लेकर इंटरपोल तक जाकर जुड़ते हैं. कुरैशी के पाकिस्तान और अन्तरराष्ट्रीय कनेक्शन तो हैं ही. यूपी के एनआरएचएम घोटाले से लेकर कर्नाटक के आईएएस अनुराग तिवारी की पिछले दिनों लखनऊ में हुई हत्या के सूत्र सब आपस में मिल रहे हैं. इस मामले की दो अलग-अलग स्तरों पर जांच चल रही है. सीबीआई अपने स्तर पर जांच कर रही है और ईडी अपने स्तर पर. हालांकि दोनों एजेंसियों में टकराव की स्थिति भी पैदा होती रहती है, लेकिन दोनों जांच एजेंसियों का आपसी टकराव फिलहाल हमारी खबर का हिस्सा नहीं है. इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे. मीट कारोबारी और मुद्रा-धुलाई (मनी लॉन्ड्रिंग) धंधे के सरगना मोईन कुरैशी से गहरे ताल्लुकात पाए जाने के कारण सीबीआई के पूर्व निदेशक अमर प्रताप (एपी) सिंह के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अब दूसरे पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने की तैयारी है. उनके खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. उस दरम्यान सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पॉलिसी) रहे जावीद अहमद भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि उनके समय में ही मोईन कुरैशी के धंधे की जांच का मसला सीबीआई के सामने आया था और पहले झटके में टाल दिया गया था. आप याद करते चलें कि सीबीआई में उनके एक्सटेंशन की केंद्र सरकार से मंज़ूरी मिल चुकी थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सेंट्रल विजिलेंस कमीशन) जावीद अहमद के नाम को सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के पद के लिए हरी झंडी दिखाने ही जा रहा था कि अचानक गृह मंत्रालय ने इस पर 'ऑब्जेक्शन' लगा दिया. इसके बाद उनका नाम वापस लेकर उन्हें यूपी कैडर में वापस भेज दिया गया. केंद्र ने जावीद का नाम वापस लिए जाने की वजहों का खुलासा नहीं किया था.

मोईन कुरैशी के काफी नजदीकी सम्बन्ध समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से रहे हैं. ये सम्बन्ध इतने गहरे रहे हैं कि आजम खान की बनाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर मोईन कुरैशी चार्टर हेलीकॉप्टर से रामपुर आया था. सीबीआई गलियारे में भुनभुनाहट थी कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाने में मोईन कुरैशी ने यूपी के अल्पकालिक कार्यकारी राज्यपाल अजीज कुरैशी से सिफारिश की थी.

मोईन कुरैशी

सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पॉलिसी) रहे जावीद अहमद भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि उनके समय में ही मोईन कुरैशी के धंधे की जांच का मसला सीबीआई के सामने आया था और पहले झटके में टाल दिया गया था. आप याद करते चलें कि सीबीआई में उनके एक्सटेंशन की केंद्र सरकार से मंज़ूरी मिल चुकी थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सेंट्रल विजिलेंस कमीशन) जावीद अहमद के नाम को सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के पद के लिए हरी झंडी दिखाने ही जा रहा था कि अचानक गृह मंत्रालय ने इस पर 'ऑब्जेक्शन' लगा दिया. इसके बाद उनका नाम वापस लेकर उन्हें यूपी कैडर में वापस भेज दिया गया. केंद्र ने जावीद का नाम वापस लिए जाने की वजहों का खुलासा नहीं किया था.

सीबीआई ने पिछले दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लखनऊ ऑफिस पर छापा मार कर सहायक निदेशक एनबी सिंह को गिरफ्तार किया. यह छापामारी अखबारों की सुर्खियां बनीं. खबर यही बनी कि एनआरएचएम घोटाले में एक आरोपी सुरेंद्र चौधरी से 50 लाख रुपए घूस मांगने और उसके एडवांस के बतौर चार लाख रुपए लेने के आरोप में एनबी सिंह और उनके गुर्गे सुभाष को गिरफ्तार किया गया. लेकिन इस गिरफ्तारी की जो 'अंतरकथा' है, वह खबर नहीं बनी और न अखबारों ने इसकी समीक्षा ही की. एनबी सिंह उसी महीने यानि जून में ही रिटायर होने वाले थे. चार लाख रुपए घूस लेने के लिए वे खुद एक स्थानीय होटल में जा रहे थे, जहां से उन्हें पकड़ा गया. रिटायरमेंट नजदीक होते हुए भी एनबी सिंह का केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया था और मार्च में ही उनसे एनआरएचएम घोटाले की सारी फाइलें ले ली गई थीं, फिर भी वे ईडी के ऑफिस से वाकायदा ईडी का काम कैसे देख रहे थे? एनआरएचएम का आरोपी सुरेंद्र चौधरी जब सरकारी गवाह बन चुका है, तब उसे ईडी के अधिकारी को घूस देने की जरूरत क्या थी? फिर इस प्रायोजित घूस-प्रहसन का सूत्रधार कौन है? दरअसल पूरे मामले की पटकथा कुछ और थी और दिखाई कुछ और गई. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लखनऊ दफ्तर में कुछ ही अर्सा पहले सहायक निदेशक एनबी सिंह और संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के बीच हुई कहासुनी और गाली-गलौज ईडी में सार्वजनिक चर्चा का विषय रही है. दो अधिकारियों के बीच (शेष पृष्ठ 2 पर)

4 चाइल्ड पोर्नोग्राफी : क़ानून से अधिक जागरूकता की आवश्कता

5 जानिए क्या है फेक न्यूज़

6 अमरनाथ यात्रियों पर हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही

7 झारखंड में आसान नहीं महागठबंधन की राह

सोनिया गांधी, आज़म ख़ान, रंजीत सिन्हा, जितिन प्रसाद और मोईन कुरैशी

पृष्ठ 1 का शेष

तनातनी और कलह का कारण क्या था? जांच का विषय यह है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में ईडी की कोताही, नोटबंदी के दरम्यान मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों पर ईडी की ओर से किसी कार्रवाई का न होना, मनी लॉन्ड्रिंग धंधे में मुब्तिला एक बहुराष्ट्रीय फोन कंपनी का मामला रफा-दफा कर दिया जाना, एक बड़ी मिठाई कंपनी की मुद्रा-धुलाई के धंधे में संलिप्तता हजम कर जाना, मनी लॉन्ड्रिंग धंधे के सरगना मोईन कुरैशी के खिलाफ रामपुर के एसएसपी से मिली आधिकारिक सूचनाओं को दबा दिया जाना जैसे कई मसले हैं जो एक साथ आपस में गुंथे हुए हैं. सीबीआई अधिकारी मानते हैं कि अब ईडी में घुसने का उन्हें मौका मिल गया है, अब सारे मामले की जांच होगी. सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि ईडी की फाइलें लखनऊ के एक पॉश क्लब में क्यों ले जाई जाती थीं और कुछ खास आला नौकरशाहों के सामने फाइलें क्यों खोली जाती थीं. इस क्लब के पदाधिकारी जेल में बंद एक कुख्यात माफिया सरगना के इशारे पर चुने और हटाए जाते हैं. उस माफिया सरगना के भी मोईन कुरैशी से अच्छे सम्बन्ध बताए गए हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग सरगना मोईन कुरैशी के साथ सम्बन्धों की बात तो प्रसिद्ध फिल्मकार मुजफ्फर अली भी स्वीकार नहीं करेंगे. जबकि असलियत यही है कि मुजफ्फर अली की फिल्म 'जानिसार' में मोईन कुरैशी का पैसा लगा और मोईन की बेटी परनिया कुरैशी इस फिल्म में हिरोइन बनी. 'जानिसार' फिल्म के प्रोड्यूसर में मीरा अली का नाम दिखाया गया, लेकिन सब जानते हैं कि फिल्म में मोईन कुरैशी ने पैसा लगाया था. बाप मोईन कुरैशी की तरह बेटी परनिया कुरैशी को भी कानून से खेलने में मजा आता है.

सीबीआई अफसरों को 'पटाने' वालों को पकड़ती क्यों नहीं सरकार!

देश का अजीब हाल है कि केंद्र सरकार सीबीआई जैसी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को पूंजी-सिंडिकेटों और सरगनाओं की ओर से उपकृत किए जाने पर गुस्सा भी दिखाती है और उसे रोकती भी नहीं है. सीबीआई के अधिकारियों को 'पटाने' का दो तरीका इस्तेमाल में लाया जा रहा है. या तो उन्हें मोटी रकम घूस में दी जाती है, या उन्हें सेमिनार और गोष्ठियों में बुला कर आकर्षक सम्मानिकी देकर उपकृत किया जाता है. कई पूंजी संस्थानों में तो खास तौर पर सीबीआई अधिकारियों को आलीशान वेतन पर नौकरी दी जाती है. यह ऐसा प्रलोभन है कि सीबीआई अफसर अपने रिटायरमेंट के बाद के जुगाड़ में उस पूंजी संस्थान को अनैतिक मदद पहुंचाते रहते हैं. सीबीआई के अधिकारियों को आकर्षक नौकरी का प्रलोभन देने में जिंदल प्रतिष्ठान अव्वल है. जिंदल प्रतिष्ठान कोयला घोटाले में लिप्त रहा है, लिहाजा वह सीबीआई अफसरों को अधिक उदारता से अपने यहां नौकरियां देता रहा है. सीबीआई जांचों के फेल होने की वजहों का भयानक सच भी यही है.

अब हम इसे आपको तफसील से बताते हैं. इसके लिए थोड़ा फ्लैश-बैक में चलना होगा. सीबीआई के निदेशक रहे अश्वनी कुमार सीबीआई से रिटायर होने के बाद और नगालैंड का राज्यपाल बनाए जाने के पहले नवीन जिंदल के प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहे थे. सीबीआई के कई पूर्व निदेशक और वरिष्ठ नौकरशाह जिंदल संगठन में अभी भी नौकरी कर रहे हैं. सीबीआई के निदेशकों को रिटायर होते ही जिंदल के यहां नौकरी कैसे मिल जाती है? सत्ता के गलियारे में पैठ रखने वाले वरिष्ठ नौकरशाहों को जिंदल से जुड़े प्रतिष्ठानों में प्रभावशाली ओहदों पर क्यों बिठाया जाता है? जिंदल के संस्थानों से ताकतवर नौकरशाह महिमामंडित और उपकृत क्यों होते रहते हैं? उन पर केंद्र सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? यह सवाल सामने है. कोयला घोटाले में जिंदल समूह की संलिप्तता और घोटाले की सीबीआई जांच से जुड़ी फाइलों की रहस्यमय गुमशुदगी के वाकये को देखते हुए इन सवालों को सामने रखना और भी जरूरी हो जाता है. उद्योगपति और ताकतवर कांग्रेसी नेता नवीन जिंदल की कोयला घोटाले में भूमिका जगजाहिर है. यूपीए कालीन सत्ता से उनकी नजदीकियां और उन नजदीकियों के कारण कोयला घोटाले की लीपापोती की करतूतें आपको याद ही होंगी. घोटाले में लिप्त हस्तियों की साजिशी पहुंच कितनी गहरी होती है, यह कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने के बाद पूरे देश को पता चला था.

खैर, अब आप इस खबर के जरिए देखिए कि पर्दे के पीछे पटकथाएं कैसे लिखी जाती हैं और इसे कौन लोग लिखते हैं! कोयला घोटाले में लिप्त जिंदल समूह के जरिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ नौकरशाहों को उपकृत कराने का सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है. आप तथ्यों को खंगालें, तो पाएंगे कि सत्ता के अंतरंग जिन नौकरशाहों को केंद्र सरकार उपकृत नहीं कर पाई, उन्हें जिंदल के यहां शीर्ष पदों पर नौकरी मिल गई. ऐसा भी हुआ कि नौकरी करते हुए भी कई नौकरशाहों को जिंदल के मंच से महिमामंडित किया जाता रहा. कांग्रेस के बेहद करीबी रहे अश्वनी कुमार तब सीबीआई के निदेशक थे, जब कोयला घोटाला पूरे परवान पर था. दो साल की निर्धारित सेवा अवधि में चार महीने का विस्तार अश्वनी कुमार के सत्ता साधने के हुनर का ही प्रमाण था. अश्वनी कुमार दो अगस्त 2008 को सीबीआई के निदेशक बनाए गए थे और उन्हें दो अगस्त 2010 को रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन दिया गया. सत्ता का 'लक्ष्य' पूरा होने के बाद अश्वनी कुमार नवम्बर 2010 को सीबीआई के निदेशक पद से रिटायर हुए. जैसे ही रिटायर हुए, उन्हें जिंदल समूह ने लपक लिया. जिंदल समूह ने उन्हें ओपी जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया. बाद में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अश्वनी कुमार को नगालैंड का राज्यपाल बना दिया. कोयला घोटाला, घोटाले की लीपापोती, उसमें जिंदल की भूमिका और जिंदल समूह में सीबीआई निदेशकों की नियुक्ति के सूत्र आपस में मिलते हैं कि नहीं, इसकी पड़ताल का काम तो जांच एजेंसियों का है. हमारा दायित्व तो इसे रौशनी में लाने भर का है.

अश्वनी कुमार को सीबीआई का निदेशक बनाए जाने के पीछे की अंतरकथा कम रोचक नहीं है. 17 साल से अधिक समय से सीबीआई को अपनी सेवा देते रहे खांटी ईमानदार राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी एमएल शर्मा का निदेशक बनना तय हो गया था. चयनित निदेशक को प्रधानमंत्री के साथ चाय पर आमंत्रित करने की परम्परा के तहत शर्मा को पीएमओ में बुला लिया गया था. उधर, सीबीआई कार्यालय तक इसकी सूचना पहुंच गई थी और वहां लड्डू भी बंट गए. लेकिन अचानक केंद्र सरकार ने एमएल शर्मा का नाम हटा कर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अश्वनी कुमार को सीबीआई का निदेशक बना दिया. जबकि शर्मा उनसे सीनियर थे. वे पीएमओ से अपमानित होकर लौट आए. शर्मा ने प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड और उपहार सिनेमा हादसा जैसे कई महत्वपूर्ण मामले निपटाए थे. लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें आखिरी वक्त पर सीबीआई का निदेशक बनने लायक नहीं समझा, क्योंकि शर्मा वह नहीं कर सकते थे जो केंद्र सरकार सीबीआई से कराना चाहती थी. अचानक एमएल शर्मा को हटा कर अश्वनी कुमार को सीबीआई का निदेशक कैसे और क्यों बनाया गया, यह देश के सामने आए बाद के घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया. आरुषि हत्याकांड की लीपापोती करने और सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को घेरे में लाने में अश्वनी कुमार की ही भूमिका थी. लिहाजा, कोयला घोटाले में उनका रोल क्या रहा होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है. अश्वनी कुमार ऐसे पहले सीबीआई निदेशक हैं, जो राज्यपाल बने.

सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन जिंदल समूह के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य हैं. कार्तिकेयन 1998 में सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं. इसी तरह चार जनवरी 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2001 तक सीबीआई के निदेशक रहे आरके राघवन भी जिंदल समूह की सेवा में हैं. राघवन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के वरिष्ठ सदस्य हैं. सीबीआई के जिन निदेशकों को जिंदल अपने समूह में नियुक्त नहीं कर पाया, उन्हें अपने शैक्षणिक प्रतिष्ठान से महिमामंडित कराता रहा. सीबीआई के निदेशक रहे अमर प्रताप (एपी) सिंह को रिटायर होने के महज महीने डेढ़ महीने के अंदर केंद्र सरकार ने लोक सेवा आयोग का सदस्य मनोनीत कर दिया था. उधर, जिंदल समूह इनके भी महिमामंडन में पीछे नहीं था. ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय के कई शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एपी सिंह शरीक रहे. यहां तक कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तक में अपनी घुसपैठ बना चुका जिंदल वहां भी सैकड़ों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के विशेषज्ञीय प्रशिक्षण का आयोजन कराता रहता है और उसी माध्यम से शीर्ष नौकरशाही को उपकृत करता रहता है. सीबीआई के पूर्व निदेशक पीसी शर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ. उन्हें भी रिटायरमेंट के महीने भर के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया गया. जिंदल ने पीसी शर्मा को भी अपने समूह से जोड़े रखा और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों; ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के जरिए उनका महिमामंडन करता रहा.

सत्ता से जुड़े रहे वरिष्ठ नौकरशाहों की जिंदल से नजदीकियां वाकई रेखांकित करने लायक हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य, भारत सरकार की नीति बनाने और उसे कार्यान्वित कराने की समिति के पूर्व निदेशक, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रपति तक के मीडिया एवं संचार मामलों के निदेशक रह चुके वाईएसआर मूर्ति को जिंदल ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बना दिया. मूर्ति न केवल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं बल्कि वे मैनेजमेंट बोर्ड और एकेडेमिक काउंसिल के भी सदस्य हैं. देश के ऊर्जा सचिव रहे राम विनय शाही और भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रहे अरुण कुमार पुरवार जिंदल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं. ऐसे तमाम उदाहरण हैं. जिंदल देश का अकेला ऐसा पूंजी प्रतिष्ठान है, जिसने सत्ता से जुड़े शीर्ष नौकरशाहों को अपने समूह में सेवा में रखा. खास तौर पर सीबीआई के पूर्व निदेशकों को अपनी सेवा में रखने में जिंदल का कोई सानी नहीं है. जिंदल जैसे समूहों से उपकृत होने वाले सीबीआई के पूर्व निदेशकों या वरिष्ठ अधिकारियों पर किसी की निगाह नहीं जाती. यह भी तो घूस है! इस पर केंद्र सरकार कोई अंकुश क्यों नहीं लगाती? भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी-बड़ी बोलियां बोलने वाले सत्ताधारी नेता इन सवालों पर चुप रहते हैं.

लखनऊ में बड़े आराम से खप जाता है काला धन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के धंधे के साथ-साथ नौकरशाहों के काले धन के 'एडजस्टमेंट' का भी सुविधाजनक स्थान रही है. स्मारक घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, बिजली घोटाला जैसे तमाम घोटालों के धन मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करने वाले गिरोह के जरिए यहां से बेरोकटोक विदेश जाते रहे हैं. लखनऊ से नेपाल के रास्ते काला धन बड़े आराम और बिना किसी शोरगुल के दक्षिण एशियाई देशों तक पहुंच जाता है. केंद्र सरकार का ध्यान स्विट्जरलैंड और अन्य पश्चिमी देशों पर लगा रहता है और इधर दक्षिण एशिया के छोटे-मोटे देशों में देश का पैसा धड़ल्ले से जाता रहता है. चीन के अधीन हॉन्गकॉन्ग काले धन के निवेश का बड़ा केंद्र बन गया है. यूपी के कई नेताओं का काला धन हॉन्गकॉन्ग के अलावा थाईलैंड और मलेशिया में भी खपा हुआ है. इसकी छानबीन में खुफिया एजेंसियां कोई रुचि नहीं ले रही हैं. नेताओं की आय से अधिक सम्पत्ति की जांच इन देशों में हुए निवेश की छानबीन के बगैर पूरी नहीं हो सकती. बहरहाल, भ्रष्ट नौकरशाह भी लखनऊ का इस्तेमाल काला धन खपाने में करते रहते हैं. कुछ अर्सा पहले अंगदिया कुरियर कंपनी के जरिए 50 लाख रुपए का बड़ा कन्साइनमेंट लखनऊ निवासी ध्रुव कुमार सिंह के नाम से आया था. इसकी भनक सीबीआई को पहले ही लग चुकी थी. यह पैसा क्रिकेट फिक्सिंग और सट्टे से जुड़े धंधेबाजों का था, जिसे रिश्वत के रूप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को 'ऑब्लाइज' करने के लिए भेजा गया था. इसमें ईडी के संयुक्त निदेशक जेपी सिंह व अन्य अफसरों और उनसे जुड़े सट्टेबाज विमल अग्रवाल, सोनू जालान और कुछ अन्य का नाम आया था.

सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा और मोईन कुरैशी के सम्बन्ध इतने गहरे रहे हैं कि 15 महीने में दोनों की 90 मुलाकातें आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं. यह तथ्य कोई छुपा हुआ मामला नहीं है. एपी सिंह से भी कुरैशी की ऐसी ही अंतरंग मुलाकातें सीबीआई और ईडी की छानबीन में रिकॉर्डेड हैं. एपी सिंह और कुरैशी की अंतरंगता इतनी थी कि सिंह के घर के बेसमेंट से कुरैशी का एक दफ्तर चलता था. एपी सिंह और कुरैशी के बीच ब्लैक-बेरी-मैसेज के आदान-प्रदान की कथा सार्वजनिक हो चुकी है. यह सीबीआई का दस्तावेजी तथ्य है. दूसरे निदेशक रंजीत सिन्हा के प्रसंग में सीबीआई के दस्तावेज बताते हैं कि मोईन कुरैशी अपनी कार (डीएल-12-सीसी-1138) से कई बार सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से मिलने उनके घर गया. कुरैशी की पत्नी नसरीन कुरैशी भी अपनी कार (डीएल-7-सीजी-3436) से कम से कम पांच बार सिन्हा से मिलने गईं. कुरैशी दम्पति की दोनों कारें उनकी कंपनी एएमक्यू फ्रोजेन फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम और सी-134, ग्राउंड फ्लोर, डीफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली के पते से रजिस्टर्ड हैं. ये दोनों कारें कई बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर भी जाती रही हैं, जिनमें मोईन और उसकी पत्नी सवार रही हैं. मोईन कुरैशी की बेटी परनिया कुरैशी की शादी कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के रिश्तेदार अर्जुन प्रसाद से हुई है.

बहरहाल, सीबीआई का निदेशक रहते हुए रंजीत सिन्हा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (सीबीडीटी) पर दबाव डाल कर मोईन कुरैशी के खिलाफ हो रही छानबीन का ब्यौरा जानने और छानबीन की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की थी. सीबीडीटी के पास रंजीत सिन्हा का वह पत्र भी है, जिसके जरिए उन्होंने छानबीन का ब्यौरा उपलब्ध कराने का औपचारिक दबाव डाला था. बाद में वित्त मंत्री बने अरुण जेटली ने सीबीडीटी को निर्देश देकर ऐसा करने से मना किया था. एपी सिंह हों या रंजीत सिन्हा, इस सिस्टम में मोईन कुरैशी के हाथ इतने अंदर तक धंसे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मसला बिना किसी नतीजे के अधर में ही टंगा रह जाएगा, इसी बात का अंदेशा है. अमेरिका के पेंसिलवानिया में अरबों रुपए की जालसाजी करने वाला जाफर नईम सादिक जब कोलकाता के रवींद्र सरणी इलाके में पकड़ा जाता है, तब यह रहस्य खुलता है कि वह भी मोईन कुरैशी का ही आदमी है. इंटरपोल की नोटिस पर जाफर पकड़ा जाता है. बाद में यह रहस्य खुलता है कि जाफर नईम, दुबई के विनोद करनन और सिराज अब्दुल रज्जाक का नाम इंटरपोल की वांटेड-लिस्ट और उनकी तलाशी के लिए जारी रेड-कॉर्नर नोटिस से हटाने के लिए इंटरपोल के तत्कालीन प्रमुख रोनाल्ड के नोबल से कुरैशी ने सिफारिश की थी. नोबल ने यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके मोईन कुरैशी परिवार और सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एपी सिंह से नजदीकी सम्बंध रहे हैं. लेकिन नोबल ने इंटरपोल की लिस्ट से नाम हटाने के मसले को सिरे से खारिज कर दिया था. कुरैशी की सिफारिश को नकारने वाले इंटरपोल प्रमुख रोनाल्ड के नोबल के भाई जेम्स एल. नोबल जूनियर और भारत से फरार स्वनामधन्य ललित मोदी बिजनेस-पार्टनर हैं. अमेरिका में दोनों का विशाल साझा धंधा है. यह सीबीआई के रिकॉर्ड में है. रोनाल्ड नोबल वर्ष 2000 से 2014 तक की लंबी अवधि तक इंटरपोल के महासचिव रहे हैं.

केंद्रीय खुफिया एजेंसी काले धन की आमद-रफ्त का पूरा नेटवर्क जानने की कोशिश में लगी है. इसी क्रम में मुद्रा-धुलाई और हवाला सिंडिकेट के सरगना मोईन कुरैशी से जुड़े उन तमाम लोगों के लिंक खंगाले जा रहे हैं, जिनके कभी न कभी मोईन कुरैशी से सम्बन्ध रहे हैं या मोईन कुरैशी का धन उनके धंधे में लगा है. इनमें नेता, अफसर, व्यापारी और फिल्मकारों से लेकर माफिया सरगना तक शामिल हैं. जैसा ऊपर बताया, मोईन कुरैशी के काफी नजदीकी सम्बन्ध समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से रहे हैं. ये सम्बन्ध इतने गहरे रहे हैं कि आजम खान की बनाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर मोईन कुरैशी चार्टर हेलीकॉप्टर से रामपुर आया था. सीबीआई गलियारे में भुनभुनाहट थी कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाने में मोईन कुरैशी ने यूपी के अल्पकालिक कार्यकारी राज्यपाल अजीज कुरैशी से सिफारिश की थी. स्वाभाविक है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि छानबीन से ही (शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 22
31 जुलाई- 06 अगस्त 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सोनिया गांधी, आज़म ख़ान, रंजीत सिन्हा, जितिन प्रसाद और मोईन कुरैशी

पृष्ठ 2 का शेष

होगी, क्योंकि इंटरपोल के महासचिव की तरह कोई यह स्वीकार तो करेगा नहीं कि मोईन कुरैशी से उनके दोस्ताना सम्बन्ध रहे हैं. यह भारतवर्ष के लोगों की खासियत है. इसी प्रसंग में याद करते चलें कि उत्तर प्रदेश के दो निवर्तमान राज्यपालों क्रमशः टीवी राजेस्वर और बीएल जोशी ने मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था. जोशी के जाने के बाद और राम नाईक के राज्यपाल बन कर आने के बीच में महज एक महीने के लिए यूपी के कार्यकारी राज्यपाल बनाए गए अजीज कुरैशी ने आनन-फानन मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की मान्यता के विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए. कुरैशी 17 जून 2014 को यूपी आए, 17 जुलाई 2014 को जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की मान्यता दी और 21 जुलाई 2014 को वापस देहरादून चले गए.

मनी लॉन्ड्रिंग सरगना मोईन कुरैशी के साथ सम्बन्धों की बात तो प्रसिद्ध फिल्मकार मुजफ्फर अली भी स्वीकार नहीं करेंगे. जबकि असलियत यही है कि मुजफ्फर अली की फिल्म 'जानिसार' में मोईन कुरैशी का पैसा लगा और मोईन की बेटी परनिया कुरैशी इस फिल्म में हिरोइन बनी. 'जानिसार' फिल्म के प्रोड्यूसर में मीरा अली का नाम दिखाया गया, लेकिन सब जानते हैं कि फिल्म में मोईन कुरैशी ने पैसा लगाया था. बाप मोईन कुरैशी की तरह बेटी परनिया कुरैशी को भी कानून से खेलने में मजा आता है. अमेजन इंडिया फैशन वीक-2016 के दरम्यान मीडिया के लिए निजी तौर पर कॉकटेल पार्टी (बेशकीमती शराब पीने-पिलाने की पार्टी) देकर परनिया कुरैशी चर्चा में रही. मीडिया वालों ने पहले तो खूब दारू छकी और बाद में नुक्ताचीनी की कि परनिया कुरैशी फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य नहीं हैं, तो फिर

कॉकटेल पार्टी कैसे दी. मजा यह है कि इस कॉकटेल पार्टी का नाम परनिया ने 'रामपुर का कोला' रखा था. हम आप सोचेंगे वही आजम खान का रामपुर... लेकिन वो कहेंगे, नहीं, मोईन कुरैशी का रामपुर. इसके पहले भी परनिया कुरैशी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्मगलिंग के आरोप में पकड़ी और करीब 40 लाख रुपए का जुर्माना लेकर छोड़ी जा चुकी हैं. मोईन के अंतरंगों और उपकृतों की लिस्ट में ऐसे और कई नाम हैं. कांग्रेसियों के नाम तो भरे पड़े हैं. सोनिया गांधी का नाम इनमें शीर्ष पर है. पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद तो मोईन कुरैशी के रिश्तेदार ही हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल, कमलनाथ, आरपीएन सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे कई नेता इस सूची में शुमार हैं. ये उन नेताओं के नाम हैं जो मोईन कुरैशी के घर पर नियमित उठने-बैठने वाले हैं. सोनिया के घर पर मोईन परिवार नियमित तौर पर उठता-बैठता रहा है. ■

साढ़े पांच सौ घंटे की रिकॉर्डिंग उजागर हो तो तूफान आ जाएगा

इनकम टैक्स विभाग की खुफिया शाखा ने मोईन कुरैशी की विभिन्न हस्तियों से होने वाली टेलीफोनिक बातचीत टेप की. उसके बारे में आईटी इंटेलिजेंस के सूत्र थोड़ी झलक दिखाते हैं, तो लगता है कि कुरैशी का मनी लॉन्ड्रिंग का साम्राज्य पूरे सरकारी सिस्टम को समानान्तर चुनौती दे रहा है. तकरीबन साढ़े पांच सौ घंटे की रिकॉर्डिंग है. आईटी के अधिकारी ही कहते हैं कि इसे देश सुन ले, तो भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम की असलियत प्रामाणिक रूप से समझ में आ जाए.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्कम टैक्स की इंटेलिजेंस शाखा पहले से खुफिया जांच कर रही थी. आईटी इंटेलिजेंस ने मोईन कुरैशी की विभिन्न लोगों से टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को तकरीबन साढ़े पांच सौ घंटे सुना था और उसे रिकॉर्ड किया था. इसमें केंद्र सरकार के कई मंत्री, यूपी समेत कई राज्य सरकारों के मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सीबीआई के अधिकारी, बड़े कॉरपोरेट घरानों के अलमबरदार, कई फिल्मी हस्तियां समेत ढेर सारे महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं. आप हैरत न करें, इनमें भाजपा के भी कई नेताओं के नाम हैं. एक वरिष्ठ भाजपा नेता की बेटी का नाम भी है और उस भाजपा नेता का भी नाम है, जो मोईन कुरैशी के भाई को रामपुर से टिकट दिलाने की कोशिश कर रहा था. यह अपने आप में बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन होगा, अगर उसे सार्वजनिक कर दिया जाए.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोईन कुरैशी के जाल में फंसने और सीबीआई के दो-दो निदेशकों के उसके साथ सम्बन्ध उजागर होने के बाद देशभर में चर्चा हुई, निंदा प्रस्ताव जारी हुए और अपने-अपने तरीके से नेताओं ने इसे खूब भुनाया. लेकिन किसी भी नेता ने सार्वजनिक तौर पर यह चर्चा नहीं की कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने केंद्र सरकार को पहले ही क्या सूचना दे दी थी. ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने भारतीय खुफिया एजेंसी को आगाह करते हुए यह बता दिया था कि दुबई के एक बैंक अकाउंट से 30 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं. अकाउंटधारी भारतीय है और यह पैसा सीबीआई के निदेशक को घूस देने के लिए भेजा गया है. केंद्र सरकार न तो उस अकाउंट को जब्त कर पाई और न अकाउंटधारी को ही पकड़ा जा सका.

सीबीआई के निदेशक के पद पर रहते हुए एपी सिंह और रंजीत सिन्हा, दोनों मोईन कुरैशी की फर्म 'एसएम प्रोडक्शन्स' को सीबीआई के विभागीय कार्यक्रमों के आयोजन का भी ठेका देते रहे हैं. इसे मोईन कुरैशी की दूसरी बेटी सिल्विया कुरैशी संचालित करती थी. सीबीआई के निदेशकों के साथ मोईन कुरैशी के इंटरपोल के प्रमुख रोनाल्ड के नोबल के करीबी सम्बन्धों के बारे में आपने ऊपर जाना. साथ-साथ यह भी जानते चलें कि सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों के अधिकारी फ्रांस के आर्किटेक्ट जीन लुईस डेनॉयट को मोईन कुरैशी के हवाला धंधे के सिंडिकेट से सक्रिय तौर पर जुड़ा हुआ सदस्य बताते हैं. ...केवल बताते हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं. ■

जिनसे आतंकी लेते हैं फंड, उन्हीं से नेता लेते हैं धन

देखिए, दृश्य एकदम साफ है. मोईन कुरैशी का मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का धंधा बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन यह कोई नया थोड़े ही है! इसके पहले भी हवाला का धंधा होता रहा है. इसके पहले भी काला धन सफेद होता रहा है. उन घोटालों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. सारे मामले लीप-पोत कर बराबर कर दिए गए. कम राजनीतिक औकात वाले कुछ नेता और दलाल जेल गए, फिर सब कुछ सामान्य हो गया. नेता और नौकरशाह जिन मामलों में इन्वॉल्व रहेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आतंकी संगठन जिन स्रोतों से पैसे प्राप्त करते हैं, उन्हीं स्रोतों से विभिन्न राजनीतिक दल भी धन लेते हैं. लेकिन इससे नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता.

अब आप ही बताइए कि नब्बे के दशक के उस हवाला घोटाले का क्या हुआ, जो बड़े धमाके से उजागर हुआ था? देश से बाहर विदेशों में अरबों रुपए का काला धन भेजने की हवाला-कला से देश के आम लोगों का परिचय ही जैन हवाला डायरी केस से हुआ था. सीबीआई ने वर्ष 1991 में कई हवाला सरगनाओं के ठिकानों पर छापे मारे थे. इसी छापेमारी के क्रम में एसके जैन की डायरी बरामद हुई थी और वर्ष 1996 में यह देश-दुनिया के सामने उजागर हो गया था. थोड़ा झांकते चलते हैं, जैन हवाला मामले की फाइलों में...

25 मार्च 1991 को दिल्ली पुलिस ने जमायत-ए-इस्लामी के दिल्ली मुख्यालय से कश्मीरी युवक अशफाक हुसैन लोन को गिरफ्तार किया था. अशफाक से मिले सुराग पर जामा मस्जिद इलाके से जेएनयू के छात्र शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ा गया. अशफाक और शहाबुद्दीन दोनों हवाला के जरिए पैसा हासिल कर उसे आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तक पहुंचाते थे. यह पैसा लंदन से डॉ. अय्यूब ठाकुर और दुबई से तारिक भाई भेजा करता था. यह संवेदनशील सूचना मिलने पर मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया. सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद 3 मई 1991 को विभिन्न हवाला कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की. इसमें भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र कुमार जैन के महरौली स्थित फार्म हाउस और उसके भाई जेके जैन के दफ्तर पर भी छापा पड़ा. छापे में 58 लाख रुपए से ज्यादा नकद, 10.5 लाख के इंदिरा विकास पत्र और चार किलो सोना बरामद किया गया. इसके अलावा 593 अमेरिकी डॉलर, 300 पाउंड, 27 हजार डेनमार्क की मुद्रा, 50 हजार हॉन्गकॉन्ग की मुद्रा, 300 फ्रैंक सहित 50 अलग-अलग देशों की काफी मुद्राएं बरामद की गईं. सबसे महत्व-पूर्ण बरामदगी थी दो संदेहास्पद डायरियां.

एसके जैन की डायरी में तत्कालीन केंद्र सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री सहित केंद्र के कुल सात मंत्रियों, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, दो राज्यपालों और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल था. इस लिस्ट में 55 नेता, 15 बड़े नौकरशाह और एसके जैन के 22 सहयोगियों को मिलाकर कुल 92 नामों की पहचान हुई थी. अन्य 23 लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी. डायरी में लिखे नामों के आगे राशि-संख्या लिखी थी. इसमें लालकृष्ण आडवाणी पर 60 लाख रुपए, बलराम जाखड़ पर 83 लाख, विद्याचरण शुक्ल पर 80 लाख, कमलनाथ पर 22 लाख, माधवराव सिंधिया पर 1 करोड़, राजीव गांधी पर 2 करोड़, शरद यादव पर 5 लाख, प्रणब मुखर्जी पर 10 लाख, एआर अंतुले पर 10 लाख, चिमन भाई पटेल पर 2 करोड़, एनडी तिवारी पर 25 लाख, राजेश पायलट पर 10 लाख और मदन लाल खुराना पर 3 लाख रुपए लिखे थे. सीबीआई ने चार साल बाद मार्च 1995 में एसके जैन को गिरफ्तार किया. जैन ने अपने लिखित बयान में कहा कि उसने वर्ष 1991 में मार्च से मई महीने के बीच राजीव गांधी को चार करोड़ रुपए पहुंचाए. इसमें से दो करोड़ रुपए राजीव गांधी के निजी सचिव जॉर्ज के लिए थे. इसके अलावा दो करोड़ रुपए सीताराम केसरी को भी दिए गए, जो उस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे. इसी तरह उसने नरसिम्हा राव और चंद्रास्वामी को भी साढ़े तीन करोड़ रुपए देने की बात कबूली थी. एसके जैन ने यह भी स्वीकार किया था कि इटली के हथियार डीलर क्वात्रोची के जरिए वह हवाला कारोबारी आमिर भाई के सम्पर्क में आया था. आप आश्चर्य करेंगे कि गिरफ्तारी के 20 दिन बाद ही एसके जैन को जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

गिरोहबाजों के तार कितने लंबे रहे हैं, इसका अहसास आपको इस बात से ही लग जाएगा कि जिस अशफाक और शहाबुद्दीन की निशानदेही पर इतना बड़ा मामला खुला, उन दोनों का नाम चार्जशीट से गायब कर दिया गया. एसके जैन की भी गिरफ्तारी मामला उजागर होने के चार साल बाद की गई थी. सीबीआई ने 16 जनवरी 1996 को आधी-अधूरी चार्जशीट दाखिल की. 8 अप्रैल 1997 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज मोहम्मद शमीम ने लालकृष्ण आडवाणी और वीसी शुक्ला को बाइज्जत बरी कर दिया, धीरे-धीरे सारे नेता बेदाग निकल गए. कोर्ट ने भी जैन की डायरी को 'बुक ऑफ़ अकाउंट' में लेने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने इसे सबूत नहीं माना. सीबीआई ने भी सब कुछ ढीला छोड़ दिया. विडंबना यह है कि जैन हवाला डायरी मामले से यह खुलासा हुआ था कि विदेश से जिस फंड के द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा भेजा गया था, उसी चैनल के जरिए आंतकी संगठनों को भी फंड भेजा गया था. इस घोटाले में 115 राजनेता और कारोबारी के साथ-साथ कई नौकरशाह शामिल थे. लेकिन सब सबूत के अभाव में बचकर निकल गए.

लिहाजा, हमें यह समझ लेना जरूरी है कि इस बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं होने वाला. हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग के बूते ही राजनीतिक दलों का धंधा चलता है. चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कोई अन्य. राजनीतिक दलों पर हवाला के पैसे के लेन-देन के आरोप लगते रहे हैं और वे अपने सफेद वं से धूल झाड़ते रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब-करीब सारे राजनीतिक दल कमोबेश इन्वॉल्व हैं, लेकिन बताइए कौन नेता पकड़ा जाता है? आपके सामने बस एक उदाहरण है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का. आरोप है कि मधु कोड़ा ने हजारों करोड़ रुपए बटोरे और उसे हवाला के जरिए विदेश भेजा. लेकिन आप यह भी जानते चलें कि मधु कोड़ा बड़े नेताओं का एक कारगर मोहरा थे, जिसे सामने रख कर काला धन बाहर भेजा गया और मोहरा जेल चला गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

चाइल्ड पोर्नोग्राफी

क़ानून से अधिक जागरूकता की आवश्यकता

शफ़ीक़ आलम
feedback@chauthiduniya.com

यदि आज कोई ये कहे कि उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. आज भारत में बैठकर कोई छात्र दुनिया में किसी भी देश के विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल कर सकता है या वर्चुअली वहां किसी भी क्लास रूम में दाखिल हो सकता है. मिसाल के तौर पर येल यूनिवर्सिटी का लेक्चर दुनिया के किसी छात्र के लिए महज़ एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध है. आज भारत का कोई मरीज़ किसी अमेरिकी डॉक्टर से सलाह ले सकता है. इन्टरनेट ने आम जीवन में बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी हैं. लेकिन जैसे-जैसे इसका फैलाव बढ़ा है, वैसे-वैसे इसका वीभत्स रूप भी हमारे सामने खड़ा हो गया है. इसी का एक वीभत्स रूप है पोर्नोग्राफी. इन्टरनेट पर पोर्नोग्राफी का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि सरकारों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. लेकिन पोर्नोग्राफी का भी वीभत्स रूप है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो दुनिया के लिए चुनौती बन गई है. बदकिस्मती से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्यों इस पर रोक लगाने में दिक्कत आ रही है? दुनिया के देश जहां इस पर सख्त कानून हैं, वहां इससे कैसे निपटा जा रहा है? भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून क्या कहता है?

पिछले दो दशकों के दौरान इन्टरनेट की पहुंच में क्रान्तिकारी विस्तार देखने को मिला है. इन्टरनेट मेट्रो और बड़े शहरों की चहारदीवारियों से निकल कर गांव-गांव तक पहुंच गया है. इसके विस्तार में स्मार्ट फ़ोन ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. अब एक निम्न आय वाला परिवार भी ऐसे मोबाइल फ़ोन खरीद सकता है, जो इन्टरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट की सुविधा से लैस हैं. अब ये फ़ोन निम्न आय वर्ग के बच्चों के हाथों में भी आ गए हैं. कुछ जानकारी के अभाव में और कुछ उत्सुकतावश बच्चे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के विजिटर बन जाते हैं. लेकिन यहां मसला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे वयस्कों के लिए उपलब्ध सामग्री देख रहे हैं, बल्कि यह उससे कई गुना भयानक है. इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिन देशों में पोर्नोग्राफी को सामाजिक मान्यता मिली हुई है, वहां भी इसे प्रतिबंधित करने के आदेश दिए जा रहे हैं. बहरहाल जहां तक बच्चों के स्वभाव में बदलाव की बात है, तो कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन आने के बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई थी. देश के महानगरों में ऐसे एमएमएस वायरल हो रहे थे, जिनमें कम उम्र के बच्चे शामिल थे. लेकिन आज इन्टरनेट ने बच्चों को भी बाज़ार की सामग्री बना दिया है.

पिछले वर्ष अगस्त महीने में भारत सरकार ने 857 पोर्न वेबसाइट की सूची बनाकर नैतिकता और शालीनता की बुनियाद पर इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था. लेकिन भारी विरोध के बाद सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा था. 14 अगस्त को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. इसमें केंद्र ने कहा कि वो एक अमेरिकी निजी संस्था की मदद ले रहा है, जो 99 देशों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बंधित सामग्री के अपलोडिंग पर मुफ्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है. इस स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अब तक 3,522 ऐसे वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा चुका है. स्कूलों में भी इन्टरनेट जैसर लगाने पर विचार हो रहा है. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अग्रह पर इन्टरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (आईएमएआई) द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन चार करोड़ पोर्न वेबसाइट्स हैं. अब इन चार करोड़ वेबसाइट्स में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट की संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. ज़ाहिर है कुछ हज़ार वेबसाइट्स पर प्रतिबन्ध ऊंट के मुंह में जीरा के समान है. इस बात को सरकार, आईएमएआई और इन्टरनेट के जानकार भी मानते हैं कि पोर्न वेबसाइट्स पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इन्हें फ़िल्टर ज़रूर किया जा सकता है. इन वेबसाइट्स के अधिकतर सर्वर भारत से बाहर हैं, इसीलिए आईएसपी ने भी पहले ही चाइल्ड पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने में अपनी असमर्थता ज़ाहिर कर दी थी.

पिछले दिनों हैदराबाद में एक अमेरिकी नागरिक जेम्स कर्क जोन्स की गिरफ्तारी हुई. उसके पास से चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी करीब 30 हजार फाइलें बरामद हुई थीं. इस घटना पर हैदराबाद में बहुत हंगामा मचा, लेकिन हालिया सरकारी आंकड़े ज़ाहिर करते हैं कि चाइल्ड पोर्न के मामले में केवल महानगर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर भी इसमें शामिल हो गए हैं. इंटरनेट पर बाल यौन शोषण की सामग्री तलाशने और शेयर करने के मामले में देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है. इस मामले में सबसे आगे अमृतसर रहा, उसके बाद लखनऊ, अलापुझा, त्रिशूर जैसे शहर शामिल रहे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अमृतसर में 1 जुलाई 2016 से 15 जनवरी 2017 के बीच चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी 4 लाख 30 हजार से ज्यादा फाइलें शेयर की गईं. अब इस से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि चाइल्ड पोर्न ने कितना भयानक रूप ले लिया है. छोटे शहरों और गांवों तक इसके पहुंचने का एक कारण यह भी है कि अब ये सामग्रियां हिंदी और दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं. किसी अनजान यूजर के लिए गूगल या किसी और सर्विस प्रोवाइडर के सहारे हिंदी पोर्न वेबसाइट्स तलाश लेना कोई बड़ी बात नहीं है.

भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ प्रावधान मौजूद हैं. हालांकि केवल क़ानून बना देने से इस अभिशाप को रोका नहीं जा सकता और न ही कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करके. क्योंकि यदि ऐसा होता तो सऊदी अरब जहां पोर्न वेबसाइट देखने के खिलाफ सख्त क़ानून हैं, वहां पोर्नोग्राफी नहीं देखी जाती. पाकिस्तान, जो चार लाख से अधिक वेबसाइट्स पर पाबन्दी की बात करता है, वहां भी उर्दू और दूसरी स्थानीय भाषाओं में पोर्न सामग्री मौजूद नहीं रहती. बहरहाल भारत में इस बात की आवश्यकता है कि मौजूदा कानूनों को लागू करने में सख्ती बरती जाए और उनमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े जाएं. सरकार केवल यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि अधिकतर पोर्न साइट्स के आईपी विदेशी हैं, इसलिए उनपर कार्रवाई नहीं की जा सकती और उन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता है. अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार दूसरे देशों की सरकारों से इस सम्बन्ध में समझौता नहीं कर सकती? इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो बाल यौन उत्पीड़न से सम्बंधित सामग्री इन्टरनेट पर मौजूद हैं, उनकी जांच कर दोषियों को सजा दिलवाने का प्रावधान क्यों नहीं है? साथ ही सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन्स क्यों जारी नहीं की जाती, जिसमें उनकी भी ज़िम्मेदारी तय की जाए. पूरे विश्व में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, ऐसे में दूसरी सरकारों से भी सहयोग मिल सकता है. हालांकि सरकार अब ऐसे अपराधों के लिए इंटरपोल की मदद लेने की बात कर रही है, लेकिन इसमें भी अभी काफी दूरी तय करनी है. विकसित देशों से प्रत्यर्पण एक टेढ़ी खीर है. कानून के अलावा भारत में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेज में भी कुछ फ़िल्टरिंग के एप्स लगाकर इसे बहुत हद तक काबू किया जा सकता है.

बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी दुनिया के सभी देशों के लिए एक अभिशाप है. दुनिया भर में कई ऐसे शोध हुए हैं, जिनमें बच्चों में विचलित यौन व्यवहार को इंगित किया गया है. एक शोध के मुताबिक 12 से 18 वर्ष की आयु तक के 90 प्रतिशत लड़के और 60 प्रतिशत लड़कियां पोर्नोग्राफी की ज़द में आ सकती हैं. जब स्थिति इतनी भयानक है तो केवल कानून बना देने और सरकार पर सारी ज़िम्मेदारी डाल देने से काम नहीं चलेगा. इसकी रोकथाम के लिए परिवार और समाज को भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी. ■

पिछले दो दशकों के दौरान इन्टरनेट की पहुंच में क्रान्तिकारी विस्तार देखने को मिला है. इन्टरनेट मेट्रो और बड़े शहरों की चहारदीवारियों से निकल कर गांव-गांव तक पहुंच गया है. इसके विस्तार में स्मार्ट फ़ोन ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. अब एक निम्न आय वाला परिवार भी ऐसे मोबाइल फ़ोन खरीद सकता है, जो इन्टरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट की सुविधा से लैस हैं. अब ये फ़ोन निम्न आय वर्ग के बच्चों के हाथों में भी आ गए हैं. कुछ जानकारी के अभाव में और कुछ उत्सुकतावश बच्चे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के विजिटर बन जाते हैं. लेकिन यहां मसला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे वयस्कों के लिए उपलब्ध सामग्री देख रहे हैं, बल्कि यह उससे कई गुना भयानक है. इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिन देशों में पोर्नोग्राफी को सामाजिक मान्यता मिली हुई है, वहां भी इसे प्रतिबंधित करने के आदेश दिए जा रहे हैं.

कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन दोफाड़

सूरत में लड़े, दिल्ली में गवां बैठे

सूरत से शुरू हुआ कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन जब तक दिल्ली पहुंचता, उनका तेवर ढीला पड़ चुका था. जीएसटी पर विरोध के सुर बदलते ही आंदोलन भी दोफाड़ हो गया. इस हालात में कपड़ा व्यापारियों के लिए हड़ताल जारी रखना एक आत्मघाती कदम होता.

चंदन राय

सरकार से वार्ता के लिए सूरत से दिल्ली पहुंचे कपड़ा व्यापारियों में मतैक्य नहीं था. आठ व्यापारी नेताओं में से 4 तो अरुण जेटली से बिना मिले ही वापस लौट आए, जो बचे उनमें भी इतना साहस नहीं बचा था कि वे सरकार से जीएसटी रेट (वस्तु एवं सेवा कर) पर दृढ़ता से अपनी बात रख सकें. इसी बीच जब पुलिस व्यापारियों को उठा-उठाकर जेल भेजने लगी, तब व्यापारियों ने सरेंडर करना ही उचित समझा. खबर है कि पुलिस ने करीब 1000 लोगों को दंगा भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया है. सरकार के कड़े रुख से व्यापारियों ने यह भांप लिया था कि जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसलिए जीएसटी के सरलीकरण के आश्वासन पर ही उन्होंने 21 दिनों से जारी हड़ताल खत्म कर दी. कह सकते हैं कि व्यापारियों की आपसी फूट, विपक्षी दलों का सहयोग नहीं मिलना और पुलिस द्वारा दंगों का मामला दर्ज किए जाने के दबाव से कपड़ा व्यापारियों की रही-सही एकता बिखर गई.

हालांकि, कपड़ा व्यापारियों को अब भी सरकार से उम्मीद है. उन्हें 5 अगस्त को होनेवाली जीएसटी की मीटिंग का इंतजार है, जिसमें उनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है. वहीं व्यापारियों के एक धड़े का कहना है कि हमारे नेता सबको साथ लेकर नहीं चल सके. अगर सरकार से बातचीत के मुद्दे पहले से ही तय होते, तब परिणाम कुछ और होता. अब तो मीटिंग छोड़कर चले गए नेताओं पर भी सवाल उठने लगे हैं. कुछ व्यापारियों का कहना है कि अगर दुकान खोलनी ही थी, तो एक बार दुकानदारों से वोटिंग करवाकर उनका पक्ष भी जान लिया गया होता. इसके साथ ही व्यापारियों ने संघर्ष समिति भंग करने का फैसला किया है. अब नई कमिटी आगे की रणनीति तय करेगी. आइए जानते हैं कि आखिर सूरत में ऐसे हालात क्यों बने और सरकार कपड़ा व्यापारियों की मांगों को क्यों अनसुना कर रही है?

त्योहारों के सीजन में गुलजार रहने वाले सूरत बाजार में आज सन्नाटा पसरा है. रोजगार छिन जाने से हर रोज करीब 16 हजार कारीगर शहर छोड़कर जा रहे हैं. अनुमान के मुताबिक

जीएसटी लागू होने के बाद से दो लाख मजदूर शहर से पलायन कर चुके हैं. सूरत के कपड़ा उद्योग का शटर 21 दिनों तक गिरा रहा, जिसके कारण 27 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है. वहीं अनुमान है कि इस दौरान देश भर में सिर्फ कपड़ा उद्योग को 40 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है. कारोबारियों का कहना है कि अब अगर मार्केट खुल भी गया, तो त्योहार का सीजन हाथ से निकल जाएगा. दशहरा और दिवाली के लिए महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है.

सूरत से कारीगरों के पलायन से भी स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती चली गई. अगर कुछ दिनों में सूती मिलों के थमे पहिए चलने भी लगें, तो कारीगरों के नहीं होने से कारोबार ठप हो जाएगा. सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े विभिन्न कार्यों जैसे एम्ब्रॉयडरी, हैण्डलूम, डाइंग और पैकेजिंग से करीब 9 लाख कारीगर जुड़े हैं. हालत यह है कि पावरलूम मशीनें सूत नहीं मिलने के कारण बंद पड़ी हैं. पावरलूम मालिकों का कहना है कि जीएसटी नंबर नहीं होने से वे न तो कच्चा माल खरीद पा रहे हैं और न ही तैयार माल बेच पा रहे हैं. जीएसटी की अनिश्चितताओं के कारण जून से ही कपड़ों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जो अब बिल्कुल थम गई है. वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि बड़े कारोबारियों पर जीएसटी और हड़ताल का खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उद्योग से जुड़े छोटे व्यापारी और मजदूर सड़क पर आ गए हैं.

प्रधानमंत्री के गृहप्रदेश गुजरात में हजारों कपड़ा व्यापारी व कारीगर सड़क पर विरोध-प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार इस आंदोलन से बेखबर होने का स्वांग करती रही. 17 जुलाई को वित्त मंत्री अरुण जेटली के आश्वासन के बाद कपड़ा व्यापारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वे बारीकी से स्थितियों पर नजर रखे हैं. जेटली ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में टेक्सटाइल्स पर लगे जीएसटी रेट पर विचार किया जाएगा. लेकिन इसके बाद राज्य सभा में दिए एक बयान में उन्होंने स्पष्ट कहा कि कपड़े पर टैक्स नहीं घटाया जाएगा. फैब्रिक पर जीएसटी रेट जीरो प्रतिशत करने से घरेलू उद्योगों को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा. इससे यहां बने कपड़ों की अपेक्षा आयातित कपड़े सस्ते हो जाएंगे. केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड(सीबीईसी) की अध्यक्ष बनाजा सरना ने भी कहा कि किसी भी वस्तु या सेवा पर लगे जीएसटी रेट में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार को ऐसा नहीं लगे कि वह अनुचित है. उन्होंने यह भी कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र पहली बार टैक्स के दायरे में आया है, इसलिए ज्यादा विरोध हो रहा है. हालांकि सरकार का तर्क है कि 2003-04 में भी कपड़ा सेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी लगा था. वहीं इंडस्ट्री का दावा है कि टैक्स से फैब्रिक 10-12 प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे, जिसका असर कपड़ों के निर्यात पर पड़ेगा. सरकार के रुख से कपड़ा व्यापारी भी कशमकश में हैं. वे वित्त मंत्री अरुण जेटली का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं हैं. कपड़ा व्यापारियों को प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वे उनकी मांगों को जरूर सुनेंगे और उन्हें डूबने से बचा लेंगे.

सूरत की टेक्सटाइल संघर्ष समिति के संयोजक ताराचंद कासट कहते हैं कि हम जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं, पर इसके लागू करने के तौर तरीकों से असंतुष्ट हैं. कपड़ा व्यापारी अभी तक सिर्फ धागे या कपड़े पर जीएसटी को 1 अप्रैल तक टालने की मांग कर रहे थे. इसके अलावा साल में 37 रिटर्न भरने के नियम को भी वे पेचीदा बता रहे हैं. वहीं टेक्सटाइल संघर्ष समिति के एक धड़े का कहना है कि अगर सरकार ने कपड़े पर लगा जीएसटी वापस नहीं लिया, तब हम आंदोलन और तेज करेंगे. नाराज व्यापारियों का कहना है कि सरकार जीएसटी के सरलीकरण का मात्र आश्वासन दे रही है, जिसे हम किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे.

नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने यूपीए सरकार की जीएसटी नीति का विरोध किया था. प्रधानमंत्री बनते ही अब वे जीएसटी के मुखर प्रवक्ता बन गए हैं. जीएसटी लागू करने की केंद्र सरकार की बेचैनी विपक्षियों की समझ से परे है. तमाम विपक्ष अब यह जानना चाहता है कि तब उन्होंने जीएसटी के विरोध में क्या तर्क दिए थे? इसके साथ ही, लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अब गुजरात सरकार की जीएसटी पर क्या राय है? ■

feedback@chauthiduniya.com

जीएसटी पर अधूरा होमवर्क

सरकार आज भी व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी रेट की समीक्षा कर रही है. जीएसटी के बाद सिगरेट सस्ती होने पर जब सवाल उठने लगे, तो सरकार ने उस पर अलग से 5 प्रतिशत सेस लगा दिया. व्यापारी संगठन जीएसटी लागू करने से पहले सलाह-मशविरा नहीं किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं ई-कॉमर्स कंपनियां भी कह रही हैं कि इससे उनका काम मुश्किल हो जाएगा. यही मांग कई अन्य क्षेत्रों से भी उठ रही है. ऐसे में क्या ये बेहतर नहीं होता कि जीएसटी की दरें तय किए जाने से पूर्व सरकार अपना होमवर्क कर लेती. ■

कपड़ा पर जीएसटी की दरें

- कृत्रिम धागा (पॉलिस्टर)-18 प्रतिशत
- प्राकृतिक धागा (कॉटन, सिल्क, वूल)-5 प्रतिशत
- रेडीमेड कपड़ा (1000 रुपए तक)-5 प्रतिशत
- रेडीमेड कपड़ा (1000 रुपए से ज्यादा)-12 प्रतिशत

फेक न्यूज़ से सावधान

जानिए क्या है फेक न्यूज़

फेक न्यूज़ एक व्यापक श्रेणी है. इसकी कई उपशाखाएं हैं. एक शाखा है, फेक तस्वीरों की. कई नेताओं के ट्वीट से लेकर सरकार की रिपोर्ट तक में फेक तस्वीरें पहुंच जाती हैं और वहां से आप लोगों के बीच. हाल ही में भारत के गृहमंत्रालय की 2016-17 की सालाना रिपोर्ट के पेज नंबर 40 पर यह जानकारी दी गई कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहां पर 2043 किमी तक तेज़ रौशनी की व्यवस्था करने की मंज़ूरी प्रदान की गई है, सिर्फ 100 किमी ही काम बाकी रह गया है, बाकी हो गया है. इसे दिखाने के लिए गृहमंत्रालय की रिपोर्ट में एक तस्वीर लगाई गई जिसके नीचे लिखा हुआ है, सीमा पर तेज़ रौशनी की व्यवस्था. जिसे आप देखकर समझेंगे कि वाह ये तो कमाल ही हो गया.

रवीश कुमार

किसी के लिए भी ये पता लगाना बड़ी चुनौती है कि फेक न्यूज़ है या नहीं. राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो कर कई वेबसाइट मौजूद हैं, जो न्यूज़ संगठन के भेष में आपके साथ छल कर रही हैं. भारत में इस तरह की कई वेबसाइट हैं जिनके नाम इस तरह से रखे गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कोई न्यूज़ संगठन होगा. दिक्कत ये है कि इनकी चोरी पकड़ लेने के बाद भी जो सफाई होती है, वो उस झूठ का पीछा नहीं कर पाती है जो बहुत दूर निकल चुकी होती है. फेक न्यूज़ खासकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा है. इसके ज़रिए कहीं सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, तो कहीं किसी दल के नेता को लगातार बदनाम किया जाता रहता है. सूचनाओं को पहले न्यूज़ की शक्ल में भेजा जाता है. कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना का चुटकुला बनाकर फिर से भेजा जाता है, ताकि आप बार-बार देखते रहे हैं कि जवाहर लाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहां से आते थे. 15 मई 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया की अमूल्या गोपालकृष्णनन ने नेहरू के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ को लेकर एक रिपोर्ट छापी. नेहरू भी फेक न्यूज़ वालों के तंत्र से नहीं बच सके. 'जवाहर एक अरबी शब्द का नाम है, कोई कश्मीरी ब्राह्मण अपने बच्चे का अरबी नाम रख ही नहीं सकता है. नेहरू के दादा गियासुद्दीन ग़ाज़ी थे, मुग़लों के कोतवाल थे जिन्होंने अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया. नेहरू का जन्म इलाहाबाद की वेश्याटोली में हुआ था. नेहरू ने एक कैथलिक नन को गर्भवती कर दिया था, चर्च ने उस नन को भारत से बाहर भेज दिया जिसके लिए नेहरू आजीवन चर्च के आभारी रहे.'

पहले तो यह सवाल आप ख़ुद से पूछिए कि क्या आपने कभी व्हाट्सऐप या इंटरनेट पर नेहरू से संबंधित इस तरह की फेक जानकारी देखी है. इस वक्त जब भारत में 16वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, तब किसी को पहले प्रधानमंत्री की वंशावली या उन्हें मुग़ल बताने में क्या दिलचस्पी हो सकती थी. एक पूरा राजनीतिक तंत्र लगा रहा नेहरू के बारे में इस तरह की बातों को फैलाने में. यह साल भर से ज़्यादा समय से चल रहा था. लेकिन जब अमूल्या ने इन तथ्यों की जांच की तब कुछ लोगों तक यह बात पहुंची, क्योंकि तब तक फेक न्यूज़ के गिरोह से लड़ने वाला अल्ट न्यूज़ डॉट इन नहीं आया था. यू ट्यूब पर भी नेहरू को लेकर कई तरह के वीडियो बनाए गए हैं, जिनमें फेक तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है. एक वीडियो का ज़िक्र है, जिसका टाइटल है हिन्दुस्तान का सबसे अय्याश आदमी. जिसे 40 लाख लोगों ने देखा था. मकसद है कि नेहरू की साख को ख़त्म करते रहा जाए.

नेहरू को लगातार बदनाम किया जा रहा है. नेहरू दुनिया में नहीं हैं. इसलिए 2019 में उनके प्रधानमंत्री का चुनाव उम्मीदवार बनने की कोई संभावना भी नहीं है, फिर एक राजनीतिक तंत्र क्यों नेहरू को बदनाम करता जा रहा है. नेहरू के बारे में ऐसी ग़लत सूचनाओं को न्यूज़ की शक्ल में पेश किया गया ताकि लाखों लोग देख सकें और नेहरू के प्रति घृणा फैलती रहे. इनमें से अधिकांश फेक न्यूज़ था. मकसद था कि नेहरू को कश्मीरी ब्राह्मण से मुसलमान बना दो. अय्याश बता दो. एक वीडियो में बताया गया है कि नेहरू की मौत एड्स से हुई थी. जैकलीन केनेडी और मृणालिनी साराभाई की तस्वीरें लगाकर नेहरू को अय्याश दिखाया गया. फोटोशॉप का इस्तेमाल हुआ. विकिपीडिया में नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को लेकर जानकारियां बदल दी गईं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के प्राणेश प्रकाश के हवाले से लिखा है कि सरकार के आईपी एड्रेस से यह बदलाव किया गया. 24 जनवरी 2016 की स्क्रोल डॉट इन की एक खबर है. जब नेताजी के पेपर सार्वजनिक किए गए, तो उनमें से कुछ भी ख़ास नहीं निकला मगर उसके हवाले से नेहरू के नकली पत्र बनाकर व्हाट्सऐप के ज़रिए बांटा जाने लगा, जिसके झांसे में पत्रकार तक आ गए. जब पता चला तो सबने डिलिट करना शुरू कर दिया और माफी मांगनी शुरू कर दी. जबकि इस तरह का कोई पत्र ही नहीं था.

फेक न्यूज़ का एक रूप यह भी है कि आज के समय में आपको फेक न्यूज़ देना और इतिहास के तथ्यों को भी फेक कर देना. सोचिए इस तरह से आप न तो आज के बारे में सही जान पाएंगे और न बीते हुए कल के बारे में. इंटरनेट पर नेहरू के बारे में फेक जानकारियां भरी जा रही हैं. आपका बच्चा स्कूल-कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जब डाउनलोड करेगा तो ग़लत जानकारियां लिख आएगा. हो सकता है कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित शिक्षक उन्हीं जानकारियों पर उसे नंबर भी दे दें और वो पूरी ज़िंदगी इस यकीन में जीता रहेगा कि जो जानता है वह सही था जबकि वो फेक था. फेक न्यूज़ और फेक वीडियो के कारण कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई है, हत्या हुई है और संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है. लेकिन इसी फेक न्यूज़ के ज़रिए इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा से जुड़ी जानकारी को ही मिटाने की कोशिश की गई.

आपने हाल ही में देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी इज़रायल दौरे पर होलोकॉस्ट मेमोरियल गए थे. जहां उन्होंने इतिहास का एक क्रूरतम अध्याय बताया था. लेकिन गार्डियन अखबार की कैरोल कैडवॉलडर ने नोटिस किया कि गूगल के सर्च में यह डालने पर कि क्या सच में हालोकॉस्ट हुआ था? तो जवाब आता है कि होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था और सर्च रिज़ल्ट एक नव नात्ज़ी वेबसाइट स्टॉर्मफ्रंट डॉट ओआरजी पर ले जाता है, जहां इस तरह की बातें लिखी हैं कि चोटी के दस कारण कि होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था. 11 दिसंबर 2016 के अपने लेख में कैरोल ने इस पर विस्तार से बात की है, जो गार्डियन अखबार में छपा है. उन्होंने बताया है कि यू ट्यूब पर भी इस तरह के कई वीडियो हैं. जबकि किताबों और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में यह बात दर्ज़ है कि हिटलर ने साठ लाख लोगों को मरवा दिया था. कैरोल ने जब यह सवाल उठाया तो उसके बाद गूगल ने सुधार कर दिया, लेकिन सोचिए इंटरनेट पर ऐसे कितने ऐतिहासिक साक्ष्यों को बदल दिया गया होगा. उसी तरह जैसे सरकारें इतिहास की किताबों को बदल देती हैं. आप सोचते हैं कि यह आपके और आपके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है. क्या आप इतने समझदार माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को फेक न्यूज़ और फेक हिस्ट्री की विरासत खुशी-खुशी देना चाहता है.

नेहरू को लगातार बदनाम किया जा रहा है. नेहरू दुनिया में नहीं हैं. इसलिए 2019 में उनके प्रधानमंत्री का चुनाव उम्मीदवार बनने की कोई संभावना भी नहीं है, फिर एक राजनीतिक तंत्र क्यों नेहरू को बदनाम करता जा रहा है. नेहरू के बारे में ऐसी ग़लत सूचनाओं को न्यूज़ की शक्ल में पेश किया गया ताकि लाखों लोग देख सकें और नेहरू के प्रति घृणा फैलती रहे. इनमें से अधिकांश फेक न्यूज़ था. मकसद था कि नेहरू को कश्मीरी ब्राह्मण से मुसलमान बना दो. अय्याश बता दो. एक वीडियो में बताया गया है कि नेहरू की मौत एड्स से हुई थी. जैकलीन केनेडी और मृणालिनी साराभाई की तस्वीरें लगाकर नेहरू को अय्याश दिखाया गया.

पिछले साल बज़फीड नाम की वेबसाइट ने 5 बड़ी फेक न्यूज़ की एक लिस्ट बनाई थी, मसलन-

❖ ओबामा ने देश के सभी स्कूलों में निष्ठा की शपथ लेने पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं. इसे फेसबुक पर 21 लाख बार शेयर किया गया.

❖ पोप फ्रांसिस ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन किया, इसे 9 लाख बार शेयर किया गया.

एक और दिलचस्प तथ्य है. अमेरिकी अख़बार द सन क्रॉनिकल के टॉम रिली ने 29 जून, 2017 को अपने एक संपादकीय में लिखा कि एसोसिएडेट प्रेस जैसी बड़ी संस्था भी फेक न्यूज़ का शिकार हुई है. जबकि यह संस्था 171 साल पुरानी है. दुनिया भर के 1700 अख़बारों, 5000 टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्ट एपी की स्टोरी छापते हैं. तो सोचिये कहां-कहां फेक न्यूज़ पहुंच जाता होगा. ये उस संस्था का हाल है, जिसके 120 देशों में 243 न्यूज़ ब्यूरो हैं. भारत के आठ दस टीवी चैनल मिला देंगे, तो भी इतने रिपोर्टर नहीं होंगे.

एसोसिएटेड प्रेस ने यह बात स्वीकार की है कि उसकी कुछ ऐसी ख़बरें भी थीं, जो न्यूज़ नहीं थीं. इसलिए एपी ने एक नया न्यूज़ फीचर शुरू किया है, नॉट रियल न्यूज़. इसके तहत ऐसी फेक न्यूज़ का पर्दाफ़ाश किया जाएगा जो ट्वीटर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई. फिर भी यह काम किसी बड़ी झील को छलनी से साफ़ करने जैसा है.

फेक न्यूज़ एक व्यापक श्रेणी है. इसकी कई उपशाखाएं हैं. एक शाखा है, फेक तस्वीरों की. कई नेताओं के ट्वीट से लेकर सरकार की रिपोर्ट तक में फेक तस्वीरें पहुंच जाती हैं और वहां से आप लोगों के बीच. हाल ही में भारत के गृहमंत्रालय की 2016-17 की सालाना रिपोर्ट के पेज नंबर 40 पर यह जानकारी दी गई कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहां पर 2043 किमी तक तेज़ रौशनी की व्यवस्था करने की मंज़ूरी प्रदान की गई है, सिर्फ 100 किमी ही काम बाकी रह गया है, बाकी हो गया है. इसे दिखाने के लिए गृहमंत्रालय की रिपोर्ट में एक तस्वीर लगाई गई जिसके नीचे लिखा हुआ है, सीमा पर तेज़ रौशनी की व्यवस्था. जिसे आप देखकर समझेंगे कि वाह ये तो कमाल ही हो गया. लेकिन जब 14 जून को अल्ट न्यूज़ डॉट इन ने इस तस्वीर को झूठ बताते हुए रिपोर्ट छापी, तो सब हैरान रह गए. आखिर गृहमंत्रालय की रिपोर्ट में फेक तस्वीर कैसे जा सकती है, आई कहां से. क्या ये रिपोर्ट गूगल सर्च करके बनाई जा रही थी. अल्ट न्यूज़ डॉट इन ने बताया कि यह तस्वीर स्पेन मोरक्को सीमा की है. गनीमत है कि गृहमंत्रालय के गृहसचिव ने ज़रा भी देरी नहीं की. बाद में खबर आई कि गृहसचिव ने रिपोर्ट की तैयारी से जुड़े अधिकारियों से सफाई मांगी तो पता चला कि बीएसएफ से ये तस्वीर आई थी. गृहसचिव ने इसके लिए अफसोस जताया और सालाना रिपोर्ट के ऑनलाइन संस्करण से तस्वीर हटा ली गई है. मगर तीन महीने से यह तस्वीर मौजूद थी. जाने कहां-कहां पहुंच गई होगी. आल्ट न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिंदुत्व डॉट इन्फो पर इसे लेकर सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचार शुरू हो गया. लिखा गया कि भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील करने का काम भी ज़ोर से चला हुआ है और जल्द ही सीमाएं पहले की अपेक्षा काफी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी. एक काम करने वाली सरकार को ऐसा करते देखते हुए काफी अच्छा अहसास होता है...

यही नहीं, बीजेपी के सांसद परेश रावल के दो ट्वीट की चर्चा करने जा रहा हूं. पहला ट्वीट 3 जुलाई का है. सांसद परेश रावल ने पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम का एक बयान ट्वीटर हैंडल पर शेयर कर दिया. लिखा कि ये छद्म लिबरल लोगों के लिए है. बाद में पता चला कि वो बयान कलाम का था ही नहीं.

इस बयान में लिखा था कि मुझे पाकिस्तान ने इस्लाम का हवाला देकर मिलाने का प्रयास किया लेकिन मैंने मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं की. जब हंगामा हुआ तो परेश रावल ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि यह फेक है. अगर इनकी जगह कोई और होता, तो मैं इसे दो बार चेक करता मगर कलाम की वजह से मुझे यह सही लगा.

यह बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा हुआ है और ऐसा हो जाता है. कोई भी ऐसी तस्वीरों और बयानों के झांसे में आ जाता है. लेकिन जब उन्होंने मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को लेकर एक ट्वीट किया तो उसके कई ख़तरनाक पहलू सामने आ गए.

17 मई 2017 को परेश रावल ने ट्वीट किया कि अरुंधति रॉय ने इंटरव्यू दिया है कि 70 लाख भारतीय सेना कश्मीर के आज़ादी गैंग को हरा नहीं सकती. इसी के साथ उन्होंने अरुंधति रॉय की तस्वीर लगा दी, जिसमें वो सेना की जीप के आगे बिठाई गई हैं.

इसे लेकर कई बड़े न्यूज़ चैनलों पर बकायदा बहस हो गई. बहस का तेवर ऐसा था कि अरुंधति रॉय के खिलाफ भीड़ आक्रामक हो सकती थी. जबकि अरुंधति राय न तो हाल में श्रीनगर गई थीं और न ही ऐसा कोई इंटरव्यू किसी को दिया था. अरुंधति राय ने एक साल पहले आउटलुक पत्रिका को ज़रूर इंटरव्यू दिया था, मगर परेश रावल का ट्वीट उस इंटरव्यू को लेकर नहीं था. 24 मई को द वायर डॉट इन ने जब यह पता लगाया कि परेश रावल तक जानकारी कैसे पहुंची, तो फेक न्यूज़ का एक और ख़तरनाक पहलू सामने आ गया.

परेश रावल ने अरुंधति रॉय का यह फेक इंटरव्यू द नेशनलिस्ट नाम के फेसबुक पेज से उठाकर ट्वीट कर दिया. इस पेज पर ख़बर पहुंची पोस्टकार्ड डॉट न्यूज़ से, इस वेबसाइट की कई ख़बरें फेक न्यूज़ के सिलसिले में विवादित हो चुकी हैं. इस पर लिखा था कि अरुंधति रॉय ने यह इंटरव्यू द टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद को दिया है कि 70 लाख भारतीय सेना कश्मीर के आज़ादी गैंग को हरा नहीं सकती हैं. पोस्टकार्ड डॉट न्यूज ने अपना सोर्स नहीं बताया, लेकिन वायर ने पाया कि रेडियो पाकिस्तान ने सबसे पहले यह प्रसारित किया था. जिस द टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद को पाकिस्तानी अख़बार बताया जा रहा है, वो वेबसाइट है, अखबार नहीं है. पोस्टकार्ड डॉट न्यूज ने जिस दिन ये फेक इंटरव्यू छापा था, उसी दिन इसे सत्यविजयी डॉट कॉम ने भी छापा और चार पांच वेबसाइट ने भी इसे अपने यहां जगह दी. इन सभी का नाम भी फेक न्यूज़ के सिलसिले में आ चुका है. द वायर डॉट इन ने पकड़ा कि इंटरनेट हिंदू डॉट इन ने अपनी स्टोरी में टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद का लिंक दिया था. आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तानी साइट से चलते हुए फेक न्यूज़, फेक इंटरव्यू भारत के सांसद के ट्वीटर हैंडल पर पहुंचता है और वहां से भारत के चैनलों पर अरुंधति रॉय के ख़िलाफ़ ज़ोरदार बहस छिड़ जाती है. परेश रावल ने ट्वीट डिलिट कर दिया, लेकिन आज भी यह फेक इंटरव्यू रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट और भारत के पास्टकार्ड डॉट न्यूज़ पर तस्वीर के साथ है. यह भी एक रणनीति है. जब विवाद थम जाएगा तो फिर से इस फेक इंटरव्यू को घुमाया जाने लगेगा या क्या पता व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी में घुमाया ही जा रहा हो.

आप सोचिए यह कितना ख़तरनाक पहलू है. फेक न्यूज़ के मामले में भारत और पाकिस्तान की वेबसाइट भी एक दूसरे की मदद कर सकती हैं. कोई आपके नाम से पाकिस्तान में फेक इंटरव्यू छपवा दे, जब तक आप सफाई देंगे, टीवी चैनल, नेता और ये वेबसाइट मिलकर आपका भयंकर नुकसान कर चुके होंगे. अभी तो इसके ज़रिए आवाज़ उठाने वालों को डराया जा रहा है, कमज़ोर और डरपोक विपक्ष को डराया जा रहा है. लेकिन जल्दी ही इस खेल के ज़रिए आप लोगों को भी फिक्स किया जाने लगेगा. बल्कि किया भी जा रहा है. ■

(लेखक जाने माने टीवी पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

अमरनाथ यात्रियों पर हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही

हारून रेशी

बीते 10 जुलाई की रात कश्मीर में आतंकवादियों ने 61 यात्रियों से भरी बस पर अपनी बंदूकों के दहाने खोल दिए. इस घटना में महज 20 सेकेंड में ही पांच महिलाओं समेत सात लोगों की मौत गई और 19 घायल हो गए. घायलों में शामिल एक इलाजरत महिला ने बाद में दम तोड़ दिया. ड्राइवर ने बुद्धि से काम लेते हुए बस को रोकने के बजाय उसे तेजी से भगा दिया. जिसके कारण केवल 20 सेकेंड तक ही ये गाड़ी गोलियों की चपेट में रही. अगर ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी रोक दी होती, तो शायद इसमें सवार एक भी अमरनाथ यात्री जिंदा नहीं बच पाता. बस जब काफी दूर जाकर रुकी, तब इसमें सवार यात्रियों की चिख-पुकार आसपास के लोगों ने सुनी.

दक्षिणी कश्मीर के जिस इलाके में ये घटना हुई, वो सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है. इस घटना के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आ चुकी हैं. अमरनाथ यात्रियों पर हुआ ये आतंकी हमला बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की असफलता का निर्विवाद साक्ष्य है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने से कई हफ्तों पहले ये माला जपने लगी थीं कि यात्रा की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. कहा जा रहा था कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 हजार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. लेकिन इन सबके बावजूद, इस घटना से जुड़ी जानकारियां बता रही हैं कि ये घटना सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही से हुआ है. 61 यात्रियों से भरी वो बस अमरनाथ यात्रा के कारवां में रजिस्टर्ड नहीं थी और न ही उसमें सवार किसी भी यात्री ने रजिस्ट्रेशन कराया था. जबकि सुरक्षा नियमों के अनुसार हर यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और इसके लिए देशभर में सैकड़ों काउंटर खोले जा चुके हैं. गौर करने वाली बात ये है कि केवल बस और यात्री ही रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं थे, बल्कि ओसाई ट्रैवल्स एजेंसी जिसकी वो बस थी, वो भी कश्मीर की किसी टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन में शामिल नहीं है. लेकिन इसके बावजूद वे यात्री कश्मीर आए, अमरनाथ गुफा में जाकर दर्शन भी किए और वहां से वापस भी आए, क्या ये सुरक्षा खामी नहीं है? अगर बिना रजिस्ट्रेशन के 61 लोगों का ग्रुप गुफा तक पहुंच सकता है और वहां से वापस भी आ सकता है, तो इसका मतलब है कि वहां कोई भी जा सकता है और सरकार को कानों-कान खबर भी नहीं होगी. बस पर ये हमला रात के ठीक 8 बजकर 25 मिनट पर हुआ. सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से निर्धारित नियम के अनुसार, सात बजे के बाद अमरनाथ यात्रियों को चलने-फिरने की अनुमति नहीं है. तो फिर ये बस 8.30 बजे दक्षिणी कश्मीर के राजमार्ग पर कैसे जा रही थी और सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में पता क्यों नहीं था?

जिस स्थान पर हमला हुआ, वहां से केवल 200 मीटर की दूरी पर एक फौजी कैंप है और पास में ही कश्मीर पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स का भी एक पोस्ट है. लेकिन इसके बावजूद, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमले के 25 मिनट बाद सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे. क्या ये सुरक्षा खामी नहीं है?

जम्मू-कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मुनीर अहमद खान का कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रियों पर संभावित हमले के बारे में पहले ही सूचित किया था. आईजी ने हमले से दो दिन पूर्व ही सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल को लिखे पत्र में बताया था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की सूचनाओं के अनुसार मिलिटेंट्स अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा हमला कर सकते हैं. इस पत्र में लिखा गया है कि मिलिटेंट्स 100-150 यात्रियों और 100 पुलिस अफसरों को मारने का इरादा रखते हैं. उनका मकसद है कि देशभर में धार्मिक घृणा फैलाई जा सके. लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों की इस सूचना के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां ये हमला रुकवाने में असफल रहीं. राज्य के उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने भी ये स्वीकार किया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी. अब सवाल है कि हमले का अंदेशा होने के बाद भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इतनी लापरवाह क्यों रहीं?

कश्मीर की सिविल सोसायटी और ट्रेडर्स ने इस हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है. हमले के एक दिन बाद श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक प्रदर्शन के दौरान मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, नेताओं और सिविल सोसायटी के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए जोरदार शब्दों में इस घटना की निंदा की और इसकी जांच की मांग की.

ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा. कश्मीर की सिविल सोसायटी और ट्रेडर्स ने इस हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है. हमले के एक दिन बाद श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक प्रदर्शन के दौरान मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, नेताओं और सिविल सोसायटी के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए जोरदार शब्दों में इस घटना की निंदा की और इसकी जांच की मांग की. सोशल मीडिया में भी नीजवानों ने इस आतंकवादी हमले का विरोध किया और इसे कश्मीरियत और इंसानियत पर हमला करार दिया गया. धार्मिक लोगों ने इसे गैर इस्लामी काम कहा. हुर्रियत के नेताओं ने भी एक साथ इसकी निंदा की. व्यापारियों, ट्रांसपोटरों और दूसरे संगठनों ने भी अपने बयानों में इस हमले का विरोध किया.

पिछले 30 वर्ष की हिंसक परिस्थितियों में ये अमरनाथ यात्रियों पर हुआ दूसरा बड़ा हमला है. पहला हमला अगस्त 2000 में पहलगाम के निकट यात्रियों के बेस कैंप पर हुआ था. इस हमले में 21 यात्री, छह आम कश्मीरी और दो पुलिस वाले मारे गए थे. उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी. एक उच्च स्तरीय कमेटी से उस हमले की जांच कराई गई थी, जिसका नेतृत्व सेना की 15वीं कोर के कमांडर कर रहे थे. इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आतंकवादियों के हमले का निशाना बुनियादी तौर पर पुलिस और सेना के जवान थे, लेकिन यात्री उसकी चपेट में आ गए. अब 17 साल बाद दुबारा वैसा हमला हुआ है. सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसकी जांच कराए और इसमें शामिल लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाए. इसके साथ ही सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की अग्रीम सूचना के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने लापरवाही क्यों बरती? सही जानकारियां तभी सामने आएगी जब इस घटना की बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता के साथ जांच हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्किल इंडिया : हुनरमंद बनाने की चुनौती

विकास सिंह

प्रधानमंत्री ने कौशल विकास अभियान 'स्किल इंडिया' की शुरुआत करते हुए कहा था कि जिस तरह चीन वैश्विक विनिर्माण कारखाना बन गया है, वैसे ही भारत को दुनिया के 'मानव संसाधन केंद्र' के रूप में उभरना चाहिए. देश के युवाओं का कौशल विकास कर निकट भविष्य में अन्य देशों की जरूरतों को भी पूरा करना हमारा लक्ष्य है.

प्रशिक्षण देने की लक्ष्य प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को काम पर लगाया गया. लेकिन विगत समय में जिस तरह से इस योजना के क्रियान्वयन में खामियां देखने को मिल रही हैं, उससे लगता है कि स्किल इंडिया मिशन का हाल भी अन्य कई दूसरी परियोजनाओं की तरह न हो जाए. 'स्किल इंडिया' अभियान से गरीबी के खिलाफ सरकार की लड़ाई का उद्घोष भी गरीबी हटाओ और शाइनिंग इंडिया जैसा ही न साबित हो. योजना का जिस कुशलता से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहा है. इसकी तस्दीक हाल में उत्पन्न स्थितियों से की जा सकती है.

योजना के तहत ऐसे केन्द्र को मान्यता दी जाती है, जो निर्धारित मानदंडों पर स्थापित किए गए हों. इन केन्द्रों को तैयार करने में लाखों रुपयों की लागत आती है, लेकिन हाल में एनएसडीसी ने घोषणा की कि उनके नए नियमों के मुताबिक फ्रेंचाइजी सेंटर्स को काम नहीं मिलेगा. न ही अब इन फ्रेंचाइजी सेंटर्स को ट्रेनिंग के बदले पैसे दिए जाएंगे और न ही यहां ट्रेनिंग लेने वालों को प्रमाण पत्र मिलेगा. विरोध में उन लोगों ने प्रदर्शन किया, जिनके केन्द्रों को ट्रेनिंग देने के लिए एनएसडीसी ने मंज़ूरी दी थी. लोगों ने अपने केन्द्रों पर काफ़ी पैसे खर्च कर ज़रूरी इंतज़ाम किए, लेकिन अब ट्रेनिंग देने का काम नहीं मिलने से ठगा महसूस कर रहे हैं. परेशान और कर्ज में डूबे सेन्टर मालिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या? ऐसे में कई सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं, नहीं तो सरकार के आह्वान पर कोई भी विकास कार्य, स्वरोजगार या उद्यम शुरू करने वालों का विश्वास उठ जाएगा. इससे स्टार्ट-अप जैसी सोच और मिशन को भी धक्का लगेगा. भविष्य में कोई भी सरकार की बातों पर भरोसा कर किसी काम में पूंजी लगाने से पहले सौ बार सोचेगा.

जहां सरकारी एजेंसी द्वारा उच्च ग्रेड प्राप्त केन्द्रों को काम नहीं दिया गया, वहीं महज अंडरटेकिंग लेकर कई नामी-गिरामी संस्थाओं को काम दे दिया गया. जबकि नियम के तहत पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग पार्टनर बनाए जाएंगे, फिर ट्रेनिंग पार्टनर के ज़रिए फ्रेंचाइज़ी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे. लेकिन तमाम नियमों की अनदेखी कर महज अंडरटेकिंग लेकर काम दे दिया गया. स्थिति यह है कि अंडरटेकिंग देकर काम लेने वाली संस्थाओं ने अब तक कई सेन्टर्स शुरू भी नहीं किए हैं.

सरकार चाहती है कि रोजगार के अवसर बढ़े. यही कारण है कि कौशल विकास के साथ उद्यमशीलता पर भी जोर दिया गया है. लेकिन अपनी पूंजी लगाकर उद्यमशीलता की अलख जगाने वाले उद्यमी आज एनएसडीसी के नए नियमों के जाल में उलझकर रह गए हैं. गांव-गांव में स्वयं की पूंजी लगाकर खोले गए केन्द्रों को फ्रेन्चाइजी के नियम और पांच जॉब रोल का लक्ष्य पूरा होने की बात कह कर, इन केन्द्रों को अब काम नहीं देना, एनएसडीसी की कमियों को ही उजागर करता है. सवाल यह है कि अगर लक्ष्य पूरा हो गया था तो नया केन्द्र बनाने क्यों दिया गया? उनका निरीक्षण कर उन्हें मान्यता क्यों दी गई? उनसे शुल्क क्यों लिया गया? समय-समय पर अपने पोर्टल पर टार्गेट की राज्यवार और जॉब रोल के हिसाब से विवरण क्यों नही दिया गया? बिना किसी पूर्व सूचना के टार्गेट देना बंद क्यों कर दिया गया? एनएसडीसी ने अगर इसका लगातार मूल्यांकन किया होता, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती.

रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे भी सेंटर्स हैं, जिन्हें मंज़ूरी तो मिली, लेकिन असल में वो ग़ायब हैं या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें घोस्ट सेंटर का नाम दे दिया गया. ऐसे घोस्ट सेंटर्स की कोई कमी नहीं है. सवाल यह है कि घोस्ट सेंटर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कैसे ये केन्द्र अब तक चलते रहे, जबकि इन केन्द्रों की मॉनिटरिंग के लिए शुल्क भी केन्द्र मालिकों से ही एनएसडीसी और स्किल सेक्टर काउंसिल लेते हैं.

योजना के तहत ऐसे केन्द्र को मान्यता दी जाती है, जो निर्धारित मानदंडों पर स्थापित किए गए हों. इन केन्द्रों को तैयार करने में लाखों रुपयों की लागत आती है, लेकिन हाल में एनएसडीसी ने घोषणा की कि उनके नए नियमों के मुताबिक फ्रेंचाइजी सेंटर्स को काम नहीं मिलेगा. न ही अब इन फ्रेंचाइजी सेंटर्स को ट्रेनिंग के बदले पैसे दिए जाएंगे और न ही यहां ट्रेनिंग लेने वालों को प्रमाण पत्र मिलेगा.

लोगों को हुनरमंद बनाना बड़ी चुनौती है. अगर इस चुनौती से निपटना है तो गांव-गांव में खुल रहे केन्द्रों को और मजबूत करना होगा. देश के पिछड़े इलाकों की सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक व्यवस्था ऐसी है कि वहां से युवाओं खास कर लड़कियों को शहर के केन्द्रों तक लाना आसान काम नहीं होगा. ऐसे में अगर परियोजना का लाभ सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाना है, तो जमीनी स्तर पर काम कर रही संस्थाओं को भी साथ लाना होगा. हर जिले में आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान उपलब्ध हैं, उन्हें ही पीएमकेके के तौर पर स्थापित करने पर जोर देना चाहिए. एनएसडीसी को अपनी व्यवस्था और चुस्त-दुरुस्त करनी होगी, अगर ऐसा नहीं कर पाए, तो कौशल विकास की चुनौती से निबटने की असफलता का दाग उनके ही दामन पर लगेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा के ख़िलाफ़ एकता का कर रहे जतन, पर सीटों को लेकर एकमत नहीं

झारखंड में आसान नहीं महागठबंधन की राह

प्रशांत शरण

मिशन 2019 के नारे के साथ लोकसभा चुनाव पर लक्ष्य साध कर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल एक होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर एक मत नहीं हो पाते. झारखंड में 2019 का पेंच यहीं आकर फंस जा रहा है. मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा सबसे आगे हैं. जाहिर है, जब झारखंड में महागठबंधन बनेगा तो झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ही इसके संयोजक होंगे और वे अपने पुत्र हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री की ताज सौंपना चाहेंगे. जबकि गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे. बाबूलाल की छवि अभी भी एक ईमानदार, मृदुभाषी एवं स्पष्ट विजन वाले नेता के रूप में बनी हुई है. हालांकि डोमिसाइल का मामला बाबूलाल के ऊपर अभी भी एक धब्बे के रूप में कायम है. हेमंत की भी छवि एक कर्मठ एवं विजन वाले नेता के रूप में कायम है. हेमंत के पिता झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन निश्चित ही धृतराष्ट्र की भूमिका में रहेंगे और महागठबंधन में यह शर्त हर हाल में रखेंगे. झारखंड में विपक्षी दल बिहार मॉडल तो अपनाना चाहते हैं, परन्तु यहां राह बिहार की तरह आसान नहीं है. बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को यह अहसास हो गया था कि यदि राजनीति में वजूद बनाए रखना है, तो गठबंधन बनाना ही पड़ेगा. यही कारण है कि दोनों ही नेता सारे अहंकार को भूल चुनावी मैदान में भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गए. मगर झारखंड में महागठबंधन में झामुमो का अहम इसके आड़े आ रहा है. इसका कारण भी है, झामुमो को लोकसभा चुनाव से कोई ज्यादा लेना-देना नहीं है और वह अपना सारा फोकस विधानसभा चुनाव पर ही करना चाहती है. उसे क्षेत्रीय राजनीति में ही दिलचस्पी है.

अगर गठनबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों की स्थिति पर गौर करते हैं, तो झामुमो अभी झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी है और विधानसभा में विपक्षी दल की भूमिका में है. इसके 19 विधायक हैं, तो जाहिर है यह गठबंधन का मुख्य हिस्सा होगा, पर इसे मुख्यमंत्री पद से कम पर समझौता मंजूर नहीं होगा. भावी समझौते में इसे 40 से कम सीटें मंजूर नहीं होंगी. संथाल परगना एवं कोल्हान में इसकी पकड़ मजबूत है और खासकर आदिवासी मतदाताओं पर झामुमो की पकड़ मजबूत मानी जाती है. वही झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण लोग अभी तक याद करते हैं. झारखंड गठन के बाद दो सालों में विकास का काम राज्य में खूब हुआ, उन कार्यों को लोग भी अब तक नहीं भूल पाए हैं. बाबूलाल ने अपने बलबूते पिछले विधानसभा चुनाव में आठ सीटों पर जीत दर्ज की थी, पर दुर्भाग्य यह था कि उसके छह विधायकों को भाजपा ने दल बदल करा कर अपने साथ ले लिया. बाबूलाल मरांडी को इस बार गैर आदिवासियों का भी समर्थन मिल सकता है. धनबाद चंद्रपुरा रेल लाईन को बंद किए जाने के बाद इनके द्वारा की गई पदयात्रा में गैर आदिवासियों का एक बड़ा जनसमूह इनके साथ था. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाबूलाल का साथ लेकर झारखंड में शराबबंदी का बड़ा अभियान चलाया था और इसमें दोनों नेताओं की लोकप्रियता काफी बढ़ी थी. नीतीश बाबूलाल के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं. यही कारण भी है कि नीतीश और बाबूलाल संयुक्त रूप से कई जनसभा और कार्यक्रम कर चुके हैं. झारखंड में कुर्मी मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है और अगर नीतीश कुर्मी मतदाताओं को थोड़ा भी गोलबंद करने में सफल रहते हैं, तो यह गठबंधन एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है. वैसे अगर बाबूलाल के नेतृत्व में गठबंधन चुनाव लड़ता है, तो जाहिर है कि झामुमो इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी, क्योंकि पार्टी को मुख्यमंत्री पद से कम कुछ स्वीकार नहीं होगा.

> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पूरी तरह से अहसास हो गया है कि झामुमो बाबूलाल मरांडी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती है. दोनों ही दल के नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और यही कारण है कि नीतीश ने झामुमो को अपने गठबंधन में आने का न्यौता कभी नहीं दिया. बाबूलाल भी नीतीश को ही साथ लेकर चल रहे हैं. नीतीश भी शराबबंदी अभियान के बहाने झारखंड में अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं और वे वहां बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं.

उधर नीतीश कुमार से अलग-थलग चल रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद झारखंड में अपनी अलग राजनीतिक गोटी सेट करने की कोशिश में हैं. चारा घोटाले में फंसे लालू प्रसाद को अभी सीबीआई की अदालत में हाजिरी लगाने हर सप्ताह रांची आना पड़ता है और इस कारण लालू प्रसाद यहां के राजनीतिक हालात से लगातार अवगत हो रहे हैं. लालू यहां झामुमो एवं कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश में हैं. झामुमो के हेमंत सोरेन भी लगातार लालू प्रसाद के सम्पर्क में हैं. अगर ये तीनों ही पार्टियां एकजुट हुईं, तो बहुत संभव है कि झामुमो की सत्ता में वापसी हो जाय. तीनों ही दल अल्पसंख्यकों के हितैषी माने जाते हैं और तीनों के साथ हो जाने पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा. अभी झामुमो एवं कांग्रेस के पास 80 विधानसभा क्षेत्रों से 25 विधायक हैं, झामुमो 22 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर थी. राजद के पास अभी एक भी विधायक नहीं है. लेकिन झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में राजद की अच्छी पकड़ है. अगर यह पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरती है, तो कम से कम पांच सीटों पर चुनाव जीतने में सक्षम हो सकती है. कांग्रेस यहां राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जरूर है, लेकिन इसका जनाधार खिसकता ही जा रहा है. पार्टी में लगातार गुटबाजी के कारण संगठन कमजोर होता जा रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ही यहां एकमात्र कद्दावर नेता के रूप में हैं. अभी यहां कांग्रेस के छह विधायक हैं. लेकिन दूसरे दलों का दामन थामकर कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकती है. कांग्रेस ने बिहार से सबक सीखा है, जहां इसके एक-दो विधायक हुआ करते थे, वहां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बाद अब इसके पास तीन दर्जन विधायक हैं. हालांकि झारखंड गठबंधन में कांग्रेस लगभग बीस सीटों पर ही दावेदारी कर सकती है. इस गठबंधन के बारे में सुबोधकांत सहाय का कहना है, 'झामुमो के साथ कांग्रेस लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव लड़ सकती है. अभी दोनों दलों के बीच बातचीत प्रारंभिक अवस्था में है. राजद भी इस महागठबंधन का प्रमुख अंग होगी. साम्प्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए हमें एक मंच पर आना ही होगा.' अब इन तीनों दलों का एक साथ होना लगभग तय है. झामुमो नेता हेमंत सोरेन एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है. खुद हेमंत सोरेन यह स्वीकार करते हैं कि झामुमो समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन बनाएगी और इसी गठबंधन के तहत पार्टी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में उतरेगी.

इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पूरी तरह से अहसास हो गया है कि झामुमो बाबूलाल मरांडी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती है. दोनों ही दल के नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और यही कारण है कि नीतीश ने झामुमो को अपने गठबंधन में आने का न्यौता कभी नहीं दिया. बाबूलाल भी नीतीश को ही साथ लेकर चल रहे हैं. नीतीश भी शराबबंदी अभियान के बहाने झारखंड में अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं और वे वहां बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं. इसका एक और कारण यह भी है कि झारखंड के लोगों में यह प्रचारित किया जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार का खूब विकास हुआ है. झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकास कार्य नहीं होने से यहां के युवा मतदाता इस सरकार से खासतौर से नाराज हैं. नीतीश की ईमानदार छवि ने भी झारखंडियों के बीच उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया है. नीतीश और बाबूलाल झारखंड में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने साथ आजसू को रखना चाह रहे हैं. आजसू की महतो एवं मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है. झारखंड में भाजपा के बाद सबसे बड़ा संगठन आजसू का ही है. आजसू प्रमुख सुदेश महतो युवा नेता हैं और उनके सामने एक बड़ा राजनीतिक करियर पड़ा है, ऐसे में वे उपमुख्यमंत्री और कुछ मंत्री पद लेकर संतुष्ट हो सकते हैं. झाविमो को भी आजसू का यह फार्मूला पसंद आएगा. झाविमो और जदयू में पहले से समझौता हुआ ही है. नीतीश के लिए भी बाबूलाल से मिलना फायदे का ही सौदा है. अगर नीतीश के पांच विधायक भी चुनकर आ गए, तो झारखंड की राजनीति में उनका दखल बना रहेगा. यह एक ऐसा गठबंधन हो सकता है, जो झारखंड में तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकता है. हालांकि आजसू सुप्रीमो इस पर अभी बोलने से कतरा रहे हैं, पर इतना जरूर कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है. आजसू अभी भाजपा गठबंधन में है, लेकिन सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है. सीएनटी-एसपीटी मुद्दे पर तो आजसू काफी मुखर है. भाजपा नेता अर्जुन मुंडा के साथ तो सुदेश का बहुत ही अच्छा सम्बंध था. लेकिन मुख्यमंत्री रघुवर दास से उनकी नहीं पट रही है और यही कारण है कि सरकार में रहते हुए भी आजसू सरकार के खिलाफ आग उगलती रहती है. अगर नीतीश यह मोर्चा बनाने में सफल रहे, तो चुनावी जंग में तीसरा मोर्चा चैंकाने वाले परिणाम दे सकता है.

झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी भी इस मोर्चे पर राजी हैं. इसका कारण भी साफ है कि अगर यह मोर्चा 25 सीट भी जीतने में कामयाब रहा, तो कांग्रेस और अन्य दलों का समर्थन लेकर सरकार बना सकता है. बाबूलाल की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी में भी कोई बाधा सामने नहीं आएगी. इसलिए बाबूलाल भी पूरे दम-खम के साथ चुनावी तैयारी में लगे हुए है और इन्हें जनसमर्थन भी मिल रहा है. बाबूलाल की आदिवासी वोटरों पर अच्छी पकड़ है. पिछले चुनाव में उन्होंने आठ सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन भाजपा ने इनके छह विधायकों को अपने पाले में कर लिया. उस दल-बदल का मामला अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में लंबित है. भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर बाबूलाल की पार्टी से ही है. भाजपा को यह भली-भांति पता है कि कुछ विधानसभा सीटों पर भले ही बाबूलाल की पार्टी की जीत न हो, लेकिन वह भाजपा को हराने का दमखम जरूर रखती है. गौरतलब है कि बाबूलाल भाजपा में रहते हुए ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे. इस कारण उनका और भाजपा का कोर वोटर एक ही हैं. इन सब के बावजूद, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में किसी भी गठबंधन की राह आसान नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार चुनावी मोड में चली गई है

www.kamalmorarka.com

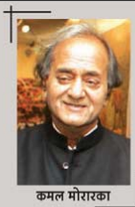

कमल मोरारका

पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने यह सुझाव दिया कि सबसे पहले भारत और चीन दोनों को अपनी पूर्व घोषित स्थिति पर वापस आना चाहिए. चीन ने अपनी पूर्व की स्थिति में बदलाव किया है. उन्होंने कहा कि चीन को कुटनीतिक रास्ता अख्तियार करना चाहिए. अपनी पूर्व घोषित स्थिति से हटना न तो भारत के हित में है और न ही चीन के हित में. यह स्थिति वर्षों तक दोनों देशों के बीच कायम रही है. दोनों देशों की सेनाओं का एक दूसरे से टकराव किसी के लिए भी ठीक नहीं है.

भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो गया. इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ. रामनाथ कोविंद एक ज़िम्मेदार वरिष्ठ नेता हैं. मुझे विश्वास है कि वे वही करेंगे जिसकी यकीन है कि वे अपने पद के साथ न्याय करेंगे. बेशक वे भाजपा की तरफ से हैं, आम तौर पर यही होता है कि सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रपति उम्मीदवार तय करता है. इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए.

दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है जीएसटी का. एक छोटी अवधि में किसी प्रणाली को पूरी तरह से बदल देना आसान नहीं होता. बहरहाल, शुरुआत तो करनी थी और शुरुआत हुई भी, लेकिन इसको लेकर व्यापारियों में बड़े पैमाने पर रोष है. अब ये रोष वास्तविक है या वे जीएसटी को समझ नहीं पाए हैं या फिर इसके प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है, इन सब को लेकर सरकार को अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए, ताकि उनकी भावनाओं को शांत किया जा सके. गुजरात समेत देश के अलग-अलग भागों में व्यापारियों के व्यापक प्रदर्शन को बहुत दिनों तक जारी नहीं रहने दिया जा सकता. गुजरात में लोग व्यवसायिक प्रवृति के होते हैं. यदि आप उनकी नहीं सुनेंगे, तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. वाणिज्य विभाग और उद्योग विभाग राज्य के मुख्य सचिव के साथ मिल कर इसपर ज़रूर विचार-विमर्श कर रहे होंगे. बहरहाल, जीएसटी एक कठिन काम है. आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा. देश के भले के लिए हम यह आशा करते हैं कि वे इसमें कामयाब हों.

इसके बाद चीन के साथ गतिरोध का मुद्दा है. पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने यह सुझाव दिया कि सबसे पहले भारत और चीन दोनों को अपनी पूर्व घोषित स्थिति पर वापस आना चाहिए. चीन ने अपनी पूर्व की स्थिति में बदलाव किया है. उन्होंने कहा कि चीन को कुटनीतिक रास्ता अख्तियार करना चाहिए. अपनी पूर्व घोषित स्थिति से हटना न तो भारत के हित में है और न ही चीन के हित में. यह स्थिति वर्षों तक दोनों देशों के बीच कायम रही है. दोनों देशों की सेनाओं का एक दूसरे से टकराव किसी के लिए भी ठीक नहीं है. चीन के लोग समझदार हैं और मुझे विश्वास है कि वे वही करेंगे जिसकी आवश्यकता है. हमें पाकिस्तान के द्वारा चीन से हाथ मिलने से अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. पाकिस्तान एक अवसरवादी देश है. उन्हें भारत को चोट पहुंचाने का जहां भी मौक़ा मिलेगा, वे उसका इस्तेमाल करेंगे. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें चीन को ज़िम्मेदारी के साथ कूटनीतिक रूप से व्यस्त रखना चाहिए और बिना टकराव के मामलों को सुलझाना चाहिए.

कर्नाटक में झंडे का विवाद खड़ा हुआ है. दरअसल, कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत झंडा रख सकता है, इसमें परेशानी कहां हैं. राष्ट्र, राष्ट्र होता है. पहले दिन से ही तमिलनाडु का अपना झंडा है. यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसे तूल दिया जाए. हर मुद्दे को कांग्रेस भाजपा मुद्दा बना देने का कोई मतलब नहीं है. जो लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं, उनमें इतनी साहस नहीं है कि वे तमिलनाडु को उसका झंडा छोड़ देने के लिए कह सकें. कश्मीर की एक विशेष स्थिति है. कश्मीर का झंडा संविधान सम्मत है. आर्टिकल 370 इसकी मान्यता देता है. यह झंडा केवल एक निशानी है. इस झंडे की कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है. भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है और इसकी ही अंतरराष्ट्रीय मान्यता है. भारतीय संघ के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपनी अलग पहचान चाहता है, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है. यह भाषा की तरह है, जैसे कन्नड़ है, मराठी है. ऐसे मुद्दों को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए.

सरकार चुनावी मोड में चली गई है. फ़िलहाल वे 2019 के चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं. उन्हें व्यवसाइयों या किसानों या किसी अन्य की कोई चिंता नहीं है. यह हमारी बदक़िस्मती है. लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है, जिसके वे अधिकारी होते हैं. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे अच्छा होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

आर या पार महाराजा के साथ छलावा

एयर इंडिया कोई अकेली विमानन कंपनी नहीं है, जिसकी स्थिति खराब है. निजी विमानन कंपनियों की हालत भी ठीक नहीं है. किंगफिशर एयरलाइंस भी ऐसा ही एक उदाहरण है. उदारीकरण के बाद कई कंपनियों ने काम शुरू किया. इनमें से 23 या तो बंद हो गए या उनका किसी दूसरी कंपनी में विलय हो गया. कई कंपनियों को पिछले एक दशक से घाटा हो रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में कमी से पहले तक विमानन ईंधन की कीमत अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र की कंपनियों की हालत खराब रही.

परंजय गुहा ठाकुरता

साल 2012 में एयर इंडिया के कायाकल्प के लिए बनी योजना में पांच साल बचे होने के बावजूद इसका निजीकरण अभी क्यों किया जा रहा है?

2016-17 की आर्थिक समीक्षा में एयर इंडिया को हमेशा घाटे में रहने वाली सरकारी विमानन कंपनी बताया गया है. अब इसका निजीकरण किया जा रहा है. कैबिनेट ने नीति आयोग की सिफारिशों के तुरंत बाद इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. यह इस सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है कि सभी पक्षों से बात किए बगैर जल्दबाजी में निर्णय ले लिए जाएं. इसके खिलाफ एयर इंडिया कर्मचारी संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

दूसरी विमानन कंपनियों की तरह एयर इंडिया भी मुश्किल दौर से गुजर रही है. 2012 में इसके कायापलट के लिए 10 वर्षीय एक योजना बनी थी, जिसका क्रियान्वयन अब भी चल रहा है. उम्मीद से पहले यानि 2015-16 में एयर इंडिया ने परिचालन मुनाफा कमाना शुरू किया और इसके कुल घाटे में कमी आनी शुरू हो गई. सस्ती सेवाएं देने वाली इसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस तो फायदे में रही. 2016-17 में इन दोनों का प्रदर्शन बेहतर रहा. विमानन कंपनियों के लिए सीट भरने की क्षमता उनकी अच्छी सेहत के लिए बेहतर संकेत माना जाता है. पिछले पांच साल में एयर इंडिया की इस क्षमता में लगातार सुधार हुआ है. पिछले साल भारतीय विमानन क्षेत्र का प्रदर्शन कई कठिन वर्षों के बाद सुधरा है. माना जा रहा है जिस तरह का स्थिर विकास है, उस हिसाब से दशक के अंत तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा. उम्मीद का माहौल बना है. अनुमान है कि अगल साल तक घरेलू यात्रियों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी. इससे साफ है कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में विमानन क्षेत्र का भविष्य अधिक उज्जवल है. भारत में विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार सुधार के नाम पर महाराजा के साथ छल कर रही है.

सरकार हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि इसका निजीकरण इसलिए जरूरी था, क्योंकि एयर इंडिया की माली हालत बहुत खराब थी और यह कुप्रबंधन का शिकार है. लेकिन यह एक वैचारिक निर्णय है और इससे निजी विमानन कंपनियों को फायदा होगा. इससे न तो एयर इंडिया का भला होगा और न ही इसके कर्मचारियों का. यह विमानन क्षेत्र और यात्रियों के हित में भी नहीं है.

एयर इंडिया कोई अकेली विमानन कंपनी नहीं है, जिसकी स्थिति खराब है. निजी विमानन कंपनियों की हालत भी ठीक नहीं है. किंगफिशर एयरलाइंस भी ऐसा ही एक उदाहरण है. उदारीकरण के बाद कई कंपनियों ने काम शुरू किया. इनमें से 23 या तो बंद हो गए या उनका किसी दूसरी कंपनी में विलय हो गया. कई कंपनियों को पिछले एक दशक से घाटा हो रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में कमी से पहले तक विमानन ईंधन की कीमत अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र की कंपनियों की हालत खराब रही. यह सोचना अतिरेक है कि एयर इंडिया हमेशा घाटे में रही और कभी भी मुनाफे में नहीं आ सकती और यह कुप्रबंधन की वजह से है. कंपनी की खराब माली हालत की वजह से इस तरह की बातें प्रचारित की गईं. पिछले डेढ़ दशक में इस सरकारी कंपनी के लिए 111 विमानों की खरीदारी विवादित रही है और इसकी जांच चल रही है. साथ ही बगैर किसी योजना के 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय से जुड़े कई सवाल भी हैं. सरकार के इन दो निर्णयों से विलय के बाद की कंपनी का हाल बुरा रहा.

एयर इंडिया को बेचने से पहले सरकार को हर हाल में इसके कुल कर्ज के एक हिस्से से इसे मुक्त करना होगा. इसके कुछ कर्जों का निपटान इसकी संपत्तियों को बेचकर और कर्जों को पुनःसंगठित करके करना होगा. यह काम बगैर निजीकरण के भी किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी की परिचालन दक्षता सुधर रही है. साथ ही एयर इंडिया को अपने कर्जों को चुकाने का अवसर दिया जाना चाहिए. यह अवसर निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, जिनके पास बैंकों का सरकारी कंपनियों के मुकाबले अधिक कर्ज है. कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान एयर इंडिया ने एक हद तक कर लिया है, लेकिन सेवा और गुणवत्ता के मामले में और सुधार की जरूरत है. इस सरकारी विमानन कंपनी को अपने कर्मचारियों में और निवेश करना चाहिए ताकि उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके.

दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह भारत के विमानन बाजार में भी कुछ कंपनियों का दबदबा है. ऐसे में भारतीय बाजार में दूसरे या तीसरे नंबर की सरकारी विमानन कंपनी को बंद करने से निजी कंपनियों का दबदबा और बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी. एयर इंडिया के पास भारतीय कंपनियों के कुल विमानों में से 31 फीसदी विमान हैं और दुनिया के प्रमुख हवाई अड्डों से परिचालन के लिए सबसे अच्छे टाइम स्लॉट हैं. कुछ निजी कंपनियों के दबदबे वाले विमानन क्षेत्र में इस तरह की सरकारी कंपनी न सिर्फ जरूरी है, बल्कि अनिवार्य है.

महाराजा की अनावश्यक आलोचना के बजाय सरकार को इसे अपने कायाकल्प की योजना को लागू करने का अवसर देना चाहिए और जल्दबाजी में इसका निजीकरण नहीं करना चाहिए. ईंधन की कीमतों और दूसरे कारकों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पहले की तरह ही एक बार फिर एयर इंडिया सरकार के लिए मुनाफा कमाने वाली कंपनी साबित होगी.■

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीरी भाषा को पुनर्जीवन मिल गया है

शुजात बुखारी

कुछ हफ्ते पहले जम्मू और कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया. इसके तहत कश्मीरी, डोगरी और बोड़ी भाषाओं को कक्षा 9 और 10 में अनिवार्य विषयों के रूप में पढ़ाया जाएगा. कश्मीरी भाषा को पढ़ाने की मांग पूरी होने के साथ ही भाषा समर्थकों की एक लंबित मांग भी पूरी हो गई है.

राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होने के बावजूद 1953 में कश्मीरी भाषा को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था. यह उस वक्त हुआ था, जब कश्मीर के सबसे बड़े नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सरकार को अवैध तरीके से हटा कर जेल में बंद कर दिया गया था. एक लंबे समय से कश्मीर के निवासी इसकी मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि शेख साहब को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन कश्मीरी भाषा को सलाखों में अब भी रखा जा रहा है. इसे वापस लाने का फैसला पिछली सरकार द्वारा 2013 में स्थापित एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देश के कुछ और हिस्सों में भी भाषाओं की लड़ाई लड़ी जा रही है. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हाल में हुए उथल-पुथल का कारण भी भाषा ही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाले संभावित खतरों के बीच अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए बंगाली भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पेश किया था. इससे गोरखालैंड (दार्जीलिंग हिल्स के लोगों द्वारा प्रस्तावित राज्य) की मांग पुनर्जीवित हो गई क्योंकि वे इस भाषा को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं. इसके कारण 1980 से चला आ रहा आंदोलन और तीव्र हो गया.

इसी तरह, दक्षिणी भारतीय राज्यों में हिंदी का प्रतिरोध बहुत गहरा है, क्योंकि यहां विभिन्न समुदायों की पहचान भाषा से जुड़ी हुई है. दक्षिण भारत ने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के भाजपा के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है. इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान निर्माण के लिए भाषा अन्य कारकों के साथ एक प्रमुख कारण बना. कश्मीरी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पेश किए जाने से पाठ्यक्रम में आया एक बड़ा गैप भर गया है. कश्मीरी भाषा प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक अनिवार्य था और अन्य सभी विषयों की तरह ही कक्षा 10 के बाद एक वैकल्पिक विषय था. इस महत्वाकांक्षी संघर्ष के रास्ते में न केवल तकनीकी मुद्दे बल्कि नौकरशाहों के प्रतिरोध भी हुए, लेकिन मौजूदा शिक्षा मंत्री अल्ताफ बुखारी ने रास्ता निकाल ही लिया.

नौकरशाहों का पूर्वग्रह कश्मीरी भाषा को अपना सही स्थान देने में लंबे समय से आड़े आ रहा था. कश्मीर का सबसे पुराना, सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठन अदबी मरकज कमराज ने एक लंबे संघर्ष का नेतृत्व किया. इसके बाद साल 2000 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने स्कूलों में इसे फिर से शुरू किया था. सरकार और निजी स्कूल की कक्षाओं में इस भाषा को वापस लाने में एक दशक से अधिक समय लग गया, लेकिन यह तब भी 9 वीं और 10 वीं कक्षा में नहीं आ पाया था.

कश्मीरी जम्मू और कश्मीर राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. यह 22 जिलों में से 18 में बोली जाती है. यह पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में भी बोली जाती है. मुजफ्फराबाद के एजेके मेडिकल कॉलेज के एक संकाय सदस्य डॉ. मोहसिन शाकल की भाषा और साहित्य में रुचि है. उन्होंने एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक 14 अगस्त 1947 से पहले के राज्य में कश्मीरी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. 1947 से क्षेत्रीय भाषाई जनसांख्यिकी में बदलाव को देखते हुए डॉ. शकील जम्मू-कश्मीर में जिला स्तर पर स्वदेशी भाषा बोलने वालों की संख्या का अनुमान लगाना चाहते थे. एक अध्ययन के अनुसार, पहले के जम्मू-कश्मीर राज्य के लोग बहुसंख्यक समाज होने के कारण कई स्वदेशी भाषा से संबंधित हैं.

अपनी तरह का यह पहला स्टडी जून 2014 में सार्वजनिक किया गया. यह दर्शाता है कि कश्मीरी 35 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है. इसके बाद पहाड़ी/ पोथवारी (24 प्रतिशत) और डोगरी (18 प्रतिशत) है. सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रभाव से संभवतः क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों की संख्या में गिरावट आई है. आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा कश्मीरी पढ़ और लिख नहीं सकता था. अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा था.

कश्मीरी को 8 वीं कक्षा में पढ़ाए जाने के बाद से यह प्रवृत्ति अब बदल रही है. विडंबना यह है कि बच्चों को उस भाषा के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जो वास्तव में उनकी मातृभाषा है. उनके माता-पिता अपने अंग्रेजी और उर्दू कौशल को लेकर चिंतित रहते हैं. वे इस विश्वास के तहत परिश्रम करते हैं कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने और कुलीन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए यह आवश्यक है.

कश्मीरी के लिए असली चुनौती समाज से ही आती है. इसे पहचान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए. इसके लिए बच्चों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. यह प्रणाली ही ऐसी है, जो उन्हें अपनी भाषा को गले लगाने की इजाजत नहीं देती है. इस भाषा के पतन के लिए जिम्मेदार है बदलती शिक्षा प्रणाली की मांग, जो परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है. कश्मीरी भाषा के संघर्ष का यही कारण है.

कश्मीरी, जो इस क्षेत्र की सबसे पुरानी और सबसे अमीर भाषाओं में से एक है, को फास्सी और संस्कृत की बहन भाषा मानी जाती है. 14 वीं शताब्दी के कश्मीरी संत और कवि लाल देद अपनी कविता के लिए कश्मीरी भाषा के लिखित शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे. उनके बाद कश्मीरी संत शेख-उल-आलम थे. लेकिन कश्मीरी एक भाषा के तौर पर बहुत पहले से अस्तित्व में थी. इतिहासकार मानते हैं कि यह 2000 वर्ष पुरानी भाषा है और इसकी लिपि 900 वर्ष पुरानी है. यह इसे दक्षिण एशिया की कई लोकप्रिय भाषाओं (उर्दू, हिन्दी) की तुलना में पुराना बनाता है. विख्यात साहित्यकार मोहम्मद यूसुफ टैंग के अनुसार, कश्मीरी भाषा के निशान 400 ई.पू. तक मिलते हैं और यह चरक-संहिता में भी पाई जाती है. यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा का एक व्यापक पाठ है, जिसका श्रेय चरक को दिया जाता है.

कश्मीरी शब्द राजतरंगिनी (रिवर ऑफ किंग) में भी मिलता है जिसे 1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखा गया था. यह कश्मीर के इतिहास को अपने में समेटे हुए है. यह अपनी तरह का सबसे बेहतर और प्रामाणिक काम माना गया है. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक, यह किताब कश्मीर के इतिहास के पूरे दौर को अपने में समेटे हुए है.

उस खतरे को समझना महत्वपूर्ण है, जो 2500 से अधिक भाषाओं के सामने है. यूनेस्को द्वारा 2009 में पेरिस मुख्यालय से जारी दुनिया की लुप्तप्राय भाषाओं के व्यापक डेटाबेस में इस मुद्दे को रेखांकित किया गया है. विशेषज्ञों की टीम के अनुसार, 2500 भाषाएं खतरे में हैं, जिनमें 500 से अधिक तकरीबन लुप्तप्राय हैं. इनमें 199 ऐसी भाषाएं हैं, जिसे बोलने वालों की संख्या 10 से भी कम है. यह आश्चर्यजनक है कि इक्वाडोर के अंडोवा भाषा को बोलने वालों की संख्या केवल 10 है. हाल में स्थानीय लोगों द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया है. अब तक उन्होंने लगभग 150 शब्द इकट्ठे किए हैं और शब्दों की तलाश जारी है. एक और चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि दुनिया भर में एक दर्जन से अधिक भाषाओं के पास केवल एक मातृभाषा बोलने वाले ही हैं. कुछ भाषाएं जल्द ही मरेंगी, जबकि अन्य को फिर से जीवित करने के लिए युवा पीढ़ी उत्सुक है.

9 वीं और 10 वीं कक्षा में कश्मीरी भाषा लाए जाने से यह उम्मीद की जा रही है कि कश्मीरी भाषा का विकास होगा. चुनौतियां फिर भी रहेंगी, लेकिन मौजूदा कदम अपने प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा.■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

वर्तमान माहौल से गुस्से में हैं सेना के परिजन

मेरी मुलाकात भारतीय सेना के एक जांबाज अधिकारी की पत्नी से हुई. उसने अपना एक अलग दर्द मेरे सामने रखा. मैं आपके साथ उसे इसलिए बांटना चाहता हूं, ताकि आज देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, आप कम से कम इतना महसूस कर सकें कि वो माहौल सेना के अफसरों के परिवारों को कितना डरा रहा है. हमारे देश में सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल का अगर वश चले, तो कल ये पाकिस्तान से युद्ध कर लें और ज्यादा वश चले तो कल ये चीन के ऊपर हमला कर दें. उनकी नजर में हम अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं. हमारे आंख दिखाने भर से चीन खामोश हो जाएगा और पाकिस्तान डर कर चादर तान कर सो जाएगा. हो सकता है ऐसा हो या काश ऐसा होता, पर सेना के इस बहादुर अधिकारी की पत्नी ने जो कहा, वो इन सबसे अलग है.

उसने कहा कि जब मैं सोशल मीडिया देखती हूं और जब टेलीविजन चैनल की बहस सुनती हूं, तब बहुत डर जाती हूं. इसके बाद जब सोचती हूं कि अगर युद्ध हुआ तो मेरे पति को भी मोर्चे पर जाना पड़ सकता है, वो लौटेगा या नहीं, इसे लेकर मेरे मन में संशय है. मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही हूं कि पाकिस्तान और चीन की सीमा पर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई, जिसे बातचीत से हल नहीं किया जा सकता. अगर राजनीतिज्ञ असफल हो रहे हैं, तो उसका कारण देश को पता चलना चाहिए. क्या उनमें बातचीत करने की क्षमता नहीं है, उनकी बातचीत में तर्क नहीं है या वो विश्व जनमत को अपने पक्ष में नहीं ला सकते हैं. इस बहादुर महिला का एक ही बेटा है और वो अपना बेटा भी सेना में भेजना चाहती है. उसके पति भी सेना में हैं. उसके पिता भी सेना के अधिकारी रहे हैं. उसके रिश्तेदार भी सेना में हैं. इस महिला के मन में सवाल घुमड़ रहा है कि हम राजनीति के जरिए सीमा के जिन सवालों को हल कर सकते हैं, कूटनीति के जरिए विश्व जनमत अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम देश में ये झूठा वातावरण क्यों बना रहे हैं कि सारी दुनिया हमारे साथ है और हमने पाकिस्तान और चीन को अलग-थलग कर दिया है. उसका कहना है कि अगर देश की आन पर कोई बात आ जाए, तो सेना का एक-एक सिपाही सीमा पर जाने के लिए तैयार है. लेकिन देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उससे सेना के सिपाही और अधिकारी काफी गुस्से में हैं.

उसने मुझसे सवाल किया कि आप एक अखबार में काम करते हैं. क्या आप मेरी तरफ से देश के लोगों से ये पूछ सकते हैं कि कारगिल में हुए शहीदों के नाम किसी को याद हैं? क्या आप लोगों से ईमानदारी से ये सवाल कर सकते हैं? वो ईमानदारी से यह बताएं कि वो कितने शहीदों के घर साल में एक बार भी जाते हैं? क्या आप ये मेरी तरफ से लोगों से पूछ सकते हैं कि जब होली, दिवाली होती है, जब हम खुशियों में नाचते-गाते हैं या 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाते हैं, तो हम कितने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हैं? वो चाहे कारगिल के शहीद रहे हों या फिर आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए हों, क्या उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान है कि उनके परिवार किस हालात में जी रहे हैं? उसने मुझसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि शहीद के परिवारों की उनके गांव में क्या हालत है? उनकी जमीन पर किसने कब्जा कर लिया है? जब वो पुलिस थाने जाते हैं, तो उनका किस तरह से अपमान होता है? उनसे कहा जाता है कि साला, मरने वाला तो मर गया, बवाल छोड़ गया. हमारे शहीदों के साथ जो हो रहा है, सोशल मीडिया पर जैसा माहौल बनाया जा रहा है, इससे हमारे सेना के परिवारों को क्या संदेश मिलता है? सैनिक अधिकारी की इस पत्नी ने मुझसे ये भी सवाल पूछा कि कारगिल के शहीदों का नाम मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो सबसे ताजा उदाहरण हैं. भारत-पाक के बीच 1965 और 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूं, क्योंकि वो लोग हमारे तथाकथित देशप्रेमियों के अत्याचारों से इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं कि वो अब अपनी बात ही नहीं कहते. जगह-जगह ऐसे किस्सों की भरमार है कि कारगिल में शहीद हुए परिवार अपने ही समाज की प्रताड़ना झेल रहे हैं. उनमें से बहुतों का ये भी कहना है कि काश हम देशप्रेम में इतने अंधे नहीं हुए होते. अब मैं आप पाठकों से यह पूछना चाहता हूं कि इस सैन्य अधिकारी की पत्नी का दर्द क्या आपके पास तक पहुंच पा रहा है? क्या आप भी अपने आस-पास किसी शहीद के परिवार के साथ समाज, पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को देखकर अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं. लेकिन ऐसा हो रहा है.

इस बहादुर सैनिक अधिकारी की पत्नी ने मुझसे एक सवाल और पूछा. उसने कहा कि इस समय देश में गायों की रक्षा के नाम पर जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा-पीटा जा रहा है, क्या इन लोगों की पहचान भारत के प्रधानमंत्री जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उससे हो सकती है? प्रधानमंत्री की भाषा पर राज्य सरकारें गोरक्षा के नाम पर अपराधवृत्ति करने वाले लोगों को रोकने का काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या इसलिए कि राज्य सरकारें जानती हैं कि प्रधानमंत्री ये सिर्फ कह रहे हैं, करने के लिए नहीं कह रहे हैं. करने वाली भाषा वो होती है, जो नोटबंदी में इस्तेमाल की गई थी. करने वाली भाषा वो होती है, जो जीएसटी में की गई. करने वाली भाषा वो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेशों और चिंताओं को अनदेखा कर आधार कार्ड में इस्तेमाल की गई. पर ऐसा क्या कमाल है या इस भाषा में ऐसी कौन सी कमजोरी है कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद गोरक्षा के नाम पर अपराधवृत्ति करने वाले लोग डर नहीं रहे हैं.

इस महिला ने ये भी पूछा कि ये लोग गोरक्षा के नाम पर सड़क पर किसी को भी पकड़कर मार-पीट रहे हैं. लोगों के घरों में घुसकर जवान लड़कियों के पहनावे को लेकर बेइज्जत कर रहे हैं. ये गाय की रक्षा के नाम पर आंदोलन करने वाले या समाज को बांटने वाले लोग, क्या इस देश में मां-बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक पा रहे हैं? जो अपनी मां-बहनों पर होने वाले अत्याचार को न रोक पाए और गाय की रक्षा के नाम पर सड़क पर निकलकर फुफकार भरे, उससे ज्यादा नकली देशप्रेमी कोई हो नहीं सकता. इसमें मैंने एक चीज और कही कि सारे तथाकथित देश-प्रेमी जो शहीद हुए हैं, उनके घर तो जाते ही नहीं हैं. जो सेना के सिपाही अभी जीवित हैं और सेना में हैं और देश में कहां उनकी ड्यूटी लगी होगी, उनके घर वाले भी नहीं जानते, जो बॉर्डर पर हैं चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चीन का, क्या इनमें से कोई उनके घरों पर ये जाकर पूछता है कि तुम्हारे घर की समस्या क्या है? तुम्हारे बच्चे स्कूल में हैं, उनकी फीस समय पर जा रही है. तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी तो परेशान नहीं कर रहा है. तुम्हारी जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है. तुम्हारी बहनों और पत्नियों को कोई छेड़ तो नहीं रहा है. सैन्य अधिकारी की इस महिला ने कहा कि मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला, जहां लोगों ने कहा हो कि समाज की तरफ से हमें यह सहयोग मिल रहा है. बहुत सारी जगहों पर जिला प्रशासन, सेना में काम करने वाले मौजूदा सिपाहियों के घरवालों की समस्याओं को इसलिए हल नहीं करते क्योंकि वो घूस नहीं दे पाते. पुलिस अधिकारी उन्हें निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं. अब तो अखबारों में भी खबरें आने लगी हैं कि पुलिस के लोग सैन्य अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं?

ये सवाल मुझे झिंझोड़ गया. जब मैंने अपने स्तर पर पता किया, तो इस बहादुर सैन्य अधिकारी, जिसे सेना के कई मेडल मिल चुके हैं, की पत्नी की बातों में मुझे 99 प्रतिशत सच्चाई मिली. मैं आपसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं, जो समाज नकली देशप्रेम में पागल हो रहा है और जो सचमुच देशभक्त हैं, जो शहीद हुए हैं या जो शहीद होने के रास्ते पर हैं, उन्हें अनदेखा कर रहा है. यह हमारे ही देश में हो सकता है. उस देश में, जहां सेना की बहादुरी भी राजनीति का एक हिस्सा बन जाती है. इस बहादुर महिला ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे सवाल आपको पसंद नहीं आएंगे. आप सोचेंगे कि मैं बुजदिली की बात कर रही हूं, लेकिन मैं ये सवाल करती हूं कि आपके परिवार के कितने लोग सेना में हैं. जिनके परिवार सेना में हैं, उनके परिवारों से पूछिए कि उन्हें नकली देशप्रेम सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि अगर युद्ध चुनाव जीतने के लिए हो या अगर युद्ध अपने अहम को तुष्ट करने के लिए हो, तो ऐसे माहौल में जब लाशें घर में आती हैं तो घरवालों को सिर्फ राजनीतिज्ञों के चेहरे याद आते हैं. उन्हें लगता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई और हमारा पति राजनीतिज्ञों की असफलता की वजह से शहीद हुआ है. युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए, पर हमारे देश में युद्ध पहला रास्ता बना दिया गया है. इसके उदाहरण देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ टीवी चैनलों की बहसों और सोशल मीडिया में चल रहे झूठ, फेक न्यूज और पागलपन के उफान को देखना भर पर्याप्त है.

मैं सांस रोककर इन सारी बातों को सुनता रहा. मुझे लगता है कि आप उनके साहस को सलाम करेंगे कि वो इतना सोचती हैं. वो सामाजिक रूप से सेना के सिपाहियों और अधिकारियों के बीच काम कर रहे सैनिक पत्नियों के एक बड़े दस्ते का हिस्सा है. उसने जो कहा, अगर उसका एक हिस्सा भी आप कर सकें, तो आप सचमुच देशप्रेमी कहलाने के लायक हैं. कारगिल में जो शहीद हुए, कारगिल में जो अपंग हुए या उसके बाद कश्मीर में शहीद होने वाले परिवारों के प्रति सिर्फ दिखावे की संवेदना मत जताइए, बल्कि उनके घर जाकर ये देखिए कि वो किस स्थिति में जी रहे हैं. अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो फौरन मदद कीजिए. उन नकली देशप्रेमियों की तरह अपने चेहरे को क्रूर मत बनाइए, जो इनकी शहादत की भावना का देशप्रेम के नाम पर अपमान करते है. उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके परिवार की बीमारी में उनका साथ, सरकारी अधिकारियों के ऊपर दबाव कि उनकी समस्याओं का हल निकालें और साथ ही पुलिस अधिकारियों में ये डर पैदा कीजिए कि वो किसी भी सेना के सिपाही के परिवार को, चाहे वो शहीद का परिवार हो या इस समय सेना में काम करने वाले किसी सैनिक का परिवार हो, उसके प्रति अपमानजनक व लज्जाजनक व्यवहार करने की हिम्मत न करे. क्या मेरी इतनी सी बात आप मानेंगे? सिर्फ वो नहीं मानेंगे, जो नकली देशप्रेमी हैं. जो अपने मां और पिता की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, लेकिन वो गाय के नाम पर सड़क पर शुद्ध आपराधिक कृत्यों का नेतृत्व करते हैं. लेकिन जो सचमुच भारत को प्यार करते हैं, उन लोगों के पास मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कृपा कर शहीदों के परिवारों और सेना में काम करने वाले परिवारों को अपना परिवार मानिए. उस घर की बहन-बेटियों को अपनी बहन-बेटियां मानिए और उनकी रक्षा समाज के अपराधी तत्वों से कीजिए, जिनमें अधिकांश वो लोग हैं, जो आज सड़क पर अपराध का नंगा नाच कर रहे हैं.■

editor@chauthiduniya.com

मायावती का इस्तीफ़ा दलित-हित या हताशा

एसआर दारापुरी

मायावती ने राज्यसभा में दलित मुद्दों पर बयान देने के लिए अधिक समय न दिए जाने पर पिछले दिनों सदन से इस्तीफा दे दिया, जो एक-दो दिन उपराष्ट्रपति के पास विचाराधीन रहा, बाद में उसे स्वीकार कर लिया गया. मायावती ने बाद में अपने बयान में कहा कि दलित उत्पीड़न, खास तौर पर सहारनपुर दलित उत्पीड़न कांड पर उन्हें सदन में पूरा बोलने नहीं दिया गया. इससे दुखी होकर वे इस्तीफा दे रही हैं. मायावती के इस तरह नाटकीय ढंग से इस्तीफे देने के कई निहितार्थ हैं, जिन पर विस्तार से चर्चा करने और यह देखने की जरूरत है कि मायावती ने क्या वास्तव में दलित हित में इस्तीफा दिया है या उसके पीछे दूसरे कारण हैं.

उल्लेखनीय है कि मायावती की राज्यसभा की सदस्यता नौ माह बाद वैसे ही समाप्त हो रही है. उनके दोबारा चुने जाने की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के केवल 19 सदस्य हैं, ये संख्या राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए पर्याप्त नहीं है. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मायावती ने केवल दलित वोटरों को प्रभावित करने के लिए दलित मुद्दों का बहाना बना कर इस्तीफा दिया है. वे भली प्रकार जानती हैं कि दलित हितों की उपेक्षा के कारण ही उनका दलित वोट बैंक बुरी तरह से खिसक चुका है. 2012 से लेकर 2017 तक के चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट है. लिहाजा, मायावती का इस तरह नाटकीय ढंग से इस्तीफा देना उनकी हताशा का प्रतीक है.

अब सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि क्या मायावती दलित उत्पीड़न या दलित हितों के प्रति इतनी संवेदनशील रही हैं, जैसा वे इस समय दिखाने की कोशिश कर रही हैं? आइए सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर दलित उत्पीड़न के प्रति मायावती की संवेदनशीलता का जायजा लें. क्या यह एक चिंताजनक ऐतिहासिक परिघटना नहीं है कि दलित उत्पीड़न से सम्बंधित एससी/एसटी एक्ट को लागू करने पर वर्ष 2001 में मायावती ने रोक लगा दी थी? वर्ष 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द होने के बाद वह फैसला रुका. क्या ऐसी रोक लगाने की उम्मीद कोई किसी दलित मुख्यमंत्री से कर सकता है? परन्तु मायावती ने ऐसा किया. इस रोक का दलितों को बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ा. इससे एक तो दलित उत्पीड़न के मामले इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज नहीं हो सके और दूसरा, दलितों को इस एक्ट के अंतर्गत मिलने वाला मुआवजा नहीं मिल सका. इस प्रकार मायावती के इस कुकृत्य से दलितों को दोहरी मार का शिकार होना पड़ा.

इसके अतिरिक्त, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मायावती अपराध के आंकड़े कम करने पर बहुत जोर देती थीं. आंकड़े बढ़ने पर वे अधिकारियों को सस्पेंड या उनका तबादला कर देती थीं. इसका खामियाजा भी दलितों को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि अपराध के आंकड़े कम रखने के लिए पुलिस दलितों पर हुए अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करती थी. इसके इलावा मायावती को बदनामी से बचाने के लिए बसपा कार्यकर्ता भी अपराध दर्ज न करने पर जोर देते थे. समाचार पत्रों से उपलब्ध सूचना और अध्ययन के अनुसार वर्ष 2007 में दलित उत्पीड़न के 60 प्रतिशत अपराध दर्ज ही नहीं किए गए थे. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती दलित उत्पीड़न के प्रति कितनी संवेदनशील रही हैं.

पिछले कुछ वर्षों में दलित उत्पीड़न के कुछ बड़े मामले देखें, तो पाएंगे कि इन मामलों में मायावती की प्रतिक्रिया अत्यंत मामूली रही है. हैदराबाद में रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या को लेकर मायावती हैदराबाद नहीं गईं और उन्होंने केवल राज्यसभा में बयान देकर रस्म अदायगी कर दी. इसी तरह ऊना दलित उत्पीड़न के मामले में मायावती वहां गईं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत सतही रही. सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में वे घटना के 18 दिन बाद 23 मई को शब्बीरपुर गईं, वो भी तब जब उन्हें भीम सेना के पक्ष में उमड़ी भीड़ से लगा कि उनका वोट बैंक और खिसक गया है. वहां पर भी मायावती केवल समरसता बनाए रखने का संदेश देकर लौट आईं. इतना ही नहीं, उन्होंने लखनऊ आकर सहारनपुर के दलितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाली भीम सेना के विरोध में बयान दिया और उसे भाजपा की उपज कहा. उन्होंने भीम आर्मी पर बसपा के नाम पर चंदा इकठ्ठा करने का आरोप भी लगाया. पूर्व में भी मायावती आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत करती रही हैं. इसके अलावा वे भी पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की पक्षधर रही हैं. उन्होंने इस सम्बंध में विधानसभा से बिल पारित करा कर केंद्र सरकार को भेजा भी था. मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए पांच सालों (2007-12) में अनुसूचित जातियों की पदोन्नति में आरक्षण की बहाली हेतु इलाहबाद हाईकोर्ट में वांछित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए और कोर्ट में उचित पैरवी नहीं की, जिसके कारण हजारों दलित अधिकारियों को पदावनत होना पड़ा. इस दलित-त्रासदी के लिए मायावती जिम्मेदार हैं. मायावती ने कांशीराम के प्रयासों से बनाई गई फिल्म 'तीसरी आज़ादी' और रमास्वामी नायकर द्वारा लिखी पुस्तक 'सच्ची रामायण' को प्रतिबंधित कर दिया था, जो आज तक जारी है. उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज में दलितों के आरक्षण का प्रावधान रद्द कर दिया था. इसके अलावा उन्होंने सरकारी विद्यालयों में दलित रसोईयों की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया था. इससे विद्यालयों में दलित रसोईयों की नियुक्तियां बंद हो गईं और सरकारी स्कूलों में छुआछूत को बढ़ावा मिला. मायावती ने दलितों के आवास की भूमि को उनके पक्ष में नियमित किए जाने के आदेश को यह कह कर रद्द कर दिया था कि सम्बंधित अधिकारी ने उनसे धोखे से दस्तखत करवा लिए थे. उन्होंने 2007 में अंबेडकर महासभा के कार्यालय भवन का आवंटन रद्द करके उसे मंत्री आवास के लिए आवंटित कर दिया था, जो इलाहबाद हाईकोर्ट के स्टे से रोका जा सका. मायावती ने वर्ष 2008 में लागू वनाधिकार कानून के अंतर्गत वनवासियों और आदिवासियों को भूमि का मालिकाना अधिकार देने के बजाए उनके 81 प्रतिशत दावों को रद्द कर दिया था. इस वजह से आदिवासियों को उनके कब्ज़े की ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका. बाद में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिवासियों के हित का आदेश जारी किया. यह मायावती का अजीबोगरीब दलित प्रेम है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के महज दो फीसदी आदिवासियों के लिए विधानसभा की दो सीटें आरक्षित करने संबंधी बिल का विरोध किया था. इस कारण 2012 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों को कोई भी सीट नहीं मिल सकी थी. 2017 के चुनाव में आदिवासियों के लिए दो सीटें आरक्षित हो पाईं.

मायावती के चार बार के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके छद्म दलित प्रेम के ये कुछ नायाब उदहारण हैं. इस दरम्यान दलित हितों की घोर उपेक्षा हुई और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका. इसके विपरीत मायावती के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के कारण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी दलित आंशिक तौर पर ही लाभान्वित हो सके. अब नाटकीय तरीके से इस्तीफा दे कर मायावती दलित हितैषी होने का जो स्वांग कर रही हैं, उसे दलित समुदाय अच्छी तरह समझता है.■

(लेखक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं)

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का कबाड़ा

नरक भोग रहा बनारस

अंबरीश बनारसी

बाबा विश्वनाथ का नगर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, इन दो प्रसिद्धियों की सुखानुभूति से ओतप्रोत बनारस नर्कवास भोग रहा है. प्रधानमंत्री बनने के क्रम में और बनने के बाद जो योजनाएं वादे की तरह झोंकी गईं, वे आज कूड़े के अंबार की तरह बनारस को गंदा कर रही हैं. आप बनारस आएं तो आपको यहां के नर्क में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की प्रसिद्धि की असलियत दिखाई पड़ेगी, आप उसे भोग कर भी जाएंगे. आप अभी की बरसात में आएंगे, तो नरक का अलग दृश्य है. कुछ दिन पहले की असह्य गर्मी के दरम्यान आते, तो नरक का सीन कुछ और होता. गंगा के शुद्धिकरण से लेकर मोदी-उत्तार्ध की तमाम योजनाओं का जायजा लें, तो वे सब की सब नौकरशाही के गंदे आसनों के नीचे फंसी दिखाई देंगी. पहले तो हम सतह पर दिख रही गंदगी का विस्तार से जायजा लें, इसके बाद सतह के नीचे की गंदगी झांकेंगे.

अभी बारिश का समय है. प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र फिलहाल तालाब बना हुआ है. जो अभी बनारस आएंगे उन्हें तालाब के नीचे की दुर्दशा पानी सूखने के बाद दिखेगी. जो यहीं के हैं, वे तो सतह के ऊपर और सतह के नीचे, दोनों की दुर्दशा जानते हैं. बनारस में नगर निगम का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है. बनारस के लोग गर्मी में चाहे जितना उबलें, लेकिन बारिश के नाम से भयाक्रांत होने लगते हैं. यह भाव मोदी के चुनाव जीतने के बाद भी यथावत कायम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवींद्रपुरी में संसदीय दफ्तर है. थोड़ी भी बरसात हो, तो रवींद्रपुरी अलग ही गंदी गंगा बन जाती है. नई सड़क और गिरजाघर रोड जैसे व्यस्त इलाके घंटों जाम में त्राहिमाम रहते हैं. उसमें बारिश हो जाए तो जाम और लोगों की परेशानी का दर्दनाक मंजर दिखाई पड़ता है. बनारस के मशहूर सिगरा-महमूरगंज रोड की तो पूछिए मत. सावन के महीने में कांवरियों को यही सड़क बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचाती है, लेकिन बारिश में इतना पानी जमा हो जाता है कि उसमें गाड़ियां तक डूब जाती हैं. यहां के बारे में कहा जाता है कि बादल घिरते ही यहां के लोग अपने वाहनों को सुरक्षित जगह पार्क कर देते हैं. अभी कांवरियों से पूछें तो उनका दर्द महसूस होता है. पुलिस लाइन जाने वाली पांडेयपुर रोड वीवीआईपी सड़क मानी जाती है. वीवीआईपी आवागमन के कारण आए दिन यहां सड़कें बनती हुई दिखती हैं, लेकिन बारिश आई तो सड़क का सत्यानाश हो जाता है. इलाके में नालियां ही नहीं हैं तो पानी कहां जाए, इसलिए पानी जमा ही रहता है. पुलिस लाइन गेट से पांडेयपुर फ्लाई-ओवर के नीचे से गुजरने वाली सड़क आपको दिखेगी कैसे, वहां तो बारिश का पानी नदी की तरह बहता रहता है. बनारस के केंद्र में स्थित बेनियाबाग इलाके से रोजाना लाखों लोग निकलते हैं. बेनियाबाग रोड से ही लोग दशाश्वमेघ घाट, बाबा विश्वनाथ मंदिर और कई दूसरे पर्यटन स्थलों पर जाते हैं. यहां का आलम यह है कि बारिश के बाद सड़क से लेकर दुकान तक पानी भर जाता है. बारिश आते ही पूरे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल बन जाता है. बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी निकलने में कई-कई घंटे लगते हैं. इस दौरान जाम का नारकीय दृश्य बनारस के लोगों को रुलाता है.

बनारस के लोगों से बारिश के पहले के दृश्य के बारे में पूछें, तो लोग कहते मिलेंगे कि कम से कम बारिश में वह गंदगी तो नहीं दिखती, जो पहले दिखती है. सड़कों और खड्डों में जो लोग डूब रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं, उससे पानी के नीचे के नीच यथार्थ का पता चलता है. पहले से प्रशासन को कहा जा रहा था कि जिस तरह सड़कें खुदी पड़ी हैं और पूरा बनारस पहले धूल में भरा और थोड़ी भी बूंदा-बांदी में कीचड़ बनजा रहा है, बारिश आने के बाद इसका क्या होगा. लोगों को क्या पता कि अधिकारी इसी बारिश का इंतजार करते हैं, अपने भ्रष्टाचार का कीचड़ साफ करने के लिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिए जाने की बात कही थी. योगी ने शायद आने वाली बारिश को अंदाज कर ही यह बात कही होगी, क्योंकि बारिश आई तो सारे गड्ढे पानी से भर गए. पानी के नीचे सड़कों का हाल बद से बदतर है और लोग किसी तरह गिरते-पड़ते जैसे-तैसे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं. बारिश आने के ऐन पहले बनारस के लोगों को लगा कि अचानक विकास के काम तेजी से शुरू हो गए हैं. हर तरफ निर्माण कार्य चल रहा है. ज्यादातर जगहों पर आईपीडीएस का काम चल रहा था. शहर की गलियों से लेकर मुख्य मार्ग तक हर तरफ आईपीडीएस ने सड़कें खोद डाली थीं. कदम-कदम पर गड्ढे थे. आईपीडीएस को लगातार यह हिदायत दी जा रही थी कि बारिश के पहले सड़कों को समतल कर दिया जाए. लेकिन यह हिदायत बरसात के साथ ही बह गई. विकास के वही गड्ढे आज लोगों की जान ले रहे हैं. गिरजाघर चौराहे से गोदौलिया जाने वाले मार्ग पर आईपीडीएस का काम चल रहा था. यहां दूध-सट्टी के सामने कई फीट तक गहरी खोदाई हुई थी. इसके चलते पूरी लेन भी बंद कर दी गई थी. गिरजाघर से रेवड़ी तालाब होते भेलूपुर जाने वाले मार्ग की हालत यह है कि पैदल चलना भी मुश्किल है. जयनारायण इंटर कॉलेज से आगे बढ़ते ही जो नरक का आलम शुरू होता है वह भेलूपुर थाने तक बदस्तूर जारी रहता है. महज आठ सौ मीटर लंबी सड़क की मरम्मत आइपीडीएस योजना के काम के चलते नहीं हो पाई. इसी दरम्यान रेवड़ी से भेलूपुर चौराहे के बीच शाही नाले की सफाई को लेकर भी काम शुरू कर दिया गया. काम पूरा तो नहीं ही हुआ, गहरे गड्ढे बन गए और जहां-तहां मिट्टी के ढूहबन गए. अब बारिश में वही गड्ढे मौत की खाई बन गए हैं.

रेवड़ी तालाब से चंद कदम दूर ही प्रसिद्ध तिलभांडेश्वर मंदिर है. इसी रास्ते से लोग दुर्गाकुंड और बीएचयू जाते हैं. लेकिन मार्ग की हालत इस कदर खराब है कि बीएचयू और दुर्गाकुंड का आवागमन तो दूर, लोगों के लिए तिलभांडेश्वर का दर्शन करना भी मुश्किल हो रहा है. बारिश ने निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं की करतूतें भी उजागर कर दी हैं. दुर्गाकुंड तालाब से रवींद्रपुरी एक्सटेंशन और अस्सी चौराहे से अस्सी घाट तक लगभग साढ़े आठ सौ मीटर लंबी सड़क का अधिकतर हिस्सा 20 मई तक बन चुका था. दुर्गाकुंड के पास की सड़क का काम भी मुख्यमंत्री योगी के दौरे के एक दिन पहले पूरा किया गया. लेकिन एक ही बारिश में यह सड़क उखड़-पुखड़ कर चौपट हो गई. कमच्छा तिराहे से शंकुलधारा जाने वाले मार्ग को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है. यह सड़क पिछले कुछ अर्से में कितनी बार खोदी जा चुकी है, यह स्थानीय लोगों को याद भी नहीं रहा. आज यह सड़क नारकीय बनी हुई है. कमच्छा तिराहे से गुरुबाग आने वाले मार्ग का भी कोई पुरसाहाल नहीं. यहां भी आईपीडीएस का काम महीनों से चल रहा है. खोदाई के कारण कमच्छा तिराहे से निमिया माई मंदिर तक बुरा हाल है. गुरुबाग तिराहे पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. ये गड्ढे इतने खतरनाक हैं कि इनके कारण रोजाना दुर्घटना होती रहती है. रथयात्रा से गुरुबाग होते हुए कमच्छा-भेलूपुर जाने वाली रोड शहर की व्यस्ततम सड़कों में शुमार है. रथयात्रा से कमच्छा जाने के लिए यह अकेली सड़क है. सभी तरह के वाहनों मसलन, नगर बस, लग्जरी वाहन, दूर एंड ट्रेवल्स की बसें, स्कूल बसें, टेम्पो, रिक्शा और निजी चार पहिया वाहनों को रथयात्रा चौराहे से गुरुबाग की ओर मोड़ दिया जाता है. गुरुबाग गुरुद्वारे से मुड़ कर ये सारे वाहन कमच्छा की ओर जाते हैं. स्थिति यह रहती है कि गुरुबाग तिराहे पर गुरुद्वारे के सामने से लेकर काफी दूर तक लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल रहता है. कदम-कदम पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. गुरुबाग तिराहे से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर गुरुनानक खालसा बालिका विद्यालय है. उससे कुछ ही दूरी पर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है. वही सड़क वसंत कन्या इंटर कॉलेज की ओर जाती है. इससे आगे सेंट्रल हिंदू ब्वॉयज स्कूल है. वहीं से रास्ता रुक्मिणी संस्कृत विद्यालय की ओर भी जाता है. सेंट्रल हिंदू ब्वॉयज स्कूल से आगे बढ़ें, तो चिल्ड्रेन्स एकेडमी है. उससे आगे सीएम ऐंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज है. रथयात्रा से गुरुबाग की ओर चलें, तो वसंत कन्या महाविद्यालय है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का दूसरा द्वार है. इन सभी स्कूल-कॉलेजों के बच्चे गर्मी में भी यंत्रणा सहते हैं और बरसात में तो जान हथेली पर लेकर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं. यह सरकार और प्रशासन को नहीं दिखता. गुरुबाग सीबीएसई की किताबों का सबसे बड़ा बाजार है. किताबों की खरीद-फरोख्त के लिए यहां रोजाना छात्रों और अभिभावकों की भीड़ लगी रहती है. बच्चों के अभिभावक यहां के गड्ढों में जमा सीवर के पानी से तर-बतर होते रहते हैं. इसी मार्ग पर रेडीमेड कपड़ों और जूते चप्पल की भी मार्केट है. पूरे इलाके में ऐसी बदबू बनी रहती है कि नाक पर कपड़ा रखे बगैर वहां कुछ सेकेंड भी आप खड़े नहीं रह सकते. न नगर निगम को इसकी परवाह है और न जिला प्रशासन को. एकल मार्ग होने के चलते इस तिराहे पर सुबह से देर रात तक जाम लगा रहता है. रात में नो-इंट्री खुलने के बाद ट्रकों और ट्रैक्टरों का रेला लग जाता है. देर रात को भी यहां जाम की स्थिति बनी रहती है. कहीं कोई ट्रैफिक पुलिसवाला भी नहीं दिखता.

लब्बोलुबाब यह है कि बनारस की बदहाली अपनी जगह बदस्तूर कायम है. बनारस की सड़कें जाम की समस्या से शाश्वत जूझ रही हैं. हर जगह कूड़े के अम्बार यथावत हैं. बनारस में हर दिन तकरीबन 600 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है. कूड़े के निस्तारण का दावा किया जाता है, लेकिन हर जगह फैली गंदगी बताती है कि निस्तारण की बातें फर्जी हैं. गंगा आज भी उतनी ही मैली है. गंगा के दरकते घाट दरकते बनारस का यथार्थ हैं. झूठे सियासतदानों और नकारे नौकरशाहों के कारण बनारस की समस्याओं की फेहरिस्त लंबी चौड़ी और भारी होती चली जा रही है. बनारस की हवा जहरीली हो चुकी है. बनारस की सड़कें धूल के गुबार के बीच बमुश्किल दिखाई पड़ती हैं. वायु प्रदूषण चरम पर है. पूरे शहर पर धूल के कण छाए रह ते हैं, बारिश आती है, तो इसे धो देती है, लेकिन इस धुलाई में भ्रष्टाचार और जन-उपेक्षा के दुर्ग भी साफ-साफ नजर आने लगते हैं.

(शेष पृष्ठ 11 पर)

गंगा आज भी उतनी ही मैली है. गंगा के दरकते घाट दरकते बनारस का यथार्थ हैं. झूठे सियासतदानों और नकारे नौकरशाहों के कारण बनारस की समस्याओं की फेहरिस्त लंबी चौड़ी और भारी होती चली जा रही है. बनारस की हवा जहरीली हो चुकी है. बनारस की सड़कें धूल के गुबार के बीच बमुश्किल दिखाई पड़ती हैं. वायु प्रदूषण चरम पर है. पूरे शहर पर धूल के कण छाए रहते हैं, बारिश आती है, तो इसे धो देती है, लेकिन इस धुलाई में भ्रष्टाचार और जन-उपेक्षा के दुर्ग भी साफ-साफ नजर आने लगते हैं.

नरक भोग रहा बनारस

पृष्ठ 10 का शेष

ढुलमुल विकास का उदाहरण बन रहा है सामने-घाट पुल

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में विकास की असलियत तो आपने ऊपर देखी ही. अब देखिए योजनाओं का हाल. मोदी सरकार में कहा जा रहा था कि प्रदेश में सपा सरकार है, इसलिए केंद्र के काम में बाधा डाली जाती है. अब तो यूपी में भी भाजपा की सरकार है. अब विकास के काम में कौन सी बाधा आ गई कि काम नहीं हो रहा! योगी सरकार बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि अधूरी पड़ी योजनाएं शुरू होंगी, लेकिन यथार्थ की जमीन पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है. निर्माण कार्य से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं को न जिला प्रशासन की परवाह है और न ही योगी सरकार की. गंगा नदी पर बनने वाले सामने-घाट पुल का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे. उन्होंने अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने का बाकायदा आदेश दिया था, लेकिन उनके फरमान की किसी ने परवाह नहीं की.

वाराणसी और रामनगर को जोड़ने वाला सामने-घाट पुल प्रशासनिक ढिलाई का उदाहरण बन गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस के कमिश्नर को लखनऊ बुला कर काशी में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था और सामने-घाट पुल के निर्माण के बारे में भी पूछा था. मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को निर्देश दिया था कि पुल का निर्माण 27 जून तक हो जाए. यहां तक कि पुल के लोकार्पण की तारीख 27 जून तय कर दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का आना तय हुआ था. उल्लेखनीय है कि इस पुल के निर्माण को वर्ष 2005 में ही मंजूरी मिली थी. इसका शिलान्यास वर्ष 2006 में हुआ था. पुल की लागत तब लगभग 4508.90 लाख रुपए आंकी गई थी. लेकिन दो बार इसके बजट में बढ़ोतरी हो चुकी है. अब इस खर्च के और बढ़ने की आशंका है. प्रशासन ने समय पर पुल नहीं बनने पर निर्माणकारी संस्था के अधिकारियों को जेल भेजने की भी चेतावनी दी थी, लेकिन यह चेतावनी कोई काम नहीं आई. कंपनी ने तय समय में काम पूरा करने से हाथ खड़े कर दिए. कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि सामने घाट और बलुवा घाट सेतु बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं. जबकि कंपनी को काम होने के पहले ही शत-प्रतिशत धनराशि सेतु निगम द्वारा दी जा चुकी है. इस तरह मुख्यमंत्री के आदेश, तमाम मंत्रियों के निरीक्षण, विधायकों की मॉनिटरिंग, कमिश्नर और जिलाधिकारी की सख्ती के बावजूद पुल नहीं ही बना. पुल निर्माण सेतु निगम की निगरानी में हो रहा है. अब निगम ने आश्वासन दिया है कि जुलाई में पुल बन जाएगा. लेकिन यह जुलाई में भी नहीं बन पाएगा. इस पुल के निर्माण की सच्चाई भी जानते चलें. इस पुल का कोई भी काम शत-प्रतिशत नहीं हुआ है, लेकिन कागजी दावा 97 फीसद काम पूरा करने का किया जा रहा है. इस झूठ की कलई सरकार और जनता के सामने खुल चुकी है, कार्रवाई भले ही कुछ न हो.

गंगा के नाम पर भी केवल राजनीति ही हो रही है

गंगा की सफाई के नाम पर लंबे दौर से सियासत चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट पर लोगों ने भरोसा किया था. साध्वी उमा भारती के मंत्री बनने पर गंगा के शुद्धिकरण की उम्मीदें जगी थीं. केंद्र ने पांच वर्ष के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपए की आर्थिक व्यवस्था भी की. नमामि गंगे कोष बनाया. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बनाया. अस्सी घाट पर श्रमदान भी किया गया. लेकिन प्रधानमंत्री के ही लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में गंगा से मिलने वाले अस्सी नाले को शुद्ध करने का कोई प्रयास आज तक नहीं हो सका.

दूसरी तरफ वरुणा नदी क्षेत्र पर अवैध कब्जा होता रहा और सरकार सोई रही. गंगा अब बनारस के घाटों से दूर होती जा रही है. पूरा समाज चिंतित है. पूरा पर्यटन-ढांचा ध्वस्त होने को है, लेकिन सरकार की चिंता में यह कहीं भी शामिल नहीं दिख रहा. गंगा-पुनर्जीवन के साथ-साथ 'नदी-विकास' शब्द भी जोड़ा गया था, इसलिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा के पुनर्जीवन से ज्यादा 'नदी-विकास' पर ध्यान दिया. विकास का मतलब उन्हें व्यापार समझ में आया. इस व्यापार के लिए वे सभी प्रमुख नदियों पर ड्रेजिंग, टर्मिनल निर्माण और बैराज निर्माण जैसी परियोजना ले आए. हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा पर बनने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-एक के लिए 37 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज भी मंजूर करा लाए. बिहार सरकार ने भी आगे बढ़कर अपनी छह नदियों पर जलमार्ग की सहमति दे दी. केंद्र के मंत्रीगण गंगा पर ई-नौका सजाने वाराणसी पहुंच गए. एक मंत्री तो गंगाजल बेचने की सुविधा भी लेकर आ गए. फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयुष गोयल भी इसमें कूद पड़े. जल विद्युत परियोजनाएं चलाने की मंजूरी ने पर्यावरण की ऐसी-तैसी कर दी. पर्यावरण मानकों की अनदेखी के लिए राष्ट्रीय हरित पंचाट (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका. बिहार सरकार ने भी देखा-देखी गंडक नदी पर 37 मेगावाट, कर्मनासा नदी पर 54 मेगावाट, कोसी नदी पर 58 मेगावाट, पुनपुन नदी पर 81 मेगावाट और सोन नदी पर 94 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी.

बनारस के लोग पूछते हैं कि सरकार के इन कदमों से गंगा को क्या लाभ मिला? उल्टे, जलमार्ग परियोजनाओं और जलविद्युत परियोजनाओं के कारण गंगा बेसिन की नदियों के मार्ग में अवरोध, गाद की बढ़ोत्तरी, नदी से छेड़छाड़ और इसके परिणामस्वरूप कटान और कचरे का खतरा भीषण रूप से बढ़ गया. गाद में मिलकर सीमेंट की तरह जम जाने वाला मल गाद के बहने में रुकावट डालता है. लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. नदी का अविरल बहाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि गंगा के मुख्य प्रवाह पर और बांध-बैराज न बने. पहले से बन चुके बांध-बैराज इतना प्रवाह अवश्य छोड़ें, जिससे गाद की प्राकृतिक तौर पर उड़ाही होती रहे और नदी में उसे निर्मल करने लायक वेग बचा रहे. गंगा ढाई सौ से अधिक सहायक छोटी-बड़ी नदियों से मिलकर बनी है. जब गंगा की ही कोई सुध नहीं ले रहा, तो उन सहायक नदियों की तरफ कौन देखे.

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. एलकेएस चौहान कहते हैं कि सिर्फ शहरों में सीवेज पाइप बिछाने, मल शोधन संयंत्र लगाने, गांव-गांव शौचालय बनाने, गंगा रक्षक बल बनाने या संस्थाओं को पांच-पांच गांव की परियोजनाएं बांटने से गंगा निर्मल नहीं होने वाली. प्रवाह बढ़ाने के लिए गंगा बेसिन की हर नदी और प्राकृतिक नाले में पानी की आवक भी बढ़ानी होगी. इसके लिए गंगा खादर में बसावटों पर रोक लगानी होगी. छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना होगा. शोधित जल और ताजा पानी नदी में बहाना होगा. नदियों को सतह अथवा पाइप से नहीं, बल्कि भूगर्भ तंत्रिकाओं के माध्यम से जोड़ना होगा. जहां कोई विकल्प न हो, वहां छोड़कर अन्यत्र लिफ्ट कैनाल परियोजनाओं के लिए मना करना होगा. जलदोहन नियंत्रित करना होगा. वर्षा जल संचयन ढांचों से कब्जे हटाने होंगे. जिस फैक्टरी, व्यावसायिक उपक्रम या कृषक समुदाय ने जितना और जैसा जल जिस स्रोत से लिया, उसे उतना और वैसा जल वापस लौटाने की प्रक्रिया बनानी होगी. उस प्रक्रिया के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करना होगा. गंगा और उसकी सहायक नदियों में रेत खनन नियंत्रित करने से नदी की जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी. इससे गंगा का प्रवाह बढ़ेगा. डॉ. चौहान ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार इनमें से एक भी उपाय कर पाई है? फिर गंगा के नाम पर नमामि-नमामि का जाप क्यों करती है? उनका कहना है कि गंगा नदी अब विभिन्न एजेंसियों के सदस्य देशों की कमाई का एजेंडा है. इसलिए समस्या बनाई रखी जाएगी और कमाई का जरिया कायम रखा जाएगा. केंद्र सरकार ने पहले दावा किया था कि अक्टूबर 2016 तक गंगा सफाई का आंशिक असर दिखने लगेगा. फिर वर्ष 2017 भी आ गया, सफाई नहीं दिखी. अब 2018 तक गंगा साफ न होने पर जल मंत्री साध्वी उमा भारती गंगा में कूद जाने का बयान दे रही हैं. फिर वर्ष 2019 भी आ जाएगा. सब चुनाव लड़ेंगे और अगर दोबारा सत्ता में आए, तो गंगा सफाई की डेड-लाइन वर्ष 2022 पर चली जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि गंगा का अपमान राष्ट्रद्रोह है. अब वे तय करें कि राष्ट्रद्रोह कौन कर रहा है और उसकी सजा क्या हो.

योजनाएं चौपट, बनारसी साड़ी का धंधा ठप्प, बुनकरों का बुरा हाल

दिल्ली और लखनऊ में बैठे मोदी के पैरोकार जमीनी स्थिति की जानकारी लिए बगैर विभिन्न योजनाओं का नाम गिनाते हैं और कहते हैं कि वे प्रोजेक्ट (जब पूरे होंगे) न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल देंगे. कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी बताए गए, जो केंद्र और राज्य सरकार के झगड़े के नाम पर लटकाए रखे गए थे. अब तो केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, अब क्यों लटका है? इसका जवाब उन अंध-पैरोकारों के पास नहीं है. जिन योजनाओं को गिनवाया जाता है, उनमें रामनगर कार्गो टर्मिनल परियोजना, डीजल रेल इंजन कारखाने की क्षमता बढ़ाने की योजना, इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना, मिनी पीएमओ बनाने की योजना, बीएचयू आईआईटी में रेल रिसर्च संकाय की योजना, वाराणसी की कनेक्टिविटी में सुधार की योजना, बिजली, टेलीफोन के तार को अंडरग्राउंड करने की योजना, हेरिटेज सिटी योजना, बनारस में गंगा पर क्रूज, प्राइवेट सेक्टर में निवेश, गंगातीरी गाय संरक्षण योजना और बनारस में कुश्ती और जूडो जैसे खेलों को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं. बनारस शहर की सड़कों और गलियों की नारकीय स्थिति को देखते हुए इनमें से कई योजनाओं के बारे में अभी ही अंदाजा लगाया जा सकता है. बचकानी योजनाओं का बेवकूफाना जिक्र करने वाले पैरोकार बनारस की संस्कृति और परंपरा को नष्ट किए जाने के कुचक्र पर कुछ नहीं कहते. बनारसी साड़ी का ऐतिहासिक कारोबार पहले नोटबंदी फिर जीएसटी के कारण नष्ट होने पर है. विडंबना यह है कि केंद्र सरकार जीएसटी लाकर कार की कीमत कम कर देती है, लेकिन बनारसी साड़ी के पारंपरिक व्यापार को जीएसटी के बाहर नहीं कर सकती.

रामनगर के राल्हूपुर में गंगा के किनारे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती है. रामनगर के सामने-घाट पुल का निर्माण किस जहालत में फंसा है, इसे आपने ऊपर जाना. लिहाजा, कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट के बारे में आप आकलन कर सकते हैं. जून 2016 में शुरू हुए कार्गो प्रोजेक्ट के अगस्त 2018 में पूरा होने का दावा किया जा रहा है. यह दावा भी पुल बनाने के दावे की तरह ही है. एफकॉन्स कंपनी कार्गो टर्मिनल बनाएगी. यह गंगा नदी पर छोटे-मोटे बंदरगाह की तरह होगा. जहां कार्गो शिप आया करेंगी. इस पोर्ट से बंगाल के हल्दिया बंदरगाह को जोड़ने की योजना है. आप खुद सोचिए कि बनारस में गंगा अपने घाट से दूर जा रही है. उसका बहाव कम पड़ता जा रहा है और वह सूखती जा रही है, ऐसे में कार्गो टर्मिनल का औचित्य क्या रहेगा. यह क्या उन्हीं तमाम परियोजनाओं की तरह नहीं हो जाएगा, जिन्हें बनाने के नाम पर अरबों रुपए खाए जाते हैं और परियोजनाओं की लाश जमीन पर छोड़ दी जाती है? भाजपा के नुमाइंदों ने यह दावा भी शुरू कर दिया कि व्यापारिक जल परिवहन का काम शुरू हो चुका है. लेकिन असलियत यह है कि प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अभी एक इंच जमीन नहीं मिली है, जबकि प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 30 एकड़ जमीन की जरूरत है. गंगा नदी पर हल्दिया से वाराणसी के बीच प्रस्तावित जल परिवहन योजना में जमीन का पेंच अभी भी फंसा हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के अपने पहले दौरे में ही जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि जमीन अधिग्रहण में आ रहे गतिरोध को जल्द से जल्द दूर किया जाए, लेकिन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अब तक जमीन नहीं मिल सकी है. अथॉरिटी के परियोजना निदेशक प्रवीर पांडेय का कहना है कि मल्टी मॉडल टर्मिनल के अलावा गोदाम और जिऊनाथपुर रेलवे स्टेशन के लिए पटरी बिछाई जानी है. जल परिवहन के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जानी हैं. लेकिन जमीन नहीं मिली है. जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं हो पाएगा. जमीन की अनुपलब्धता के कारण ही रामनगर में 'फ्रेट विलेज' बनाने की योजना भी अटकी पड़ी है. इस योजना के लिए कम से कम 60 एकड़ जमीन चाहिए. जबकि प्रशासन मुश्किल से 30 एकड़ जमीन उपलब्ध करा पा रहा है.

बनारस में इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना के बारे में भी खूब प्रचार-प्रसार किया गया. इसे अनोखा प्रोजेक्ट तक बता दिया गया. लेकिन बनारस भदोही और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकर बेल्ट में बुनकरों का क्या हश्र है, इसे जो जानते हैं उनसे बात करिए. बुनकरों को इस कॉम्प्लेक्स से क्या मिलने वाला? बुनकरों को सबसे पहले नोटबंदी ने बुरी तरह मारा और रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी. नोटबंदी से बुनकरी की 400 साल पुरानी परंपरा पर बुरा असर पड़ा. नोटबंदी के बाद सारे बुनकर बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनकी मजदूरी रोजाना के नगदी लेनदेन पर आधारित थी. नोटबंदी और जीएसटी ने बुनकरों और बनारसी साड़ी बुनने वाले कारीगरों की आजीविका पर चोट पहुंचाई है. बनारस पूरी दुनिया में बनारसी साड़ियों के लिए भी पहचाना जाता है. बुनकरी की कला में माहिर बुनकर हथकरघे पर कई-कई दिन की मेहनत के बाद एक बनारसी साड़ी तैयार करते हैं. लेकिन जीएसटी लगने के बाद बनारसी साड़ी का कारोबार ध्वस्त होने पर है. बनारस के बुनकर लगातार हड़ताल पर हैं. बनारसी साड़ी की मंडियों पर ताले लटके हैं. बुनकरों के हथकरघे की खटर-पटर की जगह मरघटी सन्नाटा छाया हुआ है. शहर के विभिन्न इलाकों में बुनकर हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर कर विरोध करते दिख रहे हैं. व्यापारियों और बुनकरों की मांग है कि मोदी सरकार बनारसी साड़ी से जीएसटी वापस ले, नहीं तो बनारसी साड़ी का व्यापार बंद हो जाएगा. पिछले करीब एक पखवाड़े से यहां बनारसी साड़ी का धंधा ठप्प पड़ा है. सरकार इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है. यह है मोदी का बनारस प्रेम. ■

बनारस के गंदे वर्तमान पर माकूल कविता

देवेंद्र पांडेय

बनारस शहर की अभागी सड़क / तू ही बता, तू कहां से आई है? / मैं कोई सरकस का बाजीगर तो नहीं, जो मौत के कुएं में जाकर / मोटर साइकिल के करतब दिखाकर, हंसता हुआ बाहर चला आऊं! / पर्वतारोही या खन्दकावरोही भी नहीं, जो चढ़ने-उतरने, दौड़ने-भागने का आदी होऊं! / सामान्य नागरिक हूं, सीधी-सादी सड़क पर ही चलना जानता हूं, / तुम्हारे जख्मों को ठीक नहीं कर सकता, तुम्हारी मरहम पट्टी के लिए, / तुम्हारे आशिक की तरह सड़क जाम कराने के आरोप में जेल नहीं जा सकता, / तो क्या यहां बैठकर, दो बूंद आंसू भी नहीं बहा सकता! / ऐ अभागी सड़क! / तेरी स्थिति बड़ी दुखदायी है, तू ही बता तू कहां से आई है? / दिल्ली या मुम्बई की तो तू हो नहीं सकती, गुजरात के भूकंप की तरह चरमराई / दंगों की तरह शरमाई दिखती तो है, पर गुजरात की ही हो यह जरूरी नहीं, / तू कश्मीर की तरह घायल है, मगर तेरे जिस्म से खून की जगह निकलते गंदे नाली के पानी को / देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तू कश्मीर की भी नहीं है, / नहीं, तू दक्षिण भारत की सुनामी लहरों की बहाई भी नहीं, / भ्रष्टाचार की गंगा में डूबी-उतराई है, तेरे जिस्म पर कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी खाई है, / लगता है तू बिहार से भटक कर बनारस चली आई है, / अब तुझ पर से होकर नहीं गुजरते रईसों के इक्के या फिर फरारि से दौड़ने वाले / गाड़ियों के मनचले चक्के, / अब तो इस पर घिसटते हैं सांड, भैंसे, गायें या फिर मजदूरी की तलाश में भागती साइकिलों के पहिये, / मैं जानता हूं कि तू कभी ठीक नहीं हो सकती, / क्योंकि तुम अपने रहनुमा की थाली की कभी खत्म न होने वाली मलाई है, / ऐ अभागी सड़क तू आधुनिक भारत के विकास की सच्चाई है / तू ही बता, बिगड़ी संस्कृति बन मेरे बनारस में कहां से चली आई है! ■

feedback@chauthiduniya.com

अपने गढ़ कोसी में कांग्रेस बेदम

अशोक चौधरी इन दिनों महागठबंधन को बचाने की कवायद में जुटे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. वहीं इन सवालों पर ही कांग्रेस पार्टी के कैडर, समर्थक, वोटर व वर्कर चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी विचार करें और पार्टी संगठन व कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर ध्यान दें. अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुशल नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस अपने ही गढ़ कोसी में वीरान व बेगाना बनकर रह जाएगी.

संजय सोनी

कभी कोसी की कांग्रेस सूबे की सरकार की दिशा व दशा तय करने वाली होती थी और आज कांग्रेसियों की यह हालत हो गई है कि वे अपनी जागीरदारी वाली सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं दे पा रहे हैं. कहा जा रहा है कि देश भर में कांग्रेस की साख कम हो रही है, इसलिए कोसी में भी कांग्रेस पिछड़ रही है. लेकिन इस आकलन को दूसरे नजरिये से भी देखने की जरूरत है. अगर कोसी में ऐसी बातें होती और यहां कांग्रेस का सशक्त संगठन नहीं होता, तो 2014 लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी की लहर के बावजूद सुपौल लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीता रंजन भारी मतों से चुनाव नहीं जीत पातीं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी के लिए यह एक अहम सवाल है, जिसपर गहन मंथन की जरूरत है. अशोक चौधरी इन दिनों महागठबंधन को बचाने की कवायद में जुटे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. वहीं इन सवालों पर ही कांग्रेस पार्टी के कैडर, समर्थक, वोटर व वर्कर चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी विचार करें और पार्टी संगठन व कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर ध्यान दें. अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुशल नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस अपने ही गढ़ कोसी में वीरान व बेगाना बनकर रह जाएगी.

बिमल यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

रंजीता रंजन

अशोक चौधरी

नब्बे के दशक तक पं. जगन्नाथ मिश्र, पं. रमेश झा, लहटन चौधरी, चौधरी मो. सलाउद्दीन, पं. अमरेन्द्र मिश्र सरीखे नेताओं की बदौलत कांग्रेस बिहार सरकार की दिशा तय करती थी. ये सभी कोसी के सहरसा, मधेपुरा व सुपौल में जात-पात व मजहब से ऊपर उठकर न केवल कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करते थे, बल्कि अपने रसूख के साथ-साथ कैडरों की पहचान एवं संगठन निर्माण में भी लगे रहते थे. आज जिनको संगठन का अधिकारी बनाया जाता है, वह पार्टी संगठन में न तो सेकंड लाइन तैयार करने में विश्वास रखता है और न ही गांव-गांव जाकर वर्करों से मिलना ही मुनासिब समझता है. लिहाजा इस क्षेत्र में जन-जन तक फैली कांग्रेस पार्टी आज कोसी में सिमट कर रह गई है. आज हालत यह है कि इनके वर्करों के दम पर ही भाजपा, रालोसपा और जदयू जैसे दल कोसी में सिर उठाकर चल रहे हैं.

सहरसा भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के टिकट पर सहरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े नीरज गुप्ता को कमान सौंपी गई है. इससे कांग्रेस को क्षेत्र में करारा झटका लगा है. नीरज गुप्ता को टिकट देना कांग्रेस की भूल ही कही जा सकती है. उस वक्त कांग्रेस ने अगर अपने कार्यकर्ताओं की बात मान ली होती और कैडरबेस कैंडिडेट को मैदान में उतारती तो आज कोसी में कांग्रेस को यह दिन नहीं देखना पड़ता. इसी तरह कांग्रेस ने कोसी में कई ऐसी भूलें की हैं, जिसपर कार्यकर्ता मंथन करना चाह रहे हैं.

अभी कोसी के जिला सहरसा से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में प्रो. विद्यानंद मिश्र, मधेपुरा से सत्येन्द्र सिंह यादव व सुपौल जिला से बिमल यादव अध्यक्ष हैं. इन तीनों में कोई शक नहीं है कि ये कांग्रेस के वफादार सिपाही नहीं हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की नजर में आज कांग्रेस में राजनीतिक रूप से कुशल अध्यक्षों की जरूरत है. कार्यकर्ता यह भी कहते हैं कि जो अध्यक्ष बन रहे हैं, वे गांव में घूमना ही छोड़ देते हैं. ऐसे में मतदाता तो जानें दें, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सुध लेने वाला भी कोई नहीं होता है. कार्यकर्ता मानते हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नरेन्द्र मोदी की लहर पर आधारित था, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी सुपौल लोकसभा सीट से रंजीता रंजन को जीत मिली, आखिर यह क्या है? आज भी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तीन सालों में सुपौल की सांसद रंजीता रंजन ने कभी संगठन को मजबूत करने का काम किया? अगर संगठन पर ध्यान दिया जाता तो आज कांग्रेस के गढ़ कोसी में कांग्रेस की यह हालत नहीं होती और 2019 के लोकसभा चुनाव का उत्साह अभी से पार्टी वर्करों में हिलोरें मार रहा होता. न कोई उत्साह न कोई पैरोकार, बस अपनी धुरी पर ही कांग्रेस की गाड़ी घूम रही है. कोसी में कांग्रेस की ताकत को देखकर ही भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को सुपौल में क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना पड़ रहा है. जबकि कोसी में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस का अपना कार्यालय व सक्रिय कार्यकर्ता होने के बाद भी वह अपने कार्यक्रमों को सही तरीके से सरजमीं पर नहीं उतार पा रही है. राजनीतिक जानकार भी यह मानते हैं कि कोसी में कांग्रेस के सभी कैडर व वोटरों को पार्टी लाइन से जोड़ने की जरूरत है, तभी पार्टी गठबंधन के साथ रहकर या अकेले दम पर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ सकती है. अभी कोसी के पड़ोसी जिला खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह चौधरी मो. सलाउद्दीन के पुत्र चौधरी महबूब अली कैसर लोजपा से सांसद हैं. बिहार के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर के नेतृत्व में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा. इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर भले खुद अपने गृह क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए, लेकिन बढ़े वोट प्रतिशत से कांग्रेस की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कार्यकर्ताओं को इस बात का मलाल है कि सुपौल में कांग्रेस के सांसद रहने के बाद भी पार्टी अपनी विचारधारा, कैडर व वर्करों को समेट नहीं पा रही है. वहां भी कार्यकर्ता व संगठन उपेक्षित हैं, जबकि मोदी लहर में सुपौल ने कांग्रेस को सांसद देने का काम किया. इस बिन्दु पर भी अगर सांगठनिक कार्यों पर जोर दिया जाए, तो कोसी में कांग्रेस ताकत के साथ उभर सकती है और 2019 के लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में भी पास हो सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

कैसे होगा भाजपा के मिशन 2019 का सपना पूरा?

वाल्मीकि कुमार

जातिवादी वर्चस्व की राजनीति ने सीतामढ़ी जिला में भाजपा संगठन को भीतर से खोखला कर दिया है. प्रदेश स्तर पर जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद से जिला संगठन दो खेमों में बंटा नजर आने लगा है. वर्तमान जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह अपने ही दल के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों की करतूतों को लेकर हाल में एनडीए गठबंधन के रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा से आमने-सामने हैं. वहीं जिला संगठन के विस्तार में पुराने सक्रिय कार्यकर्ताओं को किनारा कर नए चेहरों को तरजीह दिए जाने से विवाद और बढ़ गया है.

सीतामढ़ी जिला भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया था. परंतु पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सामान्य स्थिति बनाए रखने को लेकर प्रदेश संगठन ने जिलाध्यक्ष का चुनाव किया. इसमें पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर खास गुट के नेताओं को तरजीह दी गई. कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि नए जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी. वे एक दशक पूर्व जिला महामंत्री का पद भी संभाल चुके हैं. मगर हाल के महीनों में पार्टी पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य व विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों का चुनाव किसी भी दृष्टिकोण से पार्टी के लिए हितकर नजर नहीं आ रहा है. जिला भाजपा संगठन के एक पूर्व पदाधिकारी का कुछ ऐसा ही मानना है.

अब एक नजर जिलाध्यक्ष द्वारा गठित जिला भाजपा कमिटी की सूची पर डाल लेते हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह द्वारा गठित जिला कमिटी में पौने दो सौ कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है. इसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी, 69 कार्य समिति सदस्य, 19 स्थायी आमंत्रित कार्यसमिति सदस्य, 56 विशेष आमंत्रित कार्य समिति सदस्य के अलावा मोर्चा एवं मंच के 12 जिलाध्यक्षों को शामिल किया गया है. इसमें कुल 30 महिलाएं हैं, जिसमें 1 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री और 25 कार्य समिति सदस्य हैं. वहीं 3 अल्पसंख्यकों को भी कार्य समिति में शामिल किया गया है. इसके अलावा विधानसभा स्तर पर कुल 125 कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं. इनमें सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में 29, रून्नीसैदपुर में 13, बाजपट्टी में 14, सुरसंड में 18, परिहार में 10, बथनाहा में 11, रीगा में 19 व बेलसंड में 11 को कार्य समिति सदस्य बनाया गया है. वहीं मोर्चा एवं मंचों की जिम्मेदारी एक दर्जन कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है. इसमें युवा मोर्चा का नेतृत्व चुनचुन सिंह, किसान मोर्चा का चंदेश्वर पूर्वे, महिला मोर्चा का विभा ठाकुर, अल्पसंख्यक मोर्चा का शाहीन परवीन, अनुसूचित जाति मोर्चा का गौतम राम आजाद, अति पिछड़ा मोर्चा का बृजनंदन प्रसाद, पंचायती राज मंच का नवीन सिंह, सहकारिता मंच का सुरेश नंदन ठाकुर, शिक्षा मंच का पुणीन्द्र चौधरी, क्रीड़ा मंच का अखिलेश सिंह, व्यवसाय मंच का सुनील नायक व चुनाव आयोग मंच का महंत अशोक दास को दिया गया. पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिला कमिटी में अधिकतर वैसे लोगों को शामिल किया गया है, जो कुछ वर्षों में किसी अन्य पार्टी से पधारे हैं अथवा जिनका लंबे अर्से से पार्टी संगठन से कोई नाता नहीं था. वहीं कुछ ऐसे भी लोग शामिल

सुनील कुमार पिंटू

उमेशचंद्र झा

सुबोध कुमार सिंह

शशिनाथ सिंह

संजीव चौधरी

सुफल झा

प्रो. वीरेंद्र प्रसाद सिंह

मनोज शक्ति

किरण प्रसाद

दिनकर पंडित

बैद्यनाथ प्रसाद

अरुण गोप

हैं, जिन्होंने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के विरुद्ध बतौर निर्दलीय चुनावी समर में उतरे थे. नतीजतन पार्टी व गठबंधन के प्रत्याशियों को पराजय का सामना करना पड़ा था. विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के होते हुए चुनावी दंगल में ताल ठोकने वालों में सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से शाहीन परवीन, बेलसंड विधानसभा से पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, रून्नीसैदपुर विधानसभा से शशिनाथ सिंह व बाजपट्टी से श्याम चौधरी समेत कुछ अन्य लोग रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें जिला कमिटी में स्थान दिया गया है. जिला में मोर्चा एवं मंच की जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों को सौंपी गई है, जो बिल्कुल नए चेहरे हैं अथवा पार्टी लीक से हटकर काम करते रहे हैं. वहीं लंबे अर्से से जिला कमिटी में सक्रिय रहे प्रो. विरेंद्र प्रसाद सिंह, निर्मल कुमार वियाहुत, संजय प्रियदर्शी, राम नरेश पांडेय, शिवराम साह व संजीव चौधरी सरीखे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है. चर्चा है कि दो खेमों में विभक्त जिला नेतृत्व की कमान दो अलग-अलग स्वजातीय पूर्व प्रतिनिधि के हाथों में है. इनमें एक फिलहाल सक्रिय नहीं हैं, जबकि दूसरे पार्टी गतिविधियों में भागीदारी कर रहे हैं. चर्चा यह भी है कि इन दोनों के बीच चल रहे राजनीतिक वर्चस्व का फायदा कोई और उठा रहा है और पार्टी संगठन में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है. इनका मकसद जिला पार्टी संगठन को मजबूत करने से ज्यादा 2019 की दावेदारी को लेकर अपने कुनबे को मजबूत करना है. जिले में भाजपा संगठन के जो हालात हैं, अगर समय रहते केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो मिशन 2019 का सपना अधूरा रह जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

बिखर रही बापू की विरासत, सभी कर रहे सियासत

बापू के चरखे से निकलता सियासत का सूत

राकेश कुमार

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर बापू को लेकर राजनीतिक दलों की सियासत तेज हो गई है, पर उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए कोई तैयार नहीं है. यहां तक कि गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले नेता और तथाकथित गांधीवादी भी सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर नजर नहीं आ रहे हैं. राज्य और केन्द्र सरकार ने भी शताब्दी वर्ष पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है. ऐसे में कुछ गैर राजनीतिक संगठनों ने गांधी के विचारों को यथासंभव फैलाने की मुहिम शुरू की है.

पत्रकारों ने पहल की सत्याग्रह शताब्दी समारोह की

प्रखर गांधीवादी और वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रभूषण पाण्डेय के नेतृत्व में चम्पारण प्रेस क्लब ने 10 अप्रैल को 'वर्तमान परिवेश में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया था. सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी मौजूद थे. चम्पारण प्रेस क्लब के इस कदम को सराहनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने गांधी जी के विचारों को देश-दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया है. इस दौरान कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया. इसके बाद सत्याग्रह या बापू से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, लेकिन चम्पारण प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम ने पटना और दिल्ली तक एक महत्वपूर्ण संदेश अवश्य पहुंचाया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पहल की और चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह मनाने का निर्णय लिया.

विशेष मौके पर ही याद आते हैं गांधी

बापू के नाम पर ब्रांडिंग करने वाले नेताओं को गांधी जी की याद विशेष मौके पर ही आती है. गांधी जयन्ती, पुण्यतिथि, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसी कुछ तिथियों पर ही नेतागण समारोह का आयोजन करते हैं. सरकारों और दलों ने भितिहरवा आश्रम से अपना अभियान शुरू करने की परम्परा बना ली है, लेकिन बापू की विरासत, भितिहरवा आश्रम और उस क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई काम शुरू नहीं हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर एकमात्र ऐसे राजनेता थे, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहल की. 13 वर्षों तक बापू की पुण्यतिथि पर चन्द्रशेखर भितिहरवा आते रहे. इसी दौरान मोतिहारी के कुछ स्थानीय नेता और बुद्धिजीवी भी उनके इस अभियान से जुड़े. गांधी दर्शन से जुड़े चन्द्रभूषण पाण्डेय बताते हैं कि चन्द्रशेखर मोतिहारी में बैठक कर भितिहरवा के विकास के लिए व्यक्तिगत रूप से चंदा इकट्ठा करते थे. उनके आगमन पर आनन-फानन में राज्य सरकार सड़क निर्माण कराती थी, जो साल भर बाद पुन: टूट जाता था. इस दौरान राज्य सरकार ने भी कुछ योजनाएं शुरू कीं, जो आज खस्ताहाल हैं. 'बा' के नाम पर कस्तूरबा कन्या विद्यालय खोला गया, जो आज बंद होने के कगार पर है. यह हाल तब है, जब लगभग सभी बड़े नेता भितिहरवा जा चुके हैं.

गांधी जी की प्रथम पाठशाला बड़हरवा लखनसेन की भी हालत कुछ ऐसी ही है. ज्ञात हो कि गांधी जी ने 14 नवम्बर 1918 को बड़हरवा लखनसेन में बेसिक स्कूल की स्थापना की थी. स्थानीय रामलाल बख्शी नामक किसान ने विद्यालय के लिए जमीन और भवन दान में दिया था. इस स्कूल में बा रहकर बच्चों को शिक्षा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाती थीं. जिस खपड़ैल मकान में बा रहती थीं, उसे भी हटा दिया गया है. चम्पारण के ढाका प्रखण्ड से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़हरवा लखनसेन स्थित बापू के प्रथम बेसिक विद्यालय के भग्नावशेष को भी संभालकर नहीं रखा गया. यहां महज खानापूर्ति के लिए गांधीजी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण गांधी जी के पौत्र राजगोपाल गांधी ने किया था. यहां पर वह चरखा भी था, जो विद्यालय के स्टोर में रखे-रखे कबाड़ बन गया. इस चरखे को गांधी जी और उनके बाद बा चलाती थीं. तकरीबन 5 साल पहले वरिष्ठ पत्रकार स्वयंप्रकाश बड़हरवा लखनसेन आए थे. उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को फटकार लगाते हुए बापू की विरासत को संभालकर रखने की नसीहत दी थी.

वहीं 17 जनवरी 1918 को गांधी जी ने मधुबन में तीसरे बेसिक स्कूल की स्थापना की थी. मारवाड़ियों ने इस स्कूल के लिए जमीन दी थी. स्थानीय लोग बताते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्कूल बन्द कर दिया गया और उसमें कांग्रेस का कार्यालय बना दिया गया. कांग्रेस के नेताओं ने ही गांधी जी के तीसरे बेसिक स्कूल को हड़प लिया. आज भी वहां कांग्रेस का कार्यालय खुला है.

कह सकते हैं कि चम्पारण भले ही गांधी जी के सत्याग्रह की प्रयोगस्थली रही हो, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं ने बापू की विरासत को संजोने का काम नहीं किया. 2000 के दशक में तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण कुमार और उनके बाद चंचल कुमार के दौरान गांधी संग्रहालय एवं स्मारक का निर्माण कराया गया. गांधी स्मारक के तत्कालीन सचिव चन्द्रभूषण पाण्डेय के अथक प्रयासों के बाद स्मारक बनकर तैयार हुआ. चन्द्रहिया में भी गांधी स्मारक की भूमि पर अतिक्रमण हो गया था, जिसे तत्कालीन डीएम नर्मदेश्वर लाल ने मुक्त कराकर चहारदीवारी का निर्माण कराया.

शताब्दी वर्ष पर भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. नीतीश कुमार ने शताब्दी वर्ष समारोह के तहत 18 अप्रैल को चन्द्रहिया से मोतिहारी गांधी उद्यान तक लगभग 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा की. इस यात्रा में लोगों ने भागीदारी की, लेकिन इसमें ज्यादातर वैसे लोग थे, जो मुख्यमंत्री को अपना चेहरा दिखाना चाहते थे. जो गांधी भक्त थे वे काफिले में गुम हो गए थे. पैदल यात्रा के बाद आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाषण दिया. परंतु इस आयोजन का कोई लाभ क्षेत्र को या गांधी से जुड़े विरासत को नहीं मिला. राज्य सरकार अक्टूबर माह में एक बड़ा आयोजन मोतिहारी में करने वाली है. राज्य सरकार ने पटना में भी कई कार्यक्रम किए. इस दौरान पूरे राज्य में गांधी जी से जुड़ी फिल्में भी दिखाई गईं. महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति डॉ. अरविन्द अग्रवाल के नेतृत्व में रन फॉर चम्पारण का आयोजन किया.

वहीं स्थानीय सांसद सह केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के नेतृत्व में भी सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह 13 से 19 अप्रैल तक मनाया गया. हालांकि पहली बार मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा मोतिहारी में जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया गया. इस सात दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कृषि मेला, कौशल विकास, रोजगार मेला, खादी मेला, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नई तकनीक और परामर्श, बागवानी मिशन और कोऑपरेटिव द्वारा मेला लगाया गया. उक्त अवसर पर केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी, अनन्त कुमार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सुशील मोदी और राम कृपाल यादव भी मौजूद थे. वहीं गांधी जी की पौत्री तारा गांधी सहित कई गांधीवादी भी आए थे.

भावविभोर हुई बापू की पौत्री तारा गांधी

तारा गांधी ने चन्द्रहिया में महिलाओं की सभा में भी भाग लिया. वहां की ग्रामीण महिलाओं ने उन्हें छूकर देखने की कोशिश की, तो उनकी आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि हममें बापू जैसा कुछ भी नहीं, मैं आप जैसी ही हूं. आप लोग महान हैं, जिन्होंने अपने दिलों में बापू को आज भी जिन्दा रखा है. चन्द्रहिया गांव की महिलाएं खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित कार्य करती थीं. वे चरखा चलाने, सूत कातने और रंगाई का काम करती थीं. यही उनकी जीविका थी, पर 1970 के दशक में खादी ग्रामोद्योग का यह कार्यक्रम बन्द कर दिया गया. सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर सांसद राधा मोहन सिंह ने चन्द्रहियां को गोद लिया है. इसके बाद यहां सोलर लैम्प लगे और घर-घर विद्युत कनेक्शन दिया गया है. पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है.

बेसहारा हैं बापू के सहयोगी के परिजन

इसे विडम्बना ही कहेंगे कि गांधी जी के साथ उनके आन्दोलन में भाग लेने वाले और अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए चन्द्रहिया निवासी भिखारी राय के परिजनों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है. गांधी स्मारक के सचिव चन्द्रभूषण पाण्डेय ने उनको सरकारी लाभ दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं रहे.

8 और 9 जुलाई को चम्पारण प्रेस क्लब ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश के हर प्रान्त से पत्रकारों ने भाग लिया. मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात पत्रकार संतोष भारतीय, एशिया टीवी के राजीव मिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और लेखक आनन्द वर्धन भी मौजूद थे. उक्त समारोह में केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे. राधाकृष्ण सिकारिया बीएड कॉलेज में आयोजित सेमिनार के मंच से वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने यह प्रश्न उठाया कि गांधी जी ने जिन क्षेत्रों को चुना था, इस मौके पर उसके विकास के लिए क्या किया गया? उन्होंने विधानसभाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को भी यह संदेश दिया कि उन क्षेत्रों में गांधी जी के विचारों के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि पर काम करना चाहिए. इसके अलावा उनके विचारों को प्रचारित-प्रसारित करने पर जोर देना चाहिए. इस सेमिनार का उद्देश्य भी यही था कि देश भर के पत्रकारों को गांधी के सत्याग्रह की प्रयोगस्थली को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिल सके. अगर गांधी जी के विरासत को संभालकर रखा जाता, तो आज चंपारण विश्व स्तर पर गांधीवादियों के लिए एक पर्यटक स्थल जरूर बन जाता. ■

feedback@chauthiduniya.com

बारिश का मौसम और एलर्जी

ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
नेशनल हेल्थ केयर स्टेडियम रोड, अरविन्द प्रेस के बगल में नवादा
डॉ. एन. आजम (फिजिशियन)
MBBS - MD- Medicine

डॉ एन आजम के नेशनल हेल्थ केयर क्लीनिक से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने बारिश के मौसम में होने वाली एलर्जी पर चर्चा की और बताया कि लोग गर्मी के बाद आने वाली बारिश का मजा लेने से नहीं चुकते और सावधानी नहीं बरतने के कारण एलर्जी के शिकार हो जाते हैं बारिश में यदि आप भींग जाते हैं तो तुरंत कपड़े से पोंछ लें और कपड़ा बदल लें। वरना एलर्जी के कारण आपके सर्दी खांसी जुकाम परेशान कर देगी। उन्होंने बताया कि यह मौसम ही ऐसा है कि भींगने के अलावा फूड एलर्जी, व पॉलीग्रेन एलर्जी भी आपको हो सकती है। लोगों को इसके अलावा मिल्क एलर्जी आदि कई प्रकार के एलर्जी रोग होते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि सामान्य जिन्दगी जिने के लिए कुशल चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इन दिनों चाहिए कि बासी खाना न खायें साथ ही पानी उबाल कर पियें । खास कर वे जो कि जो कि प्यूरीफाइर का प्रयोग नहीं करते हैं। गर्म खाना खायें रात में ठंढी चीजों का प्रयोग खाने में न करें। इन दिनों वायरल बीमारियां भी ज्यादा होती हैं इसलिए घर में तथा आसपास की सफाई रखें इसके अलावा आपको चाहिए की घर को मच्छरों से दूर रखें इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। आईए बच्चों के लिए फूड एलर्जी पर जानते हैं कुछ विशेष बातें - •चार से छह महीने के शिशु को पके हुए भोजन से परिचित कराएं, हरी सब्जियों, फल और बेबी राइस से बनी चीजें दें। लेकिन मटर, बीन्स, टमाटर, मसूर दाल, सिट्रस फल और बेरी न दें। पांच से छह महीने से ऊपर के बच्चों को उपरोक्त के अलावा लैंब, चिकेन, पोर्क, स्ट्राबेरी, रसबेरी और सिट्रस फूड भी दे सकते हैं। • आठ महीने के शिशु को आप उसके खाने में मछली को भी शामिल कर सकते हैं पर शेल फिश को न शामिल करें। • एक साल का होने पर धीरे-धीरे अंडे को खाने में शामिल करने की कोशिश करें। • पांच साल का होने पर अधिकांश बच्चे इस समय तक शेल फिश व मूंगफली के लिए तैयार हो जाते हैं। पर बहुत ध्यान रखें कि कहीं बच्चे को इससे एलर्जी न हो। ▪ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

जीएसटी ने रोकी जीटी रोड की रफ्तार

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

देश में एकसमान कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद सबसे व्यस्तम रहनेवाले राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-02 (जीटी रोड) पर चलनेवाले मालवाहक वाहनों में भारी कमी आ गई है. कह सकते हैं कि जीएसटी ने जीटी रोड की रफ्तार रोक दी है. सबसे बड़ी बात यह है कि बिना परमिट और अवैध माल से लदे वाहनों को जांच चौकी से पार कराने वाले एंट्री माफिया का धंधा मंदा हो गया है. ओवरलोडेड वाहनों का भी परिचालन अभी बंद है. वाणिज्य कर विभाग ने जांच चौकी से अपना कार्यालय हटा लिया है. इसके कारण बिहार में पड़ने वाले जांच चौकी पूरी तरह से वीरान हो गए हैं. इन जांच चौकियों से सभी वाहन बिना रुकावट के पार हो रहे हैं. इससे बड़ा फायदा यह है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है और ईंधन की भी बचत हो रही है. इससे मालवाहक वाहनों के चालक खुश हैं कि उन्हें चेक पोस्ट पर घंटों खड़े रहकर कागजात की जांच कराने की फजीहत से निजात मिल गई है. वहीं अवैध रूप से बिना कागजात के माल लदे वाहनों को चेक पोस्ट से पार कराने वाले एंट्री माफिया और उनके सम्पर्क में लाइन होटल चलाने वाले परेशान हैं. ये अब दूसरे धंधों की तलाश में जुट गए हैं. राज्य के सबसे व्यस्ततम समेकित चेकपोस्ट गया के डोभी, कर्मनाशा, बक्सर या फिर नवादा के रजौली की अंतरराज्यीय चेक पोस्ट सभी पर सन्नाटा पसरा है. किसी भी चेक पोस्ट पर वाहनों की कतार नजर नहीं आती है. वाणिज्य कर विभाग द्वारा अपने कर्मियों को हटा लिए जाने से परिवहन विभाग को ओवरलोडेड वाहनों के कागजात तथा खनन एवं उत्पाद विभाग को शराब आदि की जांच करने में परेशानी हो रही है. जांच के नाम पर भी अब सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. वन विभाग के कर्मी भी जांच के नाम पर चेक पोस्ट पर बैठकर समय गुजार रहे हैं. इसका कारण यह है कि वाणिज्य कर विभाग के कारण जांच करवाने के लिए सभी चेक पोस्टों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रहती थी. इसी दौरान सभी विभाग के कर्मचारियों को भी जांच करने का मौका मिल जाता था. उस दौरान हथियार बंद सुरक्षाकर्मी भी बड़ी संख्या में चेक पोस्ट पर तैनात रहते थे. लेकिन अब वैसी स्थिति है नहीं, जिसके कारण सभी चेक पोस्टों का नजारा बदला-बदला सा नजर आ रहा है. जीएसटी लागू होने से पहले चेकपोस्ट पर ढाई से तीन किलोमीटर दूर तक वाहनों की कतार लग जाती थी. नवादा में रजौली अंतरराज्यीय जांच चौकी से दस किलोमीटर पहले ही दिबौर से रजौली तक के लाइन होटलों पर एंट्री माफिया का जमावड़ा लगा रहता था, जो अब खत्म हो गया है. गया के डाभी चेक पोस्ट पर अब वाहनों की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है या फिर वाहन रुक नहीं रहे हैं, जिसके कारण परिवहन, खनन, उत्पाद तथा वन विभाग के कर्मी वाहनों की जांच नही कर पा रहे हैं. इन विभागों के अधिकारियों ने डोभी चेक पोस्ट के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है. पहले वाणिज्य कर विभाग से इन और आउट मुहर लेने के लिए हर मालवाहक वाहन को रुकना पड़ता था. इन विभागों के अधिकारियों ने चेक पोस्ट पर वाहन रोकने की व्यवस्था करने की मांग करते हुए कहा कि सुरक्षा बल की तैनाती के बाद ही चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच संभव है.

परिवहन व्यवस्था के लिए प्राचीन काल से चर्चित जीटी रोड (अब राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-02) पर प्रतिदिन औसतन चार से पांच हजार वाहन गुजरते हैं. इसमें से आधे वाहन मालवाहक होते हैं. 24 घंटे में दो-ढाई हजार वाहनों की लाठीधारी सुरक्षा बलों के सहारे जांच करना काफी मुश्किल काम है. गया के डोभी चेकपोस्ट को कुछ वर्ष पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया था. अपराधी यहां से राशि भी लूटकर ले गए थे. इस चेकपोस्ट पर नक्सलियों का हमला भी हो चुका है. जीएसटी लागू होने के बाद अगर समेकित जांच चौकियों पर उत्पन्न समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो ट्रक चालकों की मनमानी और बढ़ जाने की उम्मीद है. अब एंट्री माफिया भी परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर ओवरलोडेड वाहनों से कुछ कमाई का रास्ता तलाश रहे हैं. हालांकि पक्के बिल और सही कागजात पर माल की ढुलाई करने वाले वाहनों में कमी आ गई है. जीटी रोड पर ऐसे मालवाहक वाहनों की संख्या कुछ कम हो गई है. अब देखना है कि आने वाले समय में जीएसटी के कारण कारोबार फिर पुराने ढर्रे पर लौटता है या नहीं. ■

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

साहित्यकार, सिनेमा और संशय

अनंत विजय

इस वक्त साहित्यिक हलके में ये खबर आम हो रही है कि मशहूर अंग्रेजी लेखक अमिष त्रिपाठी की बेस्टसेलर किताब 'द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा' पर फिल्म बनने जा रही है. ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की बात फैली है. इसके पहले भी ये खबर आई थी कि करण जौहर ने अमिष त्रिपाठी की इस किताब पर फिल्म बनाने का फैसला लिया है. उस दौर में तो यहां तक चर्चा हुई थी कि अमीष के उपन्यास के आधार पर बनने वाली फिल्म में शिव की भूमिका के लिए करण जौहर ने ऋतिक रौशन, सलमान खान जैसे बड़े सितारों से बात की थी. लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है कि फिल्मों के नहीं बन पाने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आती है, उसी तरह से करण जौहर की फिल्म फ्लोर पर क्यों नहीं जा पाई, उसका भी पता नहीं लग पाया. अब इस तरह की चर्चा चल पड़ी है कि अमिष त्रिपाठी की इस बेस्टसेलर पुस्तक पर फिल्म बनाने का अधिकार करण जौहर के पास से संजय लीला भंसाली के पास आ गया है. इस फिल्म में शिव की भूमिका के लिए संजय लीला भंसाली ने ऋतिक रोशन को तय किया है. अगर इन बातों में दम है, तो ये साहित्य के लिए बेहतर स्थिति है. अमिष त्रिपाठी को शिवा ट्रायलॉजी की इस किताब ने पर्याप्त यश और धन दोनों दिलवाया था. दुनियाभर में अमिष के लेखन को लेकर एक उत्सुकता भी बनी थी. उसके बाद अमिष त्रिपाठी ने कई किताबें लिखीं, जिनको दुनियाभर के पाठकों ने हाथों हाथ लिया. अब अगर उस किताब पर फिल्म बनती है, तो लेखक की लोकप्रियता में एक नया आयाम जुड़ेगा.

हिंदी फिल्मों का साहित्य से बड़ा गहरा और पुराना नाता रहा है. कई लेखक साहित्य के रास्ते फिल्मी दुनिया पहुंचे थे. प्रेमचंद से लेकर विजयदान देथा की कृतियों पर फिल्में बनीं. कइयों को शानदार सफलता और प्रसिद्धि मिली, तो ज्यादातर बहुत निराश होकर लौटे. प्रेमचंद, अमृत लाल नागर, उपेन्द्र नाथ अश्क, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रानंदन पंत जैसे साहित्यकार भी फिल्मों से जुड़ने को आगे बढ़े थे. लेकिन जल्द ही उनका मोहभंग हुआ और वे वापस साहित्य की दुनिया में लौट आए. प्रेमचंद के सिनेमा से मोहभंग को रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने संस्मरण में लिखा है- '1934 की बात है. बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था. इन पंक्तियों का लेखक कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने आया. बंबई में हर जगह पोस्टर चिपके हुए थे कि प्रेमचंद जी का 'मजदूर' अमुक तारीख से रजतपट पर आ रहा है. ललक हुई, अवश्य देखूं कि अचानक प्रेमचंद जी से भेंट हुई. मैंने 'मजदूर' की चर्चा कर दी. वे बोले, 'यदि तुम मेरी इज्जत करते हो, तो ये फिल्म कभी नहीं देखना.' ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं. और, तब से इस कूचे में आने वाले जिन हिंदी लेखकों से भेंट हुई, सबने प्रेमचंद जी के अनुभवों को ही दोहराया है.' अब ऐसा क्यों हुआ कि हमारे हिंदी साहित्य के हिरामन फिल्मों से इस कदर आहत हो गए. क्यों सुमित्रानंदन पंत जैसे महान कवि के लिखे गीतों को फिल्मों में सफलता नहीं मिल पाई, क्यों गोपाल सिंह नेपाली जैसे ओज के कवि को फिल्मों में आंशिक सफलता मिली. क्यों राजेन्द्र यादव और मन्नू भंडारी जैसे शब्दों के जादूगर फिल्मों में अपनी सफलता का डंका बजाते हुए लंबे वक्त तक कायम नहीं रह सके. राजेन्द्र यादव की जिस कृति 'सारा आकाश' पर उसी नाम से बनी फिल्म को समांतर हिंदी सिनेमा की शुरुआती फिल्मों में शुमार किया जाता है, वो राजेन्द्र यादव बाद के दिनों में फिल्म से विमुख क्यों हो गए.

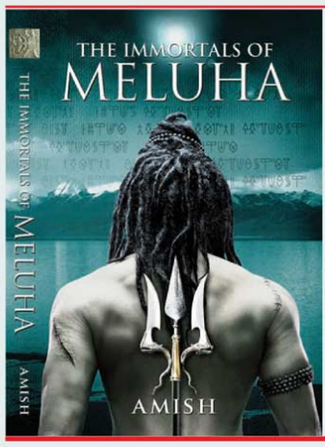

ये समझना होगा कि फिल्म लेखन साहित्य से बिल्कुल अलग है. इसकी मुख्य वजह जो समझ में आती है, वो ये कि साहित्यकार की आजाद ख्यालती या उसकी स्वछंद मानसिकता फिल्म लेखन की सफलता में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है. अपनी साहित्यिक कृतियों में लेखक अंतिम होता है और उसकी ही मर्जी चलती है, वो अपने हिसाब से कथानक को लेकर आगे बढ़ता है और जहां उसे उचित लगता है उसको खत्म कर देता है. लेकिन फिल्मों में उसके साथ ये संभव नहीं होता है. फिल्मों में निर्देशक और नायक पर बहुत कुछ निर्भर करता है और फिल्म लेखन एक टीम की कृति के तौर सामने आती है. वहीं साहित्यिक लेखन एक व्यक्ति का होता है. दिक्कत यहीं से शुरू होती है.

यहां ये समझना होगा कि फिल्म लेखन साहित्य से बिल्कुल अलग है. इसकी मुख्य वजह जो समझ में आती है, वो ये कि साहित्यकार की आजाद ख्याली या उसकी स्वछंद मानसिकता फिल्म लेखन की सफलता में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है. अपनी साहित्यिक कृतियों में लेखक अंतिम होता है और उसकी ही मर्जी चलती है, वो अपने हिसाब से कथानक को लेकर आगे बढ़ता है और जहां उसे उचित लगता है उसको खत्म कर देता है. लेकिन फिल्मों में उसके साथ ये संभव नहीं होता है. फिल्मों में निर्देशक और नायक पर बहुत कुछ निर्भर करता है और फिल्म लेखन एक टीम की कृति के तौर सामने आती है. वहीं साहित्यिक लेखन एक व्यक्ति का होता है. दिक्कत यहीं से शुरू होती है.

प्रेमचंद के जिस दर्द को रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने संस्मरणों में जाहिर किया है, उससे तो कम से कम यही संकेत मिलते हैं. कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता. प्रेमचंद जैसा लेखक ये कहने को मजबूर हो गया कि अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो इस फिल्म को कभी मत देखना. संकेत यही है कि कथानक से उनकी मर्जी के विपरीत खिलवाड़ किया गया होगा. कहा ये जाता है कि जिस तरह से बेहतरीन सृजन के लिए साहित्यकार का उच्च कोटि का होना आवश्यक है, उसी तरह से बेहतरीन कृतियों के साथ न्याय कर पाने की क्षमता के लिए फिल्मकार का भी समर्थ होना आवश्यक है. लेकिन प्रेमचंद की कृतियों के साथ तो ऋषि मुखर्जी और सत्यजित राय जैसे महान फिल्मकार भी न्याय नहीं कर सके. एम भावनानी और नानूभाई वकील और त्रिलोक जेटली तो नहीं ही कर पाए. गुरुवर रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 1929 में शिशिर कुमार भादुड़ी के भाई मुरारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सिनेमा और साहित्य पर अपने विचार प्रकट किए थे. टैगोर ने लिखा था- 'कला का स्वरूप अभिव्यक्ति के मीडियम के अनुरूप बदलता चलता है. मेरा मानना है कि फिल्म के रूप में जिस नई कला का विकास हो रहा है, वो अभी तक रूपायित नहीं हो पाई है. हर कला अपनी अभिव्यक्ति की स्वाधीन शैली अपने रचना जगत में तलाश लेती है. सिनेमा के लिए सृजनशीलता ही काफी नहीं है, उसके लिए पूंजी भी आवश्यक है और सिनेमा में बिंबों के प्रभाव के माध्यम से अभिव्यक्ति को पूर्णता प्राप्त होती है.' टैगोर की राय से काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है.

सिनेमा के सौ बरस पुस्तक में लिखे अपने लेख 'मैंने तो तौबा कर ली' में मस्तराम कपूर भी कहते हैं- 'मैंने महसूस किया कि फिल्मों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखी गई रचना सही मायने में साहित्यिक रचना नहीं बनती है. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि फिल्म और टीवी का माध्यम साहित्य के अनुकूल नहीं है. फिल्म और टीवी के लिए लिखी गई रचना बाजार की मांग को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, जबकि साहित्यिक रचना अपने अंधकार और अपने बंधनों से लड़ने की प्रक्रिया से निकलती है.' प्रेमचंद के दर्द और मस्तराम कपूर के अनुभवों से साहित्यकारों के फिल्मों में ज्यादा लंबा नहीं चल पाने की वजह के संकेत तो मिलते ही हैं.

यह तो सैद्धांतिक बातें हुईं, लेकिन बॉलीवुड में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं. ये दिक्कतें हैं, बाजार और मांग के हिसाब से लेखन करना या फिर लिखे गए में निर्देशकों की मर्जी से बदलाव करना. साहित्य में जो लेखन होता है, वो दृश्यों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि कथा के प्रवाह को ध्यान में रखकर होता है. हिंदी के ज्यादातर साहित्यकार हिंदी सिनेमा के साथ समन्वय नहीं बैठा पाए और सिनेमा की दुनिया से निराश होकर ही लौटे. ये आज की दिक्कत नहीं है. प्रेमचंद की कहानी 'शतरंज के खिलाड़ी' पर जब सत्यजित राय फिल्म बना रहे थे, तब उनपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रेमचंद की कहानी के साथ छेड़छाड़ किया. शाहरुख खान ने जब विजयदान देथा की कहानी 'पहेली' पर फिल्म बनाई, तब भी उसमें काफी बदलाव किया गया था. ये होता रहा है, लेकिन अब इसने सांस्थानिक रूप ले लिया है. अब निर्देशक कहानी में काफी बदलाव चाहते हैं या वो चाहते हैं कि घटनाओं और स्थितियों के हिसाब से कहानियां लिखी जाएं. ऐसे माहौल में साहित्यकारों का मोहभंग होना लाजिमी है. वो इस माहौल में अपने को फिट नहीं पाते हैं. उधर बॉलीवुड में प्रोफेशनल लेखकों की एक पूरी फौज तैयार है, जो घटनाओं और स्थितियों के आधार पर लेखन करने को तैयार हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमिष त्रिपाठी की कृति पर बनने वाली फिल्म में कथानक से छेड़छाड़ की जाती है या नहीं. बगैर विवाद के अगर ये फिल्म बनती है, तो साहित्य के लिए बेहतर होगा. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

जब सूचना न मिले तो अपील करें

चौथी दुनिया ब्यूरो

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी सूचना की अभिगम्यता प्रदान करने से मना किया गया हो, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील/शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

दूसरी अपील कब दर्ज करें

19 (1) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) अथवा धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट समय के अंदर निर्णय प्राप्त नहीं होता है अथवा वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से पीड़ित है, जैसा भी मामला हो, वह उक्त अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर अथवा निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उस अधिकारी के पास एक अपील दर्ज करा सकता है, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का है, जैसा भी मामला हो:

1. बशर्ते उक्त अधिकारी 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर लेता है. यदि वह इसके प्रति संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से रोकने का पर्याप्त कारण है.

19 (2): जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की सूचना का प्रकटन किया जाता है, तब सम्बंधित तीसरा पक्ष आदेश की तिथि के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है.

19 (3) उपधारा 1 के तहत निर्णय के विरुद्ध एक दूसरी अपील तिथि के 90 दिनों के अंदर की जाएगी, जब निर्णय किया गया है अथवा इसे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है:

1. बशर्ते केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इसके प्रति संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण हैं.

19 (4): यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा कि मामला हो, दिया जाता है और इसके विरुद्ध तीसरे पक्ष की सूचना से सम्बंधित एक अपील की जाती है तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनने का एक पर्याप्त अवसर देगा.

19 (7): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, मानने के लिए बाध्य होगा.

19 (8): अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित अधिकार होगा.

(क) लोक प्राधिकरण द्वारा ये क़दम उठाए जाएं, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ पालन को सुनिश्चित करें, जिसमें शामिल हैं:

सूचना तक पहुंच प्रदान करने द्वारा, एक विशेष रूप में, यदि ऐसा अनुरोध किया गया है;

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो;

सूचना की कुछ श्रेणियों या किसी विशिष्ट सूचना के प्रकाशन द्वारा;

अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और विनाश के संदर्भ में प्रथाओं में अनिवार्य बदलावों द्वारा;

अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान बढ़ाकर;

धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करना;

(ख) लोक प्राधिकरण द्वारा किसी क्षति या अन्य उठाई गई हानि के लिए शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देना;

(ग) अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों को अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन अस्वीकार करना.

19 (9): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील के अधिकार सहित अपने निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को देगा.

19 (10): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उक्त प्रक्रिया में निर्धारित विधि द्वारा अपील का निर्णय देगा.

आरटीआई आवेदन का प्रारूप:

कूड़ेदान की सफाई नहीं होना

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : *सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.*

महोदय,
कूड़ेदान का पता:
उपर्युक्त कूड़ेदान से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उस डिपो का पता बताएं, जहां से लोडर तथा ट्रक इस कूड़ेदान के लिए भेजे जाते हैं?

2. उन लोडर तथा ट्रक का नंबर बताएं, जो इस कूड़ेदान से कूड़ा उठाने के लिए नियुक्त हैं?

3. दिनांक ..... से ..... के बीच डिपो के बीट रजिस्टर में दर्ज इन गाड़ियों के डिपो छोड़ने तथा डिपो में वापस आने के समय का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं?

4. उन सभी कूड़ेदानों का पता बताएं, जहां का कूड़ा उपर्युक्त समय के दौरान इन गाड़ियों ने उठाया?

5. इस दौरान प्रतिदिन इन गाड़ियों द्वारा लगाए गए चक्करों का विवरण दें?

6. इस दौरान प्रत्येक चक्कर में इन गाड़ियों द्वारा उठाए गए कूड़े के वजन का विवरण दें?

7. उपर्युक्त कूड़ादान पिछले ..... दिनों से साफ नहीं किया गया है. इस दौरान इस क्षेत्र के सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा भेजी गई प्रतिदिन के बैलेंस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं?

8. क्या उपर्युक्त बैलेंस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है. इस दौरान कूड़ेदान का कूड़ा नहीं उठाया गया? यदि नहीं, तो सम्बंधित क्षेत्र के सेनेटरी इंस्पेक्टर ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

बैंक ऑफ बड़ौदा का 110वां स्थापना दिवस

वसुंधरा इंक्लेव शाखा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी स्थापना के 109 साल पूरे कर लिए. इस दिन को बैंक ऑफ बड़ौदा की वसुंधरा इंक्लेव शाखा ने एक अलग तरीके से सार्थक संदेश देते हुए सेलिब्रेट किया. इस अवसर पर 18 जुलाई को बैंक ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया. इस विशेष अवसर पर चौथी दुनिया से बातचीत में बीओबी के इंद्रप्रस्थ जोन के उप-महाप्रबंधक कुलभूषण डाबरा ने कहा कि 'आज से 109 साल पहले जो बैंक एक छोटे से पौधे के रूप में शुरू हुआ था, आज उसने एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है. भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा की साढ़े 5 हजार से अधिक शाखाओं के अलावा विश्व के 26 अन्य देशों में इसकी 110 शाखाएं हैं. यही कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कहा जाता है कि इसका सूरज कभी अस्त नहीं होता. इस अवसर पर वसुंधरा इंक्लेव शाखा के अतिरिक्त पांच अन्य जगहों पर भी रक्तदान शिविर और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. साथ ही मैक्स के सहयोग से चार फ्री हेल्थ चेकअप कैम्प भी लगाए गए हैं और कस्टमर मीट का भी आयोजन किया गया है. इस अवसर पर हमारे कस्टमर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए है, आपकी ही वजह से है और हम हमेशा ही आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे.' स्थापना दिवस के इस अवसर पर वसुंधरा इंक्लेव शाखा द्वारा नोएडा रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में लगभग दो दर्जन लोगों ने रक्तदान किया. रक्तदान कर रहे दिनेश मंडल ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर वसुंधरा इंक्लेव बीओबी शाखा द्वारा रक्तदान का आयोजन करना एक प्रशंसनीय कार्य है. ■

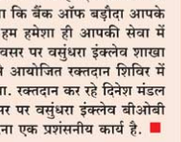

जयंती विशेष

पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राजनीति का राजर्षि

जयंती- 1 अगस्त 1882
पुण्यतिथि- 1 जुलाई 1962

राजभाषा चयन को लेकर 1949 में हो रही संविधान सभा की बैठक में महात्मा गांधी, पं. नेहरू और डॉ राजेन्द्र प्रसाद समेत अनेक नेता हिन्दुस्तानी के पक्षधर थे, लेकिन हिंदी के लिए जो लोग मुखरता से आवाज उठा रहे थे, पुरुषोत्तम दास टंडन उनमें प्रमुख थे. 11, 12, 13 और 14 दिसम्बर 1949 को जब इस मुद्दे पर गरमागरम बहस हुई और फिर हिंदी और हिन्दुस्तानी को लेकर कांग्रेस में मतदान हुआ, तो हिन्दी को 62 और हिन्दुस्तानी को 32 मत मिले. अंतत: हिन्दी राष्ट्रभाषा और देवनागरी राजलिपि घोषित हुई.

चौथी दुनिया ब्यूरो

आज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसका प्रमुख योगदान जाता है, पुरुषोतम दास टंडन को. उन्होंने न सिर्फ राजभाषा के रूप में हिंदी को हिंदुस्तान से जोड़ने में अहम भूमिका अदा की, बल्कि वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे. पुरुषोतम दास टंडन को आजाद भारत के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर और नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा जाता है. एक ऋषि के समान अपने सियासी व सार्वजनिक सत्कार्य में लगे रहने के कारण उन्हें आम जनमानस में राजर्षि के नाम से भी जाना जाता है.

पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था. इलाहाबाद के ही सिटी एंग्लो वर्नाक्युलर विद्यालय में ही उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक पाई. 1897 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की. उसी साल 15 साल की अल्पायु में ही उनकी शादी मुरादाबाद निवासी नरोत्तमदास खन्ना की पुत्री चन्द्रमुखी देवी के साथ हो गया. 1899 में उन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसी साल वे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किए और कांग्रेस के स्वयंसेवक बने. सन 1900 में वे एक कन्या के पिता बने. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्योर सेण्ट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया. इसी के साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय हो गए थे. क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण ही उन्हें 1901 में कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया. इसी बीच 1903 में उनके पिता का निधन हो गया. इन सब चुनौतियों को पार करते हुए 1904 में उन्होंने स्नातक कर लिया. पुरुषोत्तम दास टंडन के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ 1905 में, जब उन्होंने बंगभंग आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया. इससे प्रभावित होकर उन्होंने स्वदेशी का व्रत धारण किया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में चीनी खाना छोड़ दिया. 1906 में उन्हें इलाहाबाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया. इन सब के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन अपने साहित्यिक जीवन में भी आगे बढ़ रहे थे. यही समय था जब उनकी प्रसिद्ध रचना बन्दर सभा महाकाव्य 'हिन्दी प्रदीप' में प्रकाशित हुई. 1907 में उन्होंने इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त और इसके बाद एल.एल.बी की उपाधि प्राप्त करने के बाद वकालत प्रारंभ की. पढ़ाई जारी रखते हुए वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस समय के नामी वकील तेज बहादुर सप्रू के जूनियर बन गए.

पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस पार्टी की उस समिति में शामिल थे, जिसका गठन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के अध्ययन के लिए किया गया था. इसके बाद जब असहयोग आंदोलन प्रारम्भ हुआ, तो गांधी जी के आह्वान पर वे 1920 में वकालत के अपने फलते-फूलते पेशे को छोड़कर इसमें शामिल हो गए. सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में 1930 में वे बस्ती से गिरफ्तार हुए और उन्हें कारावास का दण्ड मिला. 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के वापस लौटने से पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें जवाहरलाल नेहरू के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे. 1934 में वे बिहार की प्रादेशिक किसान सभा के अध्यक्ष बने. इसके बाद 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया. 1937 में जब धारा सभाओं के चुनाव हुए, तो ग्यारह प्रान्तों में से सात में कांग्रेस को बहुमत मिला. उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली और इसका पूरा श्रेय टण्डन जी दिया गया. वे स्वयं प्रयाग नगर से विधानसभा से निर्विरोध विजयी हुए. कुछ समय बाद जब मंत्रिमंडल बना, तो वे सर्वसम्मती से धारासभा के अध्यक्ष (स्पीकर) चुने गए. स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभागिता के कारण 1940 में अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया और वे एक वर्ष तक जेल में रहे. 1942 में जब वे जेल से छूटे, तो उन्हें लगा कि भारतीय समाज में निराशा छायी हुई है, सभी हताश पड़े हुए हैं. समाज में नई चेतना का संचार करने के लिए उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधि असेम्बली नामक संस्था की स्थापना की. हालांकि जब प्रान्तीय कमेटियां बनीं तब प्रतिनिधि असेम्बली को भंग कर दिया गया. अगस्त 1942 को टंडन जी फिर से इलाहाबाद में गिरफ्तार हुए और 1944 में जेल से मुक्त हुए. पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में वे सात बार जेल गए. टण्डन जी इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष रहे और अपने कार्यकाल के दौरान अनेक साहसी तथा ऐतिहासिक कार्य किए.

पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस पार्टी की उस समिति में शामिल थे, जिसका गठन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के अध्ययन के लिए किया गया था. इसके बाद जब असहयोग आंदोलन प्रारम्भ हुआ, तो गांधी जी के आह्वान पर वे 1920 में वकालत के अपने फलते-फूलते पेशे को छोड़कर इसमें शामिल हो गए. सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में 1930 में वे बस्ती से गिरफ्तार हुए और उन्हें कारावास का दण्ड मिला.

टंडन जी 1946 में भारत की संविधान सभा में भी चुने गए. 12 जून 1947 को जब कांग्रेस कार्य समिति ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया. 14 जून को जब इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया, तब इसका विरोध करने वालों में से एक पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे. उनका कहना था कि विभाजन स्वीकार करने का मतलब होगा अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के सामने झुकना. आजादी के बाद सन 1948 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभि सितारमैय्या के विरुद्ध चुनाव लड़ा पर हार गए. सन 1950 में उन्होंने आचार्य जे.बी. कृपलानी को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद हासिल किया पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के साथ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया. टंडन जी का हिंदी भाषा से विशेष लगाव था. 17 फ़रवरी 1951 को मुजफ्फरनगर सुहृद संघ के 17 वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा भी था कि हिंदी के पक्ष को सबल करने के उद्देश्य से ही मैंने कांग्रेस जैसी संस्था में प्रवेश किया, क्योंकि मेरे हृदय पर हिंदी का ही प्रभाव सबसे अधिक था और मैंने उसे ही अपने जीवन का सबसे महान व्रत बनाया.

राजभाषा चयन को लेकर 1949 में हो रही संविधान सभा की बैठक में महात्मा गांधी, पं. नेहरू और डॉ राजेन्द्र प्रसाद समेत अनेक नेता हिन्दुस्तानी के पक्षधर थे, लेकिन हिंदी के लिए जो लोग मुखरता से आवाज उठा रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन उनमें प्रमुख थे. 11, 12, 13 और 14 दिसम्बर 1949 को जब इस मुद्दे पर गरमागरम बहस हुई और फिर हिंदी और हिन्दुस्तानी को लेकर कांग्रेस में मतदान हुआ, तो हिन्दी को 62 और हिन्दुस्तानी को 32 मत मिले. अंतत: हिन्दी राष्ट्रभाषा और वन्देमातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत कराने के लिए टण्डन जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक और अभियान चलाया था. 1952 में टंडन जी लोकसभा के लिए चुने गए और फिर 1957 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए. इसके बाद ख़राब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने सक्रीय सार्वजानिक जीवन से संन्यास ले लिया. सन 1961 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया और 1 जुलाई 1962 को ये राजनीतिक व सामाजिक योद्धा सदा के लिए सो गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ब्यूरो

बरसात में कैसे पाएं साफ़ पानी

बरसात के मौसम में पीने के पानी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है. इस मौसम में गंदे पानी और उससे बनने वाले खाद्य पदार्थों से भी कई बिमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे- दस्त, हैजा, टाइफाइड और फूडप्वाइजनिंग आदि. इसलिए खासकर बरसात में ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि आप जो पानी पी रहे हैं, वो पूर्णत: साफ व पीने योग्य पानी है. अगर आंकड़ों की मानें, तो पीने के पानी में 2,100 विषैले तत्व मौजूद होते हैं. ऐसे में बेहतरी इसी में है कि पानी का इस्तेमाल करने से पहले इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाए. हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर के पानी को पीने लायक बना सकते हैं:

पानी को उबालना : वैसे तो पानी को साफ और पीने योग्य बनाने के अब ढेरों तरीके मौजूद हैं, लेकिन पानी को साफ करने के लिए इसे उबालने का सबसे पुराना तरीका अब भी कारगर है. दुनिया भर में इस परंपरागत तरीके को लाखों लोग अपनाते हैं. पानी को पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाने के लिए कम-से-कम उसे 20 मिनट उबालना चाहिए और उसे ऐसे साफ कंटेनर में रखना चाहिए, जिसका मुंह संकरा हो ताकि उसमें किसी प्रकार की गंदगी न जाए.

कैंडल वाटर फिल्टर : पानी को साफ करने के लिए दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, कैंडल वाटर फिल्टर. हालांकि इसमें समय-समय पर कैंडल बदलने की जरूरत होती है, ताकि पानी बेहतर तरीके से साफ हो सके.

मल्टी स्टेज प्यूरीफिकेशन: मल्टी स्टेज प्यूरीफिकेशन को बिना बिजली के ही उपयोग में लाया जा सकता है और इसकी लागत भी कम होती है. देखने में यह पारंपरिक फिल्टर की तरह होता है. इसमें पानी कई चरणों में साफ होता है. पहले प्री-फिल्टर प्यूरीफिकेशन होता है, उसके बाद एक्टीवेटेड कॉर्बन प्यूरीफिकेशन किया जाता है, फिर पानी से हानिकारक बैक्टीरिया खत्म किए जाते हैं और सबसे अंत में पानी की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिहाज से उसका स्वाद बेहतर किया जाता है.

क्लोरीनेशन: क्लोरीनेशन पानी साफ करने की बहुत पुरानी प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया से पानी शुद्ध होने के साथ उसके रंग और सुगंध में भी परिवर्तन आ जाता है. विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आ चुके बदलावों के बावजूद क्लोरीन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है. पानी ो हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने के लिए नगरपालिका, अस्पताल, रेलवे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है.

हैलोजन टैबलेट : आकस्मिक परिस्थितियों में पानी साफ करने के लिए हैलोजन टेबलेट उपयोगी होती है. पानी में इसे कितनी मात्रा में डाला जाए, यह पानी की मात्रा और हैलोजन टैबलेट के ब्रांड के ऊपर निर्भर करता है. ये गोलियां पानी में पूरी तरह घुलनशील होती है.

आरओ सिस्टम : पानी को साफ करने की एक नई तकनीक पिछले कुछ सालों से बाजार में उपलब्ध है. इस तकनीक का पूरा नाम है- रिवर्स आसमोसिस प्रोसेस, जिसे हम आरओ के नाम से जानते हैं. इस तकनीक में पानी को बेहद तेज दबाव के साथ साफ किया जाता है. आरओ सिस्टम द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम हो जाती है. यह पेयजल को साफ करने का उच्चस्तरीय तरीका है. प्रभावशाली आरओ तकनीक शुरुआती चरण में ही पानी की तमाम अशुद्धियों को दूर कर देता है. घरों में प्रयोग किए जाने वाला आरओ सिस्टम 220 से 240 पीपीएम युक्त पानी को स्वच्छ कर 25 पीपीएम तक ले आता है. आरओ सिस्टम पानी को पांच चरणों में साफ करता है और उसे गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है. आरओ प्रक्रिया में पानी को कई महीन झिल्लियों से गुजारा जाता है और इसके बाद पानी में मौजूद सभी बैक्टीरिया व रसायन बाहर निकल जाते हैं. ये सारी महीन झिल्लियां बिजली से संचालित होती हैं और इनसे गुजरने के बाद गंदे से गंदा पानी भी पीने योग्य बन जाता है.

यूवी रेडिएशन सिस्टम : पानी साफ करने के लिए यूवी रेडिएशन विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है. यूवी रेडिएशन सिस्टम से पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं. साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिससे पानी मनुष्य के इस्तेमाल योग्य हो जाता है. इस प्रक्रिया में पानी में न कुछ मिलाया जाता है और न ही किसी खनिज को हटाया जाता है. यूवी प्यूरीफायर्स तीन-चार प्यूरीफिकेशन चरणों में आते हैं, जिनमें सेडीमेंट फिल्टर यानी प्री फिल्टर प्रक्रिया और सक्रिय कार्बन कार्टिरेज प्रमुख हैं. यह प्यूरीफायर वहां उपयोगी होता है, जहां लोग नगरपालिका का पानी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इस तकनीक का कमजोर पक्ष यह है कि यह तकनीक घुलनशील सॉलिड के स्तर में बदलाव कर पाने में सक्षम नहीं होती है.

पानी साफ करने के प्रत्येक तकनीक के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, ऐसे में जरूरी है कि पानी के स्रोत और गुणवत्ता आदि के आधार पर ही उसे साफ करने की तकनीक का चयन किया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

शिवाजी महाराज के ख़ास बने अजय देवगन

बॉलीवुड के टॉप 5 स्टार में अजय देवगन का नाम शान से लिया जाता है. इसके अलावा अजय को एक्शन फिल्मों के लिए भी जाना जाता है. फिल्म शिवाय में बेटी के पिता के रोल से सबका दिल जीतने वाले अजय फिल्म बादशाहो के बाद एक बार फिर एक्शन करते नजर आएंगे. अजय देवगन की ऐतिहासिक फिल्म तानाजी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है. अजय ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर इस फिल्म के फर्स्ट लुक को पोस्ट किया है. फिल्म का नाम तानाजी- द अनसंग वरियर है, जिसमें अजय छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार तानाजी मालुसरे की भूमिका में नजर आएंगे. अजय काफी समय से ट्वीट के जरिए फिल्म की जानकारी दे रहे थे. अजय ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि वह लड़ा अपने लोग, अपनी मिट्टी और अपने किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए. भारतीय इतिहास का एक जाबांज योद्धा सूबेदार तानाजी मालुसरे.

अगस्त माह में आने वाली फिल्में

साल 2017 में बीते 6 महीनों में कई फिल्में आईं और गईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली-2 की धमाकेदार एंट्री ने धूम मचा दी. अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने भी कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी फिल्म किस तारीख को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है.

नोटः फिल्म की डेट रिलीज कभी भी बदल सकती है.

04 अगस्त 2017

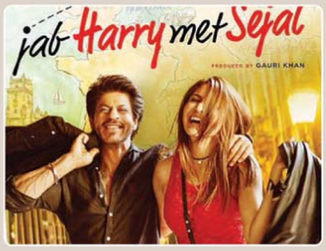

जब हैरी मेट सेजल

कलाकार : शाहरूख खान और अनुष्का शर्मा
डायरेक्टर : इम्तियाज़ अली

11 अगस्त 2017

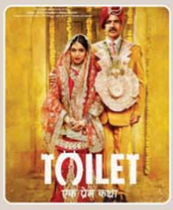

टॉयलेट एक प्रेम कथा

कलाकार
अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और अनुपम खेर

डायरेक्टर
श्री नारायण सिंह

18 अगस्त 2017

बरेली की बर्फी

कलाकार
आयुष्मान खुराना, कृति सेनन और राजकुमार राव

डायरेक्टर
अश्विनी अय्यर तिवारी

हसीना पारकर

कलाकार
श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर

डायरेक्टर
अपूर्वा लाखिया

पार्टिशनः1947

कलाकार
हुमा कुरेशी, मनीष दयाल, ओम पुरी और गिलयन एडरसन

डायरेक्टर
गुरिंदर चड्ढा

25 अगस्त 2017

ए जेंटलमैन

कलाकार
सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुनील शेट्टी और जैकलीन

डायरेक्टर
राज निदिमोरू, कृष्णा डीके

बाबूमोशाय बंदूकबाज़

कलाकार
नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दिव्या दत्ता, बिदिता बाग

डायरेक्टर
कुशन नंदी

इन अभिनेत्रियों पर भरोसा करना यानि करोड़ों का नुक़सान

नाम बड़े और दर्शन छोटे

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को लेकर बॉक्स ऑफिस पर दांव खेलना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए आसान नहीं होता, फिर चाहे वे टॉप लेवल की अभिनेत्रियां ही क्यों ना हों? फिल्म की कहानी में ही अगर दम न हो, तो फिर ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी मांगते नजर आती हैं. ऐश्वर्या-विद्या से लेकर कैटरीना-सोनाक्षी तक इन सभी की फिल्मों का बुरा हाल हो चुका है. जी हां, जब भी कोई टॉप स्टार अभिनेत्री अपने दम पर बतौर लीड रोल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर कदम रखती है, तो दर्शक उसे पूरी तरह से नकार देते हैं. फिल्म का हिट होना तो दूर, यह फिल्म का बजट भी निकाल ले, वही बहुत है.

बॉक्स ऑफिस पर अभिनेत्री प्रधान बहुत कम ही फिल्में हिट होती हैं. अभिनेताओं के बिना इन अभिनेत्रियों का बॉक्स ऑफिस पर टिक पाना मुश्किल होता है. अगर इन अभिनेत्रियों की फिल्में हिट भी हो जाएं तो बॉक्स ऑफिस पर वैसे करोड़ों रुपयों की बारिश नहीं होती जितनी टॉप एक्टर की फ्लॉप फिल्में भी कमा लेती हैं. हाल में कैटरीना, सोनाक्षी, विद्या बालन, कंगना, ऐश्वर्या राय बच्चन आदि अभिनेत्रियां इन लिस्ट में शामिल हैं, जो अपने दम पर फिल्म का बजट तक नहीं निकाल पाती हैं. हालांकि बहुत कम ही ऐसी फिल्में होंगी, जिसमें अपने दम पर इन अभिनेत्रियों ने धमाल मचाया हो. आइए जानते हैं बॉलीवुड की उन टॉप अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई बार प्रोड्यूसरों का दिवाला निकाला है.

> बॉक्स ऑफिस पर अभिनेत्री प्रधान बहुत कम ही ऐसी फिल्में हैं, जिसे वे अपने दम पर हिट करवा सकें. वरना टॉप अभिनेताओं के बिना इनका बॉक्स ऑफिस पर टिक पाना मुश्किल होता है. ऐसे में अगर इन अभिनेत्रियों की फिल्म हिट भी हो जाए, तो बॉक्स ऑफिस पर वैसे करोड़ों की बारिश नहीं होती जैसी टॉप एक्टर की फ्लॉप फिल्में भी कमा लेती हैं. हाल में कैटरीना, सोनाक्षी, विद्या बालन, कंगना, ऐश्वर्या राय बच्चन आदि अभिनेत्रियां इस लिस्ट में शामिल हैं, जो अपने दम पर फिल्म का बजट तक निकाल पाने में असफल रही हैं.

सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी बॉलीवुड में दबंग गर्ल के नाम से जानी जाती हैं. हो भी क्यों ना, आखिर सोनाक्षी की एंट्री बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के साथ जो हुई थी. इस फिल्म के बाद सोनाक्षी रातोंरात स्टार बन गई थी. लेकिन इसके बाद उनकी कई फिल्में ऐसी रहीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, फिर चाहे वह नामी अभिनेताओं के साथ हो या फिर बतौर मुख्य अभिनेत्री. उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिटती चली गईं. सोनाक्षी की पिछली फिल्में फोर्स-2, अकीरा और नूर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं. सोनाक्षी ने इससे पहले अक्षय कुमार के साथ फिल्म हॉलीडे में काम किया था. फिल्म तो हिट रही, पर सोनाक्षी को इस फिल्म में खराब अभिनय के लिए कई लोगों ने कोसा और कहा कि शायद सोनाक्षी अब एक्टिंग करना भूल गई हैं.

निर्देशक और प्रोड्यूसर को शायद अब यह बात समझ में आ गई होगी कि सोनाक्षी को लीड रोल में लेकर फिल्म बनाना घाटे का सौदा है. अब उनकी सारी उम्मीदें आने वाली फिल्म इत्तेफाक से जुड़ी हैं.

कैटरीना कैफ

2003 में कैटरीना ने बॉलीवुड की थर्ड क्लास फिल्म बूम से शुरुआत की थी. फिल्म तो सुपरफ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने हॉट सीन देकर दर्शकों के दिलों में आग लगा दी थी. इसके बाद कैट लगभग 2 साल तक फिल्म इंड्रस्टी से गायब रहीं. 2005 में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने कैट की शानदार वापसी फिल्म *मैंने प्यार क्यों किया* से करवाई. इसके बाद तो कैटरीना की फिल्मी लाइन पटरी पर आ गई और देखते देखते उनकी कई फिल्में हिट की श्रेणी में आ गई. उन्होंने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े स्टार अभिनेताओं के साथ काम किया है.

इसके कोई शक नहीं कि कैट आज के दौर की टॉप अभिनेत्री हैं, लेकिन जब निर्देशक और प्रोड्यूसर्स ने कैट को दूसरे अभिनेताओं के साथ काम करने का रिस्क लिया तो उनकी फिल्में पिटने लगीं. कैटरीना की पिछले दो साल में 2 फिल्में (फैंटम 2015 और फितूर 2016) फ्लॉप हो चुकी है और इस साल उनकी तीसरी फिल्म जग्गा जासूस भी पिटने के कगार पर है. नतीजा यह हो रहा है कि पिछले 3 साल में दूसरी न्यू एक्ट्रेस उनसे आगे निकलती जा रही है. कैटरीना को टाईगर जिंदा से काफी उम्मीदें हैं.

कंगना रनौत

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर जगह बनाई है. इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं. अपने करियर में उन्होंने कई अवॉर्ड जीते हैं, जिनमें दो नेशनल अवॉर्ड भी शामिल हैं. यह दोनों अवॉर्ड उन्हें फिल्म क्वीन और तनु वेड्स मनू-2 के लिए मिले हैं. इन फिल्मों से कंगना ने यह साबित कर दिया था कि फिल्म में अगर कोई बड़ा अभिनेता ना भी हो, तो वे फिल्म को हिट कराने का फॉर्मूला जानती हैं. इन फिल्मों के बाद प्रोड्यूसर्स को भी लगा कि कंगना पर दांव खेला जा सकता है. इसी को देखते हुए उन्होंने कंगना को लेकर फिल्म रज्जो, रिवॉल्वर रानी, कट्टी-बट्टी और रंगून जैसी फिल्मों का निर्माण किया. इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा और सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं. अब निर्देशक भी समझ चुके है कि कंगना की हर फिल्म हिट हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

ऐश्वर्या राय बच्चन

एक समय था जब बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय टॉप पर थीं और फिल्म निर्देशक उनको अपनी फिल्मों में लेने के लिए भी तरसते थे. ऐश ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक बार गाड़ी पटरी से उतरी, तो फिर ट्रैक पर लाना मुश्किल होता है. यही हाल ऐश का भी हुआ. ऐश ने बीच में कई गलत फिल्में चुन लीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनका स्टारडम अर्श से फर्श पर आ गया. बहुत कोशिशों के बाद ऐश ने 2015 में फिल्म जज्बा से कमबैक किया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला. उसके बाद 2016 में सरबजीत से उन्होंने दोबारा कमबैक की कोशिश की लेकिन यहां भी कोई फायदा नहीं हुआ. ये दोनों फिल्में बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं. हालांकि 2016 में ऐश की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल भी रिलीज हुई, जो औसत दर्ज की रही. लेकिन इसे ऐश का कम बैक नहीं कहा जा सकता. अब हाल यह है कि ऐश को लेकर निर्माता-निर्देशकों में कोई ख़ास लगाव नहीं देखा जाता.

विद्या बालन

यूं तो विद्या बालन के अभिनय का कोई जवाब नहीं. अगर फिल्म हिट होती है और उसमें कोई नामी अभिनेता हो, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि विद्या को साइड कर दिया गया हो. अपनी बेहतरीन अदाकारी और अभिनय से विद्या बालन ने करोड़ों दिलों पर राज किया है और कई बड़े अवॉर्ड भी अपनी झोली में डाले हैं. लेकिन लगता है विद्या का भी समय निकल चुका है. विद्या बालन की फिल्मों में उनके अभिनय की तारीफ जरूर होती है, लेकिन फिल्मों को हिट करवाना अब उनके लिए भी आसान नहीं रहा. उनकी पिछली फिल्मों पर अगर नज़र डालें तो यह साफ हो जाता है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अब मुनाफा नहीं, बल्कि नुकसान में ज्यादा रहती हैं. फिल्म घनचक्कर, बॉबी जासूस, तीन, एक अलबेला, कहानी-2 और बेगम जान जैसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल रहा.■

feedback@chauthiduniya.com